चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 28 नवंबर–04 दिसंबर 2011 | मूल्य 5 रुपये

मायावती का मास्टर स्ट्रोक

पेज-3

यहां भी है माइनिंग का महाघोटाला

पेज-5

चुनौतियां और अवसर

पेज-6

साई की महिमा

पेज-12

सरकार और पार्टी में दरार

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

देश की सरकार इस समय दो धुरियों में बंटी हुई है. एक तरफ़ सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी है तो दूसरी तरफ़ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके कुछ ख़ास मंत्री हैं. प्रधानमंत्री बिना कुछ बोले सोनिया गांधी की सभी सलाहों को दरकिनार कर, उनका क़द छोटा करने की जुगत में हैं, तो सोनिया गांधी सरकार पर देश की सबसे शक्तिशाली संस्था राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सुझावों को लागू कराने का दबाव बनाने में लगी हैं. मगर मनमोहन यहां भी दांव खेल रहे हैं. सोनिया गांधी के सलाहकारों द्वारा तैयार किए गए खाद्य सुरक्षा विधेयक के जिस मसौदे को मनमोहन ने अव्यवहारिक बताकर साल भर पहले दरकिनार कर दिया था. अब उसी को वह आनन–फ़ानन में अमली जामा पहनाने में लगे हैं. वजह हैं, उनके लाडले पी. चिदंबरम, जिन्हें मनमोहन इस विधेयक के बहाने संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षियों के वार से बचाना चाहते हैं.

रूबी अरुण

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क़रीब से जानने वाले इस बात से ख़ूब वाक़िफ़ हैं कि वह जो बात कहते हैं, मायने उसके नहीं होते, बल्कि वह जो नहीं कहते हैं मतलब उसका होता है. पिछले सात सालों के साथ के दरम्यान अगर इस बात से सबसे ज़्यादा किसी का वास्ता पड़ा है तो वह हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी. हालांकि मनमोहन सिंह ने कभी भी अपनी नेता की शान में ज़ुबानी तौर पर गुस्ताख़ी नहीं की. मगर पिछले दो सालों में मनमोहन सिंह और उनके सलाहकारों ने सोनिया गांधी और उनके सलाहकारों के सभी मशविरों को सिरे से दरकिनार कर यह जताने में गुरेज़ नहीं किया कि वह होंगी पार्टी की हाई कमान, पर सरकार तो हम ही चलाते हैं. लिहाज़ा सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की सभी सलाहों को प्रधानमंत्री कार्यालय बग़ैर किसी विमर्श के ख़ारिज कर देता है. जब परिषद् के सदस्य वजह पूछते हैं तो प्रधानमंत्री के सलाहकार, सोनिया गांधी के सलाहकारों के मशविरों को अव्यवहारिक क़रार देते हैं.

ज़ाहिर है कि प्रधानमंत्री की सलाहकार मंडली, सोनिया गांधी नीत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् पर हावी होती जा रही है, और कभी बेहद शक्तिशाली रही इस संस्था का वजूद सिमटता जा रहा है. मनमोहन सिंह ने बड़े मुद्दों पर सोनिया की अनदेखी नहीं की है, मसलन मंत्रिमंडल का विस्तार. लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिन पर वह मना कर देते हैं, विधेयकों के मसौदे उनमें से एक हैं. ज़्यादातर मामलों में सोनिया की सिफ़ारिशें सुनी तो जाती हैं, लेकिन उन पर पूरी तरह अमल नहीं किया जाता. एनएसी ने घरेलू हिंसा विधेयक, सूचना का अधिकार और यहां तक कि मनरेगा में कमियों पर ख़ूब शोर मचाया था. दूसरे कई मुद्दों पर भी एनएसी की सरकार से ठनी है. ऐसे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भूल जाते हैं कि ख़ुद को मज़बूत प्रधानमंत्री साबित करने की जुगत में और सोनिया गांधी की कठपुतली के तमग़े से ख़ुद को बचाने की फ़िराक़ में वह देश के लोगों का कितना बड़ा अहित कर जाते हैं.

ऐसे तमाम मसले हैं, जिनमें सोनिया गांधी की सलाहों की खुलकर अनदेखी की गई है और यह सिलसिला जारी है. मसलन, एनएसी की इस आपत्ति के बावजूद कि पोस्को की परियोजना वनाधिकार क़ानून का उल्लंघन करती है, हाल में उसे हरी झंडी दिखा दी गई. एनएसी के सदस्य एनओसी सक्सेना ने तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को 3 अगस्त, 2010 को लिखकर बताया था कि परियोजना किन–किन नियमों का उल्लंघन करती है. जयराम रमेश ने पहले तो इस परियोजना पर आपत्ति जताई, लेकिन फिर उनके मंत्रालय ने परियोजना को आगे बढ़ने का रास्ता मुहैया करा दिया. पोस्को का विरोध करने वालों का आरोप है कि पोस्को परियोजना को पीएमओ के दबाव में मंज़ूरी दी गई, जबकि सोनिया इस परियोजना के लिए सहमत नहीं थीं. सोनिया ने प्रधानमंत्री से साफ़ तौर पर कहा था कि पोस्को परियोजना वनाधिकार क़ानून का उल्लंघन है, इसलिए इसे रोक देना चाहिए. ख़ासकर वैसी स्थिति में जब ओडीसा का पुनर्वास पैकेज भी कमज़ोर है. इस वजह से वहां के आदिवासियों के हितों की सुरक्षा पुख्ता तौर पर नहीं की जा सकती. लेकिन मनमोहन ने पोस्को को सशर्त मंज़ूरी देते हुए कहा कि ओडीसा को वनाधिकार क़ानून से तालमेल बिठाकर चलना चाहिए.

भूमि अधिग्रहण बिल जैसे बेहद महत्वपूर्ण और संजीदा मसले पर भी प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों ने सोनिया की एक न सुनी. सोनिया का कहना है कि जहां भी भूमि अधिग्रहण की वजह से एक साथ अगर चार सौ परिवार बेदख़ल होते हैं, तो सरकार वहां की सौ फ़ीसदी ज़मीन अधिग्रहित करे और किसानों के लिए ज़मीन लेने का काम निजी कंपनियां करें. साथ ही साथ राहत और पुनर्वास विधेयक को भूमि अधिग्रहण विधेयक के साथ जोड़ा जाए. पर प्रधानमंत्री इस पर भी आपत्ति जताते हुए सोनिया गांधी को ये जवाब देते हैं की सरकार की सहयोगी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस क़दम से नाराज़ हो सकती है क्योंकि ममता बनर्जी भूमि अधिग्रहण में सरकारी भूमिका की पक्षधर नहीं हैं. मनमोहन सिंह का मानना है कि पुनर्वास और पुनः बसावट विधेयक को भूमि अधिग्रहण विधेयक के साथ जोड़ने की एनएसी की सिफ़ारिश से समस्या खड़ी हो सकती है. मनमोहन सिंह यह दलील भी देते हैं कि चूंकि राहत–पुनर्वास विधेयक प्राकृतिक आपदाओं से बेदख़ल लोगों के लिए है, इसलिए इसे भूमि अधिग्रहण विधेयक के साथ जोड़ना ग़लत होगा. इससे मौजूदा हालत में सियासी जगत और औद्योगिक वर्ग की तरफ़ से आ रही आपत्तियों के कारण भूमि अधिग्रहण बिल के संसद तक पहुंचने की राह फ़िलहाल मुश्किल दिख रही है. नतीजतन, यह बिल सरकार के उन विधेयकों की सूची से ग़ायब है, जो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने हैं.

एनएसी के सदस्य ज्यां द्रेज कहते हैं कि एनएसी की कई सिफ़ारिशें या तो नज़रअंदाज़ कर दी जाती हैं या नामंज़ूर कर दी जाती हैं. अगर कभी मानी भी जाती हैं तो आंशिक तौर पर.

एक और मिसाल, मनमोहन सिंह के प्रिय परमाणु विधेयक को लोकसभा से पास कराने के लिए सोनिया ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया था. सोनिया ने सरकार के गिरने तक का ख़तरा मोल लिया था, लेकिन सोनिया गांधी का पसंदीदा महिला आरक्षण विधेयक, एनएसी और सोनिया की मिन्नतों के बावजूद अभी भी अधर में लटका पड़ा है. सोनिया, संसद में महिलाओं की 33 फ़ीसदी से कम की नुमाइंदगी से ख़ुश नहीं हैं. सोनिया गांधी जब भी मनमोहन सिंह से इस बारे में ज़िक्र करती हैं तो उन्हें जवाब मिलता है कि सदन में सरकार के पास इस विधेयक के समर्थन में पर्याप्त संख्या बल नहीं है. मगर हक़ीक़त सब जानते हैं कि कभी भी सरकार की तरफ़ से इस विधेयक के समर्थन में सर्वानुमति बनाने की कोशिश नहीं की गई.

कुछ ऐसी ही बदहाली सोनिया की एक अन्य ख्वाहिश भारत–अरब दोस्ती की भी है. अरब देशों के साथ गांधी परिवार के रिश्तों का ख़ुशनुमा इतिहास है. सुदूर उत्तर और अरब देशों के साथ कांग्रेस के परंपरागत वफ़ादारी भरे संबंध रहे हैं, जिसका फ़ायदा भी समय–समय पर कांग्रेस को मिलता रहा है. सोनिया चाहती हैं कि यह रिश्ता और भी मज़बूत हो. इसके लिए कूटनीतिक क़दम उठाए जाएं, पर यह मसला मनमोहन सिंह के एजेंडे में है ही नहीं. हालांकि सोनिया ने पाकिस्तान के साथ शांति बहाली के एक सूत्रीय एजेंडे में खुलकर उनका साथ दिया. यहां तक कि जब प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार की ग़लती की वजह से शर्म–अल–शेख़ के मुद्दे पर सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, और मनमोहन की अपने ही सहयोगियों के बीच आलोचना शुरू हो गई थी तब भी सोनिया ने सबको नसीहत देकर चुप करा दिया था.

सोनिया को मनमोहन के सामने कश्मीरी विस्थापितों को टैक्स में छूट देने के मसले पर भी मुंह की खानी पड़ी है. सोनिया ने कश्मीरी विस्थापितों को टैक्स में छूट देने की मांग का समर्थन करते हुए सरकार को कई बार पत्र लिखा है. हर बार जवाब में मनमोहन सिंह की पुरानी चिट्ठी नई तारीख़ के साथ सोनिया के पास चली आती है, जिसमें लिखा होता है कि देश के आयकर नियमों में व्यक्तियों के समूह को छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है.

यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी यूआईडी भी प्रधानमंत्री की सोनिया गांधी से कोल्ड वॉर की

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एक और मिसाल, मनमोहन सिंह के प्रिय परमाणु विधेयक को लोकसभा से पास कराने के लिए सोनिया ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया था. सोनिया ने सरकार के गिरने तक का ख़तरा मोल लिया था, लेकिन सोनिया गांधी का पसंदीदा महिला आरक्षण विधेयक, एनएसी और सोनिया की मिन्नतों के बावजूद अभी भी अधर में लटका पड़ा है. सोनिया, संसद में महिलाओं की 33 फ़ीसदी से कम की नुमाइंदगी से ख़ुश नहीं हैं.

सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की सभी सलाहों को प्रधानमंत्री कार्यालय बग़ैर किसी विमर्श के ख़ारिज कर देता है. प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों के रवैये से एनएसी के सदस्य बेहद आहत और अपमानित हैं. पिछले दिनों इसके तीन सदस्यों-ज्यां द्रेज, अरुणा रॉय और हर्ष मंदर ने इस बात की खुलकर मुख़ालफ़त की. देश ने देखा कि किस तरह विशेषाधिकार प्राप्त एनएसी के सदस्यों को भी अपनी मांगों के लिए आम आदमी की तरह सड़क पर उतरना पड़ा.

सरकार ने केमिकल और पेट्रोकेमिकल विभाग के प्रमुख के. जोसे को तीन महीने के लिए फर्मास्युटिकल विभाग का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है.

दिल्ली, 28 नवंबर–04 दिसंबर 2011
चौथी दुनिया

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

अतिरिक्त प्रभार और बाबू

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के कारण बहुत से विभागों में सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है. सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटकर आने के बाद भी कई महत्वपूर्ण विभाग और मंत्रालय में सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है और इनके लिए अस्थाई व्यवस्था की गई है. सरकार ने केमिकल और पेट्रोकेमिकल विभाग के प्रमुख के. जोसे को तीन महीने के लिए फर्मास्युटिकल विभाग का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है. इसके अलावा नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव एसएनए ज़ैदी को प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. या तो सरकार यह समझती है कि ये विभाग इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि स्थाई सचिव की नियुक्ति की जाए या फिर उसे यह लगता है कि अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारी भी उसी तरह काम कर सकते हैं जिस तरह का काम स्थाई सचिव कर सकता है.

बाबुओं की समस्या

नियम के अनुसार सिविल सेवा का कोई भी अधिकारी सेवानिवृत्ति के एक साल तक निजी क्षेत्र की किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकता है. लेकिन यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में इस नियम का शायद ही अनुसरण किया गया था. आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, 2010 में 25 अधिकारियों में से मात्र एक अधिकारी को ही इसके लिए अनुमति नहीं दी गई. लेकिन इस बार सरकार ने यह तय किया है कि इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, एनएचएआई के एक अधिकारी ने सेवानिवृत्ति के पश्चात जब लर्सेन एंड टूब्रो कंपनी में काम करने के लिए मंत्रालय से अनुमति मांगी तो उन्हें अनुमति नहीं दी गई. ग़ौरतलब है कि बड़े अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद कंपनी में नियुक्त होते हैं और अपनी साख का उपयोग मंत्रालय से लाभ उठाने के लिए करते हैं. राज्य मंत्री नारायण सामी ने तो एक साल के समय को दोगुना करने का प्रस्ताव रखा है.

सीआईएल को प्रमुख का इंतज़ार

कोल इंडिया लिमिटेड जो कि देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 80 फ़ीसदी उत्पादित करता है, का अगला प्रमुख कौन होगा? इसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसके प्रमुख पार्थ एस. भट्टाचार्य का स्थान कौन लेगा, यह तय होना अभी बाक़ी है. सूत्रों के अनुसार कोयला मंत्रालय ने पीएसईबी को चयन समिति बनाने और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी है. पीएसईबी ने भी दो लोगों डीसी गर्ग और टीके लाहिरी का नाम प्रस्तावित किया है, लेकिन विजिलेंस कमीशन ने इस पर अपनी सहमति नहीं दिखाई. अब नए लोगों की तलाश की जा रही है. कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय भल्ला का कहना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया एक महीने के भीतर शुरू कर दी जाएगी. दरअसल, कोई भी मंत्रालय किसी वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति में जल्दबाज़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि वह किसी विवाद में फंसना नहीं चाहता है. सभी सुरक्षित रहना चाहते हैं.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

राजीव जेएस बने

1982 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव शर्मा को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है.

पंत निदेशक बनेंगे

1990 बैच के आईओएफएस अधिकारी राजेंद्र प्रसाद पंत को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में निदेशक बनाया जा सकता है. वह लखेश्वर साकिया की जगह लेंगे.

अतुल केंद्र में

1999 बैच के आईएएस अधिकारी अतुल पांते को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है. पांते मनु श्रीवास्तव की जगह लेंगे. अभी वह महाराष्ट्र में काम कर रहे थे.

मधुसूदन अतिरिक्त सचिव बनेंगे

1981 बैच के आईएएस अधिकारी मधुसूदन प्रसाद को वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया जाएगा. वह प्रदीप कुमार चौधरी की जगह लेंगे जिन्हें डीआईपीपी में सचिव बनाया गया है.

लोचन सड़क परिवहन मंत्रालय में

1992 बैच के आईडीईएस अधिकारी राजीव लोचन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में निदेशक बनाया जाएगा. वह आनंद प्रकाश की जगह लेंगे.

सरकार और पार्टी में दरार

पृष्ठ एक का शेष

एक अहम कड़ी है. इस योजना और तकनीक पर एनएसी के कुछ सदस्यों की आपत्ति है. उनके मुताबिक़, यह निजी स्वतंत्रता का हनन है. इसका लागू होना देश हित में नहीं है, जबकि मनमोहन सिंह की पुरज़ोर कोशिश है कि उनके बेहद ख़ास रहे नंदन नीलेकणी द्वारा संचालित यह योजना न सिर्फ़ देश भर में लागू हो, बल्कि यूआइडी को अनाज सुरक्षा तथा मनरेगा के जॉब कार्डों से भी जोड़ा जाए.

यही हाल मनरेगा के तहत काम करने वाले मज़दूरों की दिहाड़ी के मसले का भी है. पिछले साल 11 नवंबर को सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मनरेगा के तहत काम करने वाले मज़दूरों की न्यूनतम दिहाड़ी सुनिश्चित करने का आग्रह किया था. इसकी वजह यह थी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा से न्यूनतम मज़दूरी की अनिवार्यता ख़त्म कर दी थी. प्रधानमंत्री ने जब इस पत्र का जवाब दिया तो उसमें लिखा था कि वह सोनिया गांधी के सलाहकारों की राय से सहमत नहीं हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने न्यूनतम मज़दूरी की अनिवार्यता ख़त्म करने का जो फ़ैसला लिया है, वह बिलकुल सही है.

हालांकि बाद में न्यूनतम मज़दूरी में आंशिक बढ़ोत्तरी कर दी गई, पर प्रधानमंत्री के इस व्यवहार से तिलमिलाई एनएसी की सदस्य अरुणा रॉय खुलकर कहती हैं कि सरकार मज़दूरों के बुनियादी अधिकारों का हनन कर रही है और पिछड़े तबक़े को हाशिये पर धकेल रही है.

मनमोहन सरकार ने एनएसी द्वारा वन अधिकार क़ानून के क्रियान्वयन में मज़बूती लाने की सिफ़ारिश को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है. उस पर तुर्रा यह कि उलटे एनएसी को ही यह सलाह दे दी गई कि ऐसे मामलों पर वह सीधा मशविरा देने की बजाय आदिवासी और पर्यावरण मामलों के मंत्रालय से चर्चा करे.

यही हाल सूचना के अधिकार क़ानून के लिए बनाए गए नए मसौदे का है. इसमें इस बात का ज़िक्र है कि अब कोई आवेदनकर्ता किसी एक विषय पर महज़ 250 शब्दों में ही सवाल दायर कर सकता है. एनएसी का कहना है कि यह आरटीआई क़ानून की भावना के ख़िलाफ़ है और पारदर्शिता का हनन भी. लेकिन सरकार उसकी सलाह पर ग़ौर करने के लिए तैयार तक नहीं.

प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों के रवैये से एनएसी के सदस्य बेहद आहत और अपमानित हैं. पिछले दिनों इसके तीन सदस्यों–ज्यां द्रेज, अरुणा रॉय और हर्ष मंदर ने इस बात की खुलकर मुख़ालफ़त की. देश ने देखा कि किस तरह विशेषाधिकार प्राप्त एनएसी के सदस्यों को भी अपनी मांगों के लिए आम आदमी की तरह सड़क पर उतरना पड़ा.

ताज़ा मसला खाद्य सुरक्षा क़ानून का है. पिछले दिनों संसद के मानसून सत्र के लिए एजेंडा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नहीं, बल्कि सोनिया गांधी ने घोषित किया था. यूपीए–दो की दूसरी वर्षगांठ के मौक़े पर रात्रि भोज में सोनिया ने ऐलान किया कि सरकार अगले सत्र में भूमि अधिग्रहण और खाद्य सुरक्षा विधेयक पटल पर रखेगी.

वहां मौजूद कांग्रेस की एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री बताती हैं कि यह सुनकर मनमोहन सिंह महज़ मुस्कराए, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ बोलकर भोज का मज़ा किरकिरा नहीं किया. शायद यह सोचकर कि ये विधेयक पेश तो किए जाएंगे, लेकिन उनका प्रारूप वैसा नहीं होगा जैसा तैयार करने का निर्देश सोनिया ने दिया है.

खाद्य सुरक्षा विधेयक पर सरकार और सोनिया की अगुआई वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के बीच पिछले दो साल से बहस–मुबाहिसा चल रहा है. पेंच फंसा है ग़रीबी के आंकड़ों पर. एनएसी ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बीपीएल) का दायरा बढ़ाना चाहती है. एनएसी ने सोनिया गांधी से विचार–विमर्श कर इसका मसौदा पिछले साल ही प्रधानमंत्री के पास भेजा था.

देश में रोज़गार गारंटी योजना लागू करने के बाद के बाद भोजन के अधिकार का क़ानून लागू करवाना सोनिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, पर उनके मसौदे और प्रस्ताव को मनमोहन सिंह के आर्थिक सलाहकार और आर्थिक समिति के अध्यक्ष सी. रंगराजन ने यह कहते हुए रद्दी की टोकरी में डाल दिया कि एनएसी के सुझावों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता. क्योंकि देश में न तो इतना अनाज उपलब्ध है और न ही इतनी धनराशि कि 12,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा सके. काफ़ी वक़्त से सरकार इस पर टाल–मटोल कर रही थी, लेकिन अचानक इस मसौदे पर काम शुरू हो गया और इसमें प्रावधान भी वही रखे गए जो सोनिया और उनकी सलाहकार मंडली ने सुझाए थे. जो दो प्रमुख बदलाव किए गए हैं, उनमें सामान्य परिवारों को तीन किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति तथा इसका दायरा बढ़ाकर इसमें स्तनपान कराने वाली महिलाओं, ग़रीब और उम्रदराज़ लोगों के अलावा बच्चों का पोषक आहार शामिल किया जाएगा. उन्होंने बताया कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को छह माह के लिए एक हज़ार रुपये की राशि दी जानी है. अब यह 52 ज़िलों के बजाय देशभर में दी जाएगी, जबकि पहले इसी बिंदु को सी. रंगराजन ने नकार दिया था. वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के संशोधित मसौदे को मंज़ूरी दे दी है. अब इस विधेयक को जल्द मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा. हालांकि प्रस्तावित विधेयक से अब सरकार पर सब्सिडी का सालाना बोझ 1,00,000 करोड़ रुपये का पड़ेगा, जबकि वर्तमान में सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल सालाना 70,000 करोड़ रुपये का है.

मनमोहन सरकार के एक मंत्री इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों का सीधा हमला भ्रष्टाचार और घोटालों के मसले पर पी. चिदंबरम पर ही होगा. प्रधानमंत्री के लाडले मंत्री को मुसीबत से बचाने के लिए तरकश से यह तीर निकाला गया है, ताकि भोजन के अधिकार का क़ानून लागू करवाने की वाह–वाही की आड़ में सरकार महंगाई जैसे मसले पर भी अपना दामन बचाने की जुगत कर सके. पिछली बार चुनाव जिताऊ मनरेगा की तर्ज़ पर इस बार भी चुनाव जीतने के लिए खाद्य सुरक्षा क़ानून का ढिंढोरा पीटा जा सके.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 38
दिल्ली, 28 नवंबर–04 दिसंबर 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226004
फोन : 0522–2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
सी–20, ट्रांस यमुना, एनएच–2, आगरा
फोन : 0526–4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर–440012
फोन नं : 0712–2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

माया‌वती के पांच साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे एक उपलब्धि कहा जा सके. देश में जो माहौल है वह भ्रष्टाचार केख़िलाफ़ है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव

मायावती का मास्टर स्ट्रोक

उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने की मांग उठाकर मायावती ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है. सोची समझी रणनीति केतहत एक नई चाल चली है. उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है. इसकेमुख्यमंत्री का साम्राज्य गाज़ियाबाद से लेकर गोरखपुर और आज़मगढ़ से बलिया तक होता है. मायावती इतने बड़े राज्य की मुख्यमंत्री हैं. तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कौन मुख्यमंत्री चाहेगा कि अगला चुनाव जीतने केबाद वह एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री बने. वह भी तब जब राज्य में ऐसा माहौल भी नहीं है, जिसमें यह कहा जा सके कि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी मायावती को चुनाव में बुरी तरह से हराने वाली हैं. उत्तर प्रदेश में इन राज्यों की मांग को लेकर कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं चल रहा है. इसकेबावजूद अगर मायावती उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने का फ़ैसला करती हैं तो ज़रूर कोई गहरा राज़ होगा, कोई बड़ी राजनीतिक चाल होगी.

1955 में भीम राव आंबेडकर ने राज्य पुनर्गठन क़ानून की समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया था. उनकेमुताबिक़, उत्तर प्रदेश केपूर्वी, मध्य और पश्चिमी इलाक़ेको अलग राज्य घोषित कर देना चाहिए. उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि पूर्वी इलाक़े की इलाहाबाद, मध्य उत्तर प्रदेश की कानपुर और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरठ होनी चाहिए. उनकी दलील यह थी कि राष्ट्रीय राजनीति पर कहीं कोई बड़ा राज्य हावी न हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि देश में बड़े राज्य न हों. वह यह चाहते थे कि उत्तर प्रदेश केसाथ-साथ बिहार और मध्य प्रदेश को भी विभाजित किया जाना चाहिए. लेकिन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने उनके सुझावों को दरकिनार कर दिया. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का विभाजन किए बिना यह क़ानून 1956 में लागू कर दिया गया. उत्तर प्रदेश को बांटने की बात यहीं ख़त्म नहीं हुई. 1972 में 14 विधायकों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव में राज्य को तीन, ब्रज प्रदेश, अवध प्रदेश और पूर्वी प्रदेश में बांटने की मांग थी. यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका. उत्तर प्रदेश का बंटवारा तो ज़रूर हुआ, लेकिन आंदोलन की वजह से उत्तराखंड बन गया. बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया. इन दोनों राज्यों में बाबा साहेब की बात सही साबित तो हुई, लेकिन दलील अलग थी. दोनों राज्यों में विषमता की वजह से आंदोलन हुए जिसके कारण इन राज्यों का बंटवारा हुआ. उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है. आंदोलन मुखर तो नहीं है, लेकिन इस इलाक़े के लोग मानसिक तौर पर इसका समर्थन ज़रूर करते हैं.

मनीष कुमार

हमारे संविधान में नए राज्य बनाने की एक प्रक्रिया है. संविधान के मुताबिक़, नए राज्य बनाने का अधिकार संसद के पास है. यदि किसी प्रदेश के क्षेत्र, सीमा या नाम बदलने का सुझाव है तो ऐसे बिल को राष्ट्रपति संसद में भेजने से पहले संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजकर निश्चित समय सीमा के अंदर राय देने को कहेंगे और यदि उस समय सीमा के अंदर राय नहीं दी जाती है तो यह मान लिया जाएगा कि बिल के बारे में कोई विरोध नहीं है. राज्य के पुनर्गठन, विभाजन की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक नहीं है. मतलब यह है कि राज्य को बांटने का अधिकार और उसकी प्रक्रिया में राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है. मायावती ने राज्य के बंटवारे का जो फ़ैसला लिया है वह सिर्फ़ एक सुझाव मात्र है और यह एक ऐसा सुझाव है जिसकी राष्ट्रपति पर कोई बाध्यता भी नहीं है. उत्तर प्रदेश बांटा जाएगा या नहीं, यह फ़ैसला दिल्ली में होगा. मायावती संविधान को समझती हैं, विपक्षी दलों की राजनीति को भी समझती हैं. मायावती से बेहतर यह कोई नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग को न कांग्रेस और न ही भारतीय जनता पार्टी समर्थन देगी. वह इस बात को भी अच्छी तरह से जानती हैं कि यह ऐसी मांग है जो फ़िलहाल पूरी नहीं हो सकती है. साथ ही वह यह भी जानती हैं कि यह मुद्दा ऐसा है जिससे एक ही झटके में सभी विपक्षी पार्टियों केसारे चुनावी अंक गणित और बीज गणित को विफल कर सकती हैं. अब सवाल यह उठता है कि मायावती ने इन सब बातों को जानते हुए भी उत्तर प्रदेश के बंटवारे के मुद्दे को क्यों हवा दी.

मायावती केपांच साल केकार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे एक उपलब्धि कहा जा सके. देश में जो माहौल है वह भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ है. बिहार के चुनाव ने सभी राजनीतिक दलों को डरा दिया है, ख़ासकर उन पार्टियों को जिनका भ्रष्टाचार और अच्छी सरकार देने का रिकॉर्ड ख़राब है. बिहार के चुनाव में पहली बार लोगों ने जाति धर्म और समुदाय की दीवार को तोड़ कर वोट दिया. रामदेव और अन्ना हजारे ने इस माहौल को आगे बढ़ाया. यही वजह है कि हरियाणा केहिसार में कांग्रेस पार्टी की ज़मानत ज़ब्त हो गई, जबकि वहां कांग्रेस केतीन-तीन मुख्यमंत्रियों ने प्रचार किया. राजनीति इशारे देती है. जो राजनीतिक दल इन इशारों को समझते हैं, वे फ़ायदे में रहते हैं. मायावती इस ख़तरे को जानती हैं कि पांच साल सरकार में रहने के बाद लोगों का रुख़ उनके ख़िलाफ़ है. समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार के ख़िलाफ़ कई मुद्दे हैं. भ्रष्टाचार और घोटालों की पूरी फ़ेहरिस्त है. वह इस बात से भी वाक़िफ़ हैं कि अगर विपक्षी दलों को चुनाव का एजेंडा तय करने के लिए छोड़ दिया गया तो भ्रष्टाचार और सुशासन मुद्दा बन जाएगा. अगर ऐसा हो गया तो भारी नुक़सान होगा, जिसकी भारपाई नहीं की जा सकती है. मायावती को कोई ऐसा मुद्दा चाहिए था, जो लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं से जुड़ा हो और जो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर भारी पड़े.

राज्य को चार हिस्सों में विभाजित करने का मुद्दा एक लोकप्रिय मुद्दा है. इस मुद्दे से मायावती ने एक तीर से कई शिकार कर दिए. बुंदलेखंड, हरित प्रदेश और पूर्वी प्रदेश की मांग पुरानी है. कई सालों से यहां अलग राज्य की मांग हो रही है. यहां आंदोलन चल रहा है. कई संगठन सक्रिय हैं. इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अलग राज्य की मांग रखने वाले नेताओं और आंदोलनों को जनता का समर्थन प्राप्त है. राज्य के विभाजन पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कोई साफ़ नीति नहीं है. मायावती ने यह फ़ैसला लेकर इन आंदोलनों को अपने समर्थन में खड़ा कर दिया. वह इन आंदोलनों का चेहरा बन गई हैं. उन्होंने विपक्षी दलों को कठघरे में कर दिया. इन पार्टियों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें. मतलब यह कि मायावती ने इस मुद्दे को उठाकर न सिर्फ़ अपना समर्थन बढ़ाया, बल्कि विपक्षी दलों को मुसीबत में डाला और साथ ही अपने और सरकार के ख़िलाफ़ लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप, हत्याएं, मंत्रियों पर लगे आरोपों और ख़राब क़ानून व्यवस्था को मुद्दा बनने से रोक दिया.

अलग राज्य की मांग को लेकर सबसे ज़्यादा मुखर बुंदलखंड के लोग हैं. आज़ादी के कुछ दिनों बाद से ही यहां केस्थानीय नेता और कई संगठन इसे अलग राज्य बनाने की मांग उठा रहे हैं. बुंदेलखंड भारत के बीचो-बीच उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का इलाक़ा है. बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश केललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, जालौन, हमीरपुर, फ़तेहपुर और चित्रकूट ज़िले हैं, जबकि मध्य प्रदेश के छतरपुर, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, दतिया, भिंड, सतना आदि ज़िले शामिल हैं. दो राज्यों में बंटे होने केबावजूद यह इलाक़ा भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर पर एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है. इस इलाक़े में खनिज पदार्थ हैं. यह आर्थिक संसाधनों से परिपूर्ण भी है, लेकिन यह भारत के सबसे पिछड़े इलाक़ों में से एक है. उनकी दलील वही है, जो दलील झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ की रही है. राजनीतिक तौर पर मज़बूत न होने की वजह से इन इलाक़ों का विकास नहीं हो पाया है. न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार के पास इस इलाक़े के विकास के लिए कोई रोड मैप है. वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र की स्थिति बहुत ही गंभीर है. यहां के लोगों को लगता है कि अगर बुंदेलखंड अलग राज्य बन जाता है, तो यह इलाक़ा विकसित हो जाएगा. इसकी संभावित राजधानी झांसी है.

बुंदेलखंड की मांग विषमता की मार झेल रहे लोगों की है, तो दूसरी ओर पश्चिमी प्रदेश अमीर और विकसित होने के बावजूद अलग राज्य की मांग कर रहा है. इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव प्रभावशाली हैं. यादव उत्तर प्रदेश के हर इलाक़े में फैले हैं. पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट बहुल इलाक़ा है. हरियाणा और पंजाब की तरह यहां के जाट भी अमीर हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली नहीं हैं. यहां के लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की आमदनी का 72 फ़ीसदी पैसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है, लेकिन इसके विकास पर बजट का महज़ 18 फ़ीसदी पैसा ख़र्च होता है. अजीत सिंह हरित प्रदेश की मांग करते आए हैं. अजीत सिंह कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, कांग्रेस हरित प्रदेश का खुला समर्थन नहीं कर रही है. यही वजह है, नए राज्य के मुद्दे पर मायावती ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है.

उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाक़ा राज्य के दूसरे क्षेत्रों से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लिहाज़ से अलग है. यही विषमता पूर्वांचल राज्य या पूर्वी प्रदेश की मांग का आधार है. उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाक़ा जो बिहार और नेपाल से सटा है, उसे पूर्वांचल कहा जाता है. यह उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है. अगर इसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो यह इलाक़ा बहुत ही पीछे छूट गया है. यहां की आबादी ज़्यादा है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं. यह क्षेत्र अशिक्षा, बेरोज़गारी, ख़राब क़ानून व्यवस्था और ग़रीबी के लिए जाना जाता है. यहां के लोगों को लगता है कि सरकार की उपेक्षा की वजह से यह क्षेत्र पिछड़ रहा है. इसके अलावा जो क्षेत्र बच जाता है, वह अवध प्रदेश कहलाता है. मायावाती इन्हीं चार राज्यों का गठन करना चाहती हैं.

मायावती की सरकार की सबसे बड़ी चुनौती मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी से है. मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. उनकी रैलियों और यात्राओं को जनसमर्थन मिल रहा है. अखिलेश यादव मीडिया की नज़रों से दूर ज़रूर हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका काम चुनाव को ज़रूर प्रभावित करेगा. मायावती के लिए अगर कहीं से ख़तरा है तो वह समाजवादी पार्टी से है. अखिलेश यादव की नज़र मुस्लिम मतदाताओं पर है. समाजवादी पार्टी यादवों और मुसलमानों के समर्थन से चुनाव जीतती है. समाजवादी पार्टी विभाजन के ख़िलाफ़ है. उत्तर प्रदेश के बंटवारे से मुसलमानों के सामने भी एक सवाल खड़ा होता है. हरित प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 ज़िले ऐसे हैं, जहां मुस्लिम आबादी 20 से 49 फ़ीसदी है. मतलब यह कि इलाक़े की सीटों का फ़ैसला मुस्लिम मतदाता करेंगे. राजनीतिक तौर पर वे महज़ एक वोट बैंक से राजनीतिक शक्ति बन जाएंगे. मायावती ने अगर इस मुद्दे को उठाकर चुनाव में प्रचार किया तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है. लेकिन इससे एक ख़तरा पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो जाएगा. भारतीय जनता पार्टी इस मौक़े का फ़ायदा उठा सकती है. वैसे भी उत्तर प्रदेश इस मामले में संवेदनशील है.

कुछ राजनीतिक विश्लेषक और कई अख़बार यह लिख रहे हैं कि मायावती ने यह फ़ैसला राहुल गांधी के ख़तरे से निपटने के लिए किया है. इस तर्क में कोई दम नहीं है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, संगठन के तौर पर बहुत कमज़ोर है. वह विधानसभा में चौथे नंबर की पार्टी है. भ्रष्टाचार, घोटाले और महंगाई की मार से त्रस्त जनता का ग़ुस्सा कांग्रेस के प्रति है. कांग्रेस के नेता भले ही यह ऐलान कर दें कि इस बार वे 200 सीटें जीतेंगे, ज़मीनी हक़ीक़त यही है कि कांग्रेस अगर अपनी सीटों को बचा ले जाए तो यह एक कीर्तिमान माना जाएगा. अपनी ही पार्टी की समस्याओं से उलझी कांग्रेस को मायावती ने विभाजन के मुद्दे पर उलझा दिया है. केंद्र में कांग्रेस को ही इस मुद्दे पर फ़ैसला लेना है और विभाजन का समर्थन करना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल होगा. इसका सीधा असर यह होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मतदाता कांग्रेस गठबंधन से दूर चले जाएंगे. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह के सहारे सीटें बटोरने की कांग्रेस की चाल को मायावती ने पटरी से उतार दिया. इस इलाक़े की डेमोग्राफी ऐसी है कि इससे मुसलमानों का वोट कांग्रेस के हाथ से जाता रहेगा. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका होगा.

मायावती ने उत्तर प्रदेश के विभाजन का जो मुद्दा उठाया है, वह एक चुनावी मुद्दा है. चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाकर मायावती ने चुनाव में लीड ले ली है. उन्होंने अपने हिसाब से चुनाव का मुद्दा तय किया है. दूसरे दलों को अब सोचना पड़ेगा कि इस मुद्दे के जवाब में कौन-सा मुद्दा उठाया जाए. अगर यह मुद्दा चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया तो मायावती को हराना मुश्किल हो जाएगा. समाजवादी पार्टी को इसका जवाब तलाशना होगा. भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीति साफ़ रखनी होगी. भारतीय जनता पार्टी देश में अलग राज्य बनाने वाले आंदोलनों को समर्थन देती रही है. अगर वह उत्तर प्रदेश के विभाजन के विरोध में है तो उसे यह बताना होगा कि विरोध का कारण क्या है. इसकेअलावा मायावती को चुनौती देने वाली पार्टियों को जनता से जुड़े मुद्दों पर लौटना पड़ेगा.

manish@chauthiduniya.com

राज्य को बांटने का अधिकार और उसकी प्रक्रिया में राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है. मायावती ने राज्य केबंटवारे का जो फ़ैसला लिया है वह सिर्फ़ एक सुझाव मात्र है और यह एक ऐसा सुझाव है जिसकी राष्ट्र पति पर कोई बाध्यता भी नहीं है. यह ऐसी मांग है जो फ़िलहाल पूरी नहीं हो सकती है. अब सवाल यह उठता है कि मायावती ने इन सब बातों को जानते हुए भी उत्तर प्रदेश केबंटवारे केमुद्दे को क्यों हवा दी.

राजनीति इशारे देती है. जो राजनीतिक दल इन इशारों को समझते हैं, वे फ़ायदे में रहते हैं. मायावती इस ख़तरे को जानती हैं. समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास भ्रष्टाचार और घोटालों की पूरी फ़ेहरिस्त है. अगर विपक्षी दलों को चुनाव का एजेंडा तय करने के लिए छोड़ दिया गया तो भ्रष्टाचार और सुशासन मुद्दा बन जाएगा. मायावती को कोई ऐसा मुद्दा चाहिए था, जो लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं से जुड़ा हो और जो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर भारी पड़े.

माया‌वती ने कहा कि देश की सत्ता लंबे वक़्त तक सवर्ण समाज के हाथों रही, लेकिन इस समाज के मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोग आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में काफ़ी पिछड़े रहे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव

बसपा का ब्राह्मण-दलित कार्ड

अजय कुमार

कभी बहुजन समाज पार्टी का नारा होता था–तिलक, तराज़ू और तलवार, इनको... बसपा दलितों को बताने से नहीं चूकती थी कि ब्राह्मणों के कारण आज भी दलित आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिये पर खड़े हैं. दलित मतदाता बसपा सुप्रीमो मायावती की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते, यह वह दौर था जब मायावती दलितों के सहारे सत्ता की चाबी मज़बूती के साथ हासिल करने का सपना पाले हुए थीं. उन्होंने क़रीब 15 वर्षों तक शुद्ध रूप से दलित राजनीति की. वह कांशीराम के पदचिन्हों पर चल रही थीं. कांशीराम सिर्फ़ और सिर्फ़ दलितों की बात करते थे. एकमुश्त दलित वोट बैंक के सहारे माया तीन बार सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में सफल रहीं, लेकिन बैसाखियों के सहारे. तीनों ही बार उन्हें बनिया–ब्राह्मण की पार्टी कही जाने वाली भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब हुई.

कांशीराम की बात की जाए तो इसके बाद भी बनिया–ब्राह्मण और क्षत्रियों से उनकी नाराज़गी कम नहीं हुई थी. ऐसा नहीं था कि बसपा में कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं था. बसपा में ब्राह्मण नेता तो कई मौजूद थे, लेकिन अपवाद को छोड़कर किसी नेता की अपने समाज पर मज़बूत पकड़ नहीं थी. रामवीर उपाध्याय जैसे एक–दो नेता थे, जो ब्राह्मण समाज को बसपा के साथ खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्हें शोपीस बनकर ही पार्टी में रहना पड़ रहा था.

बहरहाल, 15–20 वर्षों की राजनीति में मायावती यह ज़रूर समझ गई थीं कि दलितों के सहारे बहुमत के साथ सत्ता पर नहीं आया जा सकता है. उनकी सोच बदलने का काम किया सतीश चंद्र मिश्र ने. सतीश मिश्र को उन्होंने अपने शासन काल में प्रदेश सरकार का महाधिवक्ता नियुक्त किया. इसके बाद सतीश मिश्र मायावती के क़ानूनी कार्य करने लगे. आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या फिर अन्य कोई मुक़दमा सतीश चंद्र मिश्र बसपा सुप्रीमो के रक्षार्थ चट्टान की तरह खड़े रहते. क़ानूनविद् सतीश चंद्र मिश्र ने ही मायावती की सोच बदलने का काम किया. ब्राह्मणों के मन में उनके प्रति नफ़रत का जो गुबार भरा हुआ था वह सतीश मिश्र ने काफ़ी कम कर दिया.

दलित हितों की बात करने वाली बसपा सोशल इंजीनियरिंग की लाइन पर चल पड़ी और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के साथ ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, का नया नारा बसपा के मंच से गूंजने लगा. सतीश चंद्र मिश्र ने ब्राह्मणों और दलितों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया. परिणाम सबके सामने था. मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनीं, लेकिन इस बार वह अपने दम पर सत्ता में आई थीं. बस यहीं से उनका सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला चल निकला. इसी को मायावती 2012 के विधानसभा चुनाव में फिर आज़माने जा रही हैं. इस बात का प्रमाण बन रहे हैं ब्राह्मण भाईचारा कमेटी के सम्मेलन. ऐसा ही एक सम्मेलन पिछले दिनों लखनऊ में हुआ, जिसने काफ़ी सुर्ख़ियां बटोरीं. सतीश चंद्र मिश्र, बृजेश पाठक और रामवीर उपाध्याय जैसे नेताओं ने इसे सफल बनाने का काम किया तो मायावती ने एक घंटे से अधिक का समय देकर ब्राह्मणों को यह संदेश देने की कोशिश की कि बसपा के लिए ब्राह्मण कितने महत्वपूर्ण हैं.

2007 में ब्राह्मण–दलित गठजोड़ से अपनी जीत की ज़मीन तैयार करने वाली बसपा 2012 में एक बार फिर विरोधी दलों को इसी ख़ास दांव से चित करने के मूड में है. सम्मेलन में वह ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच के फ़ासले को भी दर्शाना नहीं भूली. मायावती ने भाजपा–कांग्रेस पर अंदरख़ाने समझौते की बात कहकर इन दोनों पार्टियों के लिए मुश्किलें बढ़ाने का भरसक प्रयास किया. बसपा के इसी तरह के एक दांव से पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा–सपा विधानसभा चुनाव में नुक़सान उठाना पड़ा था. तब बसपा ने सपा–भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत की बात उछाली थी. इससे जहां भाजपा के कमज़ोर पार्टी होने का संदेश वोटरों में गया, वहीं मुस्लिमों में भी सपा को लेकर संदेह गहराया, जिस कारण सवर्ण वोटर भाजपा से छिटका और मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा बसपा के साथ खड़ा हो गया.

बसपा ने इसका फ़ायदा ब्राह्मण–दलित गठजोड़ को मज़बूत बनाकर उठाया, जिसके सहारे वह बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता पर क़ाबिज़ हो गई. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने दिग्विजय सिंह व राजनाथ सिंह का नाम लेकर इशारों–इशारों में यह संदेश देने की कोशिश की है कि भाजपा व कांग्रेस जैसी पार्टियों को ब्राह्मणों की चिंता नहीं है. वैसे भी सवर्ण बिरादरी में राजनीतिक रूप से ब्राह्मणों के मुक़ाबले क्षत्रिय वर्ग को अधिक ताक़तवर माना जाता है. मायावती के इस शिगूफ़े से ब्राह्मण समाज में तमाम आशंकाएं घर कर सकती हैं.

बसपा जानती है कि उसे सरकार बनाने के लिए भाजपा व कांग्रेस के मुक़ाबले समाजवादी पार्टी ही असली चुनौती दे सकती है, लेकिन सवर्ण बिरादरी का वोट भाजपा–कांग्रेस की ओर जाने से रोकने के लिए बसपा ने यह दांव चला है. बसपा इस बात से उत्साहित ज़रूर है कि चुनाव में दोनों इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में होंगे. बसपा ने वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में उस घटना को सपा–भाजपा की मिलीभगत का सबूत बताया था, जिसमें भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी व अन्य नेता अपने विधायक पर पुलिसिया उत्पीड़न की शिकायत करने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के आवास पर गए थे और वहां मुलायम सिंह यादव ने भाजपा नेताओं की न केवल गंभीरता से बात सुनी, बल्कि उन्हें चाय–नाश्ता भी कराया था. जबकि भाजपा नेताओं की दलील थी कि यह सब औपचारिकतावश किया गया था.

भाजपा पूरी तरह सपा के विरोध में थी, लेकिन बात बनी नहीं. यही नहीं कई अन्य मौक़ों पर भी मुलायम सरकार की भाजपा के प्रति नरमी चर्चा का विषय रही थी. इससे चुनाव में भाजपा की छवि को गहरा आघात लगा. जब लोकसभा चुनाव आया तो बसपा ने कल्याण सिंह व सपा की नज़दीकियों को मुद्दा बनाया. इससे अल्पसंख्यक सपा से दूर होकर कांग्रेस के साथ हो लिए.

इस चुनाव में सपा का एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीता. वैसे बसपा समय–समय पर कांग्रेस व भाजपा को निशाने पर लेती रही है, लेकिन भाजपा से कांग्रेस के गठजोड़ की चर्चा ने अगर असर दिखाया तो इसमें भाजपा का कम कांग्रेस का ज़्यादा नुक़सान होगा. बसपा सुप्रीमो ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए ग़रीब ब्राह्मणों को आरक्षण देने की मांग को भी मज़बूती के साथ उठा रही हैं. मायावती ने कहा कि देश की सत्ता लंबे वक़्त तक सवर्ण समाज के हाथों रही, लेकिन इस समाज के मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोग आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में काफ़ी पिछड़े रहे. बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने आंकड़ों के माध्यम से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की. सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि ब्राह्मणों को सबसे तवज्जो इसी सरकार में मिली है. वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में बसपा 85 सीटों में 19 जीतीं तो अगले चुनाव में उसने 62 आरक्षित सीटें जीतीं. इसी तरह ब्राह्मण विधायकों की तादाद भी चार से बढ़कर 45 हो गई. बसपा के सात सांसद ब्राह्मण हैं. एक दर्जन को मंत्री बनाया गया, तो दर्जनों ब्राह्मणों को विभिन्न निगमों, आयोग में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाया गया है.

ब्राह्मण समाज भाईचारा कार्यकर्ता सम्मेलनों की पूरी धुरी सतीश चंद्र मिश्र के इर्द–गिर्द घूमती रहती थी, लेकिन अबकी बार सत्ता संतुलन के कई और केंद्र भी बसपा में देखने को मिले. बसपा के मंत्री रामवीर उपाध्याय और सांसद बृजेश पाठक भी मुख्य भूमिका में नज़र आए. मंच पर इलाहाबाद के नेता अशोक वाजपेयी की मौजूदगी ने कौतुहल पैदा किया. नारे बसपा के सम्मेलनों में नया जोश पैदा करते हैं. इस सम्मेलन में भी कुछ नए तो कई पुराने नारे हवा में उछले. बहन जी के सम्मान में, ब्राह्मण समाज मैदान में, पर ख़ूब तालियां बजीं. बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने मायावती को गणेश की प्रतिमा से युक्त स्मृति चिन्ह भेंटकर हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा,विष्णु,महेश है, के नारे को चरितार्थ किया.

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

राजनीतिक फंदे में फंसा स्टील प्लांट

सरोज सिंह

बिहार में महनार के सहदेई खुर्द, रामपुर कुमरकोल और कुमरकोल बुज़ुर्ग के किसानों ने इलाक़े के विकास के लिए चार साल पहले एक सपना देखा था. सपना ऐसा कि उनकी कई पीढ़ियां उन पर नाज़ करतीं और उनका भविष्य संवर जाता, लेकिन राजनीति की बिसात पर पड़े कुछ क़दमों ने उनके सपनों को चूर–चूर कर दिया. आज ये किसान इस बात पर अफ़सोस कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट सेल को प्लांट लगाने के लिए ज़मीन दी. किसानों का दर्द यह है कि उन्होंने बड़ी उम्मीद और भरोसे से ज़मीन दी, पर सेल का प्लांट न जाने किन अड़चनों में फंसकर रह गया है. किसान अब इतने नाउम्मीद हो गए हैं कि वे अब अपनी ज़मीन तक वापस लेने की बात करने लगे हैं. चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह जैसे कुछ किसानों का तो कहना है कि उन्हें ज़मीन के पूरे पैसे भी नहीं मिले हैं. हालांकि अशोक कुमार सिंह उर्फ़ भोला सिंह इन आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहते हैं कि सारे किसानों को पैसा दे दिया गया है और कोई किसान अपनी ज़मीन वापस चाहता है तो रक़म वापस कर अपनी ज़मीन ले सकता है. लेकिन बेहतर होता कि रामविलास पासवान व पूर्व विधायक रमा सिंह ने क्षेत्र के विकास के लिए प्लांट लगवाने का जो सपना देखा था उसे सभी लोग मिलकर पूरा करते. महनार के हक़ की लड़ाई सभी लोग मिलकर लड़ें. सेल का प्लांट महनार व वैशाली का हक़ है, उसे लेने के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक संघर्ष हो. चंद्रेश्वर प्रसाद भी कहते हैं कि राजनीति से हम लोगों का कुछ लेना–देना नहीं. हम सभी किसान चाहते हैं कि प्लांट लगे और इलाक़े में विकास की गंगा बहे, ताकि हमारी अगली पीढ़ियों को रोज़गार के लिए इधर–उधर न भटकना पड़े.

दरअसल, आरटीआई की मार्फत सेल ने जो सूचना दी, उससे इलाक़े के किसानों का दिल ही टूट गया. सेल की सूचना के मुताबिक़ प्लांट लगाने के लिए 208 किसानों ने 50.69 एकड़ ज़मीन दी. 3.94 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से इसका कुल मूल्य 199.72 लाख रुपये हुआ. प्लांट लगाने के संबंध में सेल ने कहा कि वर्तमान स्थिति पुर्नावलोकन एवं विचाराधीन है. मतलब सेल ने जो सूचना दी है उसका साफ़ अर्थ है कि मामला लटक गया है. यही वे हालात हैं जिन्होंने महनार के किसानों को बैचेन कर दिया है. उन्हें लगता है कि अब वे न घर के रहे, न घाट के. कहा जाए तो राजनीति की बदलती तस्वीर ने महनार में स्टील प्लांट के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया. इस प्लांट की बुनियाद तब पड़ी जब रामविलास पासवान इस महकमे के केंद्रीय मंत्री थे. रमा सिंह बिहार विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन राजनीति ने ऐसा पलटा खाया कि महनार के किसानों का भाग्य ही फूट गया. सत्ता की हनक ख़त्म हुई तो सेल ने भी क़दम पीछे खींच लिए. प्लांट की पूरी ज़मीन ख़ाली पड़ी है और यहां के किसान इसे

टकटकी लगाकर बस देख रहे हैं. सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सेल और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए कोई भी दल तैयार नहीं है. अभी कुछ दिन पहले रामविलास पासवान ने हाजीपुर में धरना दिया था, पर बात इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकी. बार–बार विकास का रट लगाने वाली बिहार सरकार की ओर से सेल पर दबाव बनाने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. बिहार सरकार ने केंद्र सरकार पर भी इस बाबत कोई दबाव नहीं बनाया है. जानकार बताते हैं कि स्टील प्लांट का श्रेय दूसरे नेता को मिलेगा, इसलिए बिहार सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत संजीदा नहीं है. हर तरफ़ से हताश होने के बाद किसानों की ओर से चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह ने इस बारे में सेल और अशोक कुमार सिंह को अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा है. सेल को भेजे नोटिस में कहा गया है कि ज़मीन लेने से पूर्व सेल ने यह आश्वासन दिया था कि कंपनी यहां प्लांट लगाएगी जिससे क्षेत्र का विकास होगा एवं ज़मीन देने वालों के घर के सदस्य को योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी. लेकिन 2 जून, 2008 को हुए क़रार के आधार पर दी गई ज़मीन पर आज तक कोई कार्रवाई एवं प्रगति नहीं हुई है. नोटिस में कहा गया है कि सेल द्वारा तय क़ीमत एवं उनके दिए गए ज़मीन के रक़बे के अनुसार पैसा नहीं मिला है एवं कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनकी ज़मीन तो ले ली गई है, पर उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला है. ज़मीन कंपनी को देने का मक़सद क्षेत्र का विकास एवं बेरोज़गारों को रोज़गार प्राप्त कराना था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है. नोटिस में कहा गया है कि अगर सेल वहां प्लांट नहीं लगाना चाहती है तो किसानों को उनकी ज़मीन वापस कर दी जाए और इसमें कोई और योजना हो तो किसानों की सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जाए. नोटिस में पूछा गया कि सेल की बोकारो में प्लांट लगाने की क्या योजना है और भुगतान की स्थिति क्या है?

देखा जाए तो यह किसानों की हताशा ही है कि उन्हें लीगल नोटिस का विकल्प अपनाना पड़ा, लेकिन अगर यह स्थिति पैदा हुई तो कहीं न कहीं इसकी जड़ में दलीय राजनीति है. एक–दूसरे को श्रेय न मिले, इसे लेकर प्लांट की लेट लतीफ़ी को अनदेखा किया जा रहा है. बेतिया में सब हो गया तो महनार में किसकी नज़र लग गई. महनार के वरिष्ठ नेता सहदेव साव कहते हैं कि प्लांट तभी लगेगा जब इससे राजनीति को बाहर किया जाएगा. निजी हित से ऊपर उठना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि महनार में प्लांट लगाना पहली प्राथमिकता होगी चाहे इसके लिए कोई भी क़ुर्बानी क्यों न देनी पड़े. आख़िर सेल अपनी बात से पीछे कैसे जा सकता है. उन्होंने कहा कि नीयत साफ़ होगी तो रास्ता तो बन ही जाएगा. अशोक सिंह व महनार के सारे किसानों को उम्मीद है कि सरकार जागे और प्लांट लगाने की प्रकिया ज़ोरशोर से महनार में शुरू हो, ताकि इस पूरे इलाक़े का कायाकल्प हो सके. किसानों का कहना है कि अब वे चुप नहीं रहेंगे और विधानसभा से लेकर संसद तक अपनी बात रखवाएंगे.

feedback@chauthiduniya.com

जबलपुर ज़िले के अंतर्गत चल रहे अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए कलेक्टर गुलशन बामरा द्वारा गठित किए गए विशेष दल ने सिहोरा तहसील की कुछ खदानों का औचक निरीक्षण किया.

मध्य प्रदेश

यहां भी है माइनिंग का महाघोटाला

- नेताओं, अधिकारियों और खनिज माफ़ियाओं का गठजोड़
- अरसे से जारी है मध्य प्रदेश में अवैध खनन का गोरखधंधा
- करोड़ों के सरकारी राजस्व का नुक़सान, पर्यावरण को क्षति
- शिकायत पर कार्रवाई नहीं, खनिज मंत्री भी संदेह के घेरे में

जल, जंगल, ज़मीन और आसमान. ऐसी कोई जगह नहीं जो घोटालेबाज़ों की गिद्ध दृष्टि से बची हो. प्राकृतिक संसाधनों की लूट के इस खेल में सरकार, विपक्ष, पूंजीपतियों समेत हर वह आदमी शामिल है जिसके संबंध सत्ता में बैठे लोगों से हैं और जिनके पास धनबल, बाहुबल है. कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, गोवा और अब मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में माइनिंग महाघोटाले की जड़ें कहां-कहां तक फैली हैं और कौन-कौन से लोग इसमें शामिल हैं, पढ़िए चौथी दुनिया की इस ख़ास रिपोर्ट में:

माइनिंग लीजधारी कंपनियों द्वारा इस खनिज का प्रदेश व देश के बाहर निर्यात किया जा रहा है. प्रत्येक रेलवे रेक के केमिकल ऍनालिसिस (ब्लू डस्ट) के मुताबिक़, उसमें 62 प्रतिशत से 66 प्रतिशत आयरन होता है. लेकिन हाई ब्लू डस्ट की रॉयल्टी 78 रुपये प्रति टन की जगह 48 रुपये प्रति टन लो ब्लूडस्ट के हिसाब से जमा कराई जा रही है. इस हिसाब से जमकर रॉयल्टी चोरी की जा रही है. पैसिफिक एक्सपोर्ट प्राइवेट लि. कटनी को प्रतिवर्ष 80 हज़ार मीट्रिक टन आयरन और खनन की अनुमति दी गई थी.

देश के हृदय स्थली माने जाने वाले इस राज्य के विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल का इलाक़ा खनिज तत्व से भरा है. ज़ाहिर है, मुनाफ़े के लालच में इसका बड़े पैमाने पर अवैध खनन, परिवहन तथा ख़रीद-बिक्री भी चल रही है. यह ग़ैर क़ानूनी काम न सिर्फ़ ज़िला प्रशासन, पुलिस और खनन से संबंधित प्रशासनिक विभागों के नौकरशाहों की मिलीभगत से हो रहा है, बल्कि इसमें स्थानीय और राज्य के प्रभावशाली नेताओं, विधायकों, मंत्रियों और उनके क़रीबी भी शामिल हैं. पिछले कुछ सालों से जारी इस अवैध खनन से अरबों रुपये के सरकारी राजस्व का नुक़सान तो हो ही रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंच रही है. जबलपुर व छतरपुर ज़िलों के सिहोरा तहसील, मझगवां थाना अंतर्गत झीटी, दुबयारा, अगरिया, घुघरी, टिकरिया प्रतापपुर गांवों में अंधाधुंध तरीक़े से उच्च तकनीक युक्त मशीनों से अवैध खनन का काम चल रहा है, वह भी बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के. माइनिंग लीजधारी कंपनियों द्वारा इस खनिज का प्रदेश व देश के बाहर निर्यात किया जा रहा है. प्रत्येक रेलवे रेक के केमिकल ऍनालिसिस (ब्लू डस्ट) के मुताबिक़, उसमें 62 से 66 प्रतिशत आयरन होता है. लेकिन हाई ब्लू डस्ट की रॉयल्टी 78 रुपये प्रति टन की जगह 48 रुपये प्रति टन लो ब्लूडस्ट के हिसाब से जमा कराई जा रही है. इस हिसाब से जमकर रॉयल्टी चोरी की जा रही है. बानगी के तौर पर पैसिफिक एक्सपोर्ट प्राइवेट लि. कटनी को प्रतिवर्ष 80 हज़ार मीट्रिक टन आयरन और खनन की अनुमति दी गई थी. लेकिन सितंबर 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि में कंपनी ने 11,96,450 मीट्रिक टन आयरन का खनन किया.

जबलपुर ज़िले के अंतर्गत चल रहे अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए कलेक्टर गुलशन बामरा द्वारा गठित किए गए विशेष दल ने सिहोरा तहसील की कुछ खदानों का औचक निरीक्षण किया. इसमें कई अनियमितताएं सामने आईं. खदान संचालकों द्वारा खनन में स्वीकृत माइनिंग प्लान की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं. यह जांच दल जल्द ही जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगा. जांच दल के मुखिया एडीएम अक्षय कुमार सिंह के अनुसार, ग्राम सिलुआ में खत्री मिनरल्स, केवलारी में शोभा मिनरल्स और हृदयनगर में श्रीकांत पांडे की खदानों में किए गए निरीक्षण में पाया गया कि इन खदानों में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा. खदानों में फेंसिंग और सुरक्षा दीवार भी नहीं है. इस इलाक़े में स्वीकृत माइनिंग लीज के विवरण के अनुसार, कंपनियों/फर्मों/व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत माइनिंग लीज क्षेत्र एवं समीपवर्ती इलाक़ों में भारी भरकम मशीनों तथा मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा खनिज मंत्रालय के मंत्रियों की मिलीभगत से प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है. पूर्व में भी इस संबंध में शासन स्तर पर अनेक व्यक्तियों/संगठनों द्वारा शिकायतें प्रस्तुत की गई थीं. परंतु अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दबाव में इन शिकायतों को दबा दिया गया. भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के डीसीएफ (एमआईएफ) सुजाय बैनर्जी (वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन ज़मीन के डायवर्सन अधिकारी) ने राज्य सरकार को आगाह भी किया था कि इस तरीक़े से खनन की अनुमति देने से रिजर्व फॉरेस्ट को भारी नुक़सान पहुंचेगा.

लोकायुक्त की जांच की ज़द में आए राज्य सरकार के दो बड़े मंत्री राजेंद्र शुक्ला और नागेंद्र सिंह के संबंध में राज्य के एक वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी ने एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है. इस रिपोर्ट में इन मंत्री पर खनिज माफ़िया को सहयोग देने और इसकी वजह से एक भारी भरकम घोटाले की संभावना जताई गई है.

इस पूरे प्रकरण का एक दिलचस्प पहलू है अवैध खनन के मामले में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों दलों के लोग शामिल हैं. मसलन, सिहोरा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने जबलपुर कलेक्टर और वन एवं पर्यावरण मंत्री को इस पूरे मामले में एक शिकायत पत्र भेजा. पूर्व विधायक ने 17 अक्टूबर को भेजे अपने पत्र में निर्मला मिनरल्स एवं आनंद माइनिंग कारपोरेशन (दिग्विजय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे सत्येंद्र पाठक, वर्तमान में उनके विधायक पुत्र व प्रदेश कांग्रेस महामंत्री और कटनी नगर निगम में महापौर निर्मला पाठक की भागीदारी वाली कंपनियों) के ख़िलाफ़ शिकायत की. जबकि स्वयं शिकायतकर्ता, भाजपा के पूर्व विधायक, उनके पुत्र व परिजन पैसेफिक एक्सपोर्ट प्रा. लि. से जुड़े हुए हैं और ट्रेडिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं. साथ ही अवैध खनन, अवैध परिवहन और रॉयल्टी चोरी को संरक्षण दे रहे हैं.

बहरहाल, अवैध खनन की शिकायत राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक भी की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ है. जनता दल (यू) के कुछ लोगों ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से भी की है और गंभीर पर्यावरण क्षति तथा शासन को अरबों रुपये के राजस्व नुक़सान संबंधी शिकायत की जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है. प्राकृतिक संसाधनों की मची इस लूट को एनडीए के संयोजक और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव द्वारा केंद्रीय खनिज मंत्री दिनशा पटेल के समक्ष 2 सितंबर, 2011 को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान भी उठाया गया था. बहरहाल, इतना सब कुछ होने के बाद अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी भ्रष्टाचार की परतें खुलने और अवैध खनन से कई सौ करोड़ का खनिज घोटाला सामने आने की बातें करने लगे हैं. अभी हाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेल के प्रभारी मानक अग्रवाल ने प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी की कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें जबलपुर की सिहोरा तहसील में 600 करोड़ रुपये के माइनिंग घोटाले का आरोप लगाया गया है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच इस महाघोटाले के सूत्रधारों और दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो पाएगी या फिर माइनिंग का यह महाघोटाला भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा?

अरविंद वर्मा/शशि शेखर
feedback@chauthiduniya.com

किसे कितना मिला है

इस इलाक़े में स्वीकृत माइनिंग लीज के विवरण के अनुसार, माइनिंग लीजधारी मै. पेसेफिक एक्सपोर्ट प्रा. लि., 15 डन मार्केट बरगवां, कटनी को ग्राम झीटी के खसरा नंबर 426, 412 (पी-26) में क्रमश: 6.40 हेक्टेयर और 20.65 हेक्टेयर के रक़बे में लीज स्वीकृत है. इस जगह पर काम चालू है. इसी तरह मै. निर्मला मिनरल्स पाठक वार्ड, कटनी को ग्राम अगरिया के खसरा नंबर 1093, 628 /1,(पी.- 32) में 20.141 हेक्टेयर और ग्राम दुबियारा के 32.374 हेक्टेयर रक़बे में लीज स्वीकृत है, जहां अभी काम चालू है. मै. आनंद माइनिंग कारपो., पाठक वार्ड, कटनी को ग्राम टिकरिया, दुबियारा व प्रतापपुर के खसरा नंबर 372, 495, 496, 497 में क्रमश: 20.002 हेक्टेयर व 11.578 हेक्टेयर में लीज स्वीकृत है. यहां भी काम चालू है. जबकि माया सिंह तोमर, ग्राम झीटी और ग्वालियर में 04.000 हेक्टेयर ज़मीन पर खनन प्रारंभ होना है. दूसरी ओर निवेदन भारद्वाज, ग्राम झीटी में 12.000 हेक्टेयर ज़मीन पर भी खनन कार्य शुरू होना है. लक्ष्मी नरसिंग को ग्राम झीटी में 04.000 हेक्टेयर ज़मीन पर खनन के लिए लीज दिया गया है और अभी इस ज़मीन पर भी कार्य शुरू होना है. मै. खजुराहो मिनरल्स, छतरपुर को भी 4.950 हेक्टेयर ज़मीन पर खनन के लिए लीज दिया गया है और यहां खनन का काम चालू है.

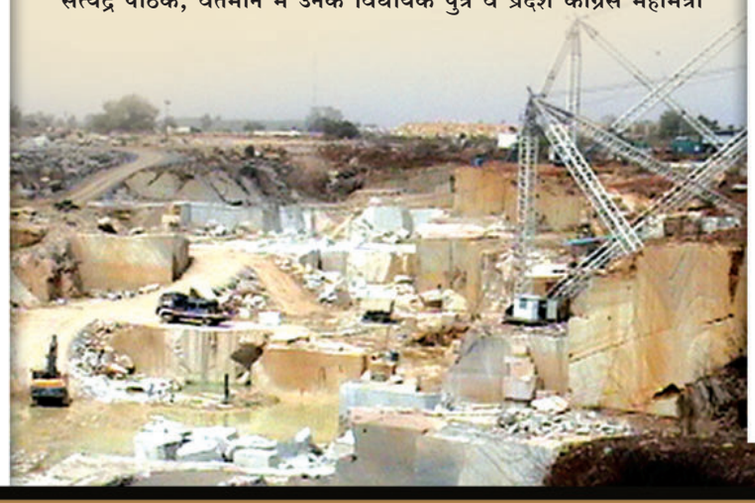

मंत्री भी शक के घेरे में हैं

मध्य प्रदेश में इतना सब कुछ चल रहा है, मगर इस दौरान एकाएक बहुत तेज़ी से उभरे-पनपे अवैध खनन उद्योग एवं इसके संचालक खनिज माफ़िया पर किसी तरह के कड़े अंकुश की बजाय उसे एक तरह से क्लीन चिट दिए जाने में भी शिवराज मंत्रिमंडल के खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला को कहीं कोई हिचक तक नहीं हो रही है. शुक्ला यह तो मानते हैं कि प्रदेश का एक बड़ा इलाक़ा, विशेषकर कटना ज़िला अवैध खनन का सबसे बड़ा केंद्र है. उनके ही अनुसार, विगत एक अरसे में उनके पास तत्संबंधी राज्य भर में सबसे अधिक शिकायतें पहुंची हैं. लेकिन कार्रवाई के नाम पर वह न तो कुछ कहते हैं और न कुछ करते हैं. और करें भी क्यों, जब ख़ुद मंत्री जी पर ही सवाल खड़े हो रहे हों. लोकायुक्त की जांच की ज़द में आए राज्य सरकार के दो बड़े मंत्री राजेंद्र शुक्ला और नागेंद्र सिंह के संबंध में राज्य के एक वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी ने एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है. इस रिपोर्ट में इन मंत्री पर खनिज माफ़िया को सहयोग देने और इसकी वजह से एक भारी भरकम घोटाले की संभावना जताई गई है. अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी मंत्री नागेंद्र सिंह और खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला को नागौद, उचेहरा क्षेत्र में दर्जन भर से अधिक अवैध खदानों के संचालन की पृष्ठभूमि में शामिल बताया गया है. ज़ाहिर है, जब खनिज संपदा की रक्षा के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति पर ही सवाल उठ रहे हों तो भला खनिज माफ़िया पर कार्रवाई की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है?

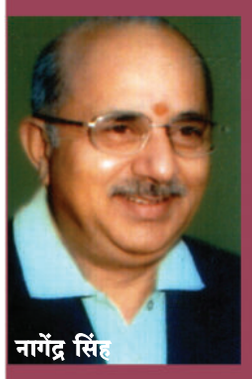

नागेंद्र सिंह

राजेंद्र शुक्ला

तत्काल प्रभाव से लागू इस रक्षा उत्पादन नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि इसमें प्राथमिकता रक्षा उपकरणों के देशी डिज़ाइन, विकास और विनिर्माण को ही दी जाएगी.

भारत की रक्षा उत्पादन नीति

चुनौतियां और अवसर

भारत के पास अपनी सेना को आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाने की इच्छा भी है और क्षमता भी. रक्षा के कुल बजट में से लगभग 40 प्रतिशत (अर्थात 14.5 बिलियन डॉलर) रक्षा पूंजी परिव्यय बजट के लिए आवंटित किया गया है, जिससे हथियारों की प्राप्ति, निर्माण और अधिष्ठापनों और अतिरिक्त अवसंरचनाओं का अनुरक्षण और अन्य सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण का वित्त पोषण किया जा सकेगा. दिलचस्प बात तो यह है कि पिछले दशक में भारतीय वायु सेना के पूंजी परिव्यय बजट के उसके शेयर में 6 से 7 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि भारतीय थल सेना और जल सेना के शेयर में कुछ गिरावट आई है.

पड़ोस में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण और क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उदय होने के कारण भारत ने रक्षा के आधुनिकीकरण की एक विशाल योजना तैयार की है. स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (एसआईपीआरआई) द्वारा हाल ही में प्रकाशित अध्ययन में भारत को 2006 और 2010 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बताया गया है और उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए 80 बिलियन डॉलर का अनुमान लगाया है. पिछले दशक में 7 और 9 प्रतिशत के बीच सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वार्षिक वृद्धि के साथ और सैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से निवेश करने की सरकारी प्रतिबद्धता के कारण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अपने शेयर के रूप में भारत का व्यय 2.5 से 3 प्रतिशत तक अपेक्षाकृत स्थिर रहा है. इसके परिणामस्वरूप 2001 से भारत के रक्षा बजट में 64 प्रतिशत (वास्तविक अर्थों में) की वृद्धि हुई है और 2011–2012 बजट में यह राशि 36.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी और इसी कारण दीर्घकालीन अर्जन की योजनाओं का कार्यान्वयन भी संभव हो पाया है. इसलिए भारत के पास अपनी सेना को आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाने की इच्छा भी है और क्षमता भी. रक्षा के कुल बजट में से लगभग 40 प्रतिशत (अर्थात 14.5 बिलियन डॉलर) रक्षा पूंजी परिव्यय बजट के लिए आवंटित किया गया है, जिससे हथियारों की प्राप्ति, निर्माण और अधिष्ठापनों और अतिरिक्त अवसंरचनाओं का अनुरक्षण और अन्य सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण का वित्त पोषण किया जा सकेगा. दिलचस्प बात तो यह है कि पिछले दशक में भारतीय वायु सेना के पूंजी परिव्यय बजट के उसके शेयर में 6 से 7 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि भारतीय थल सेना और जल सेना के शेयर में कुछ गिरावट आई है. वर्तमान पूंजी परिव्यय बजट में शेयर का एक बड़ा हिस्सा 40 प्रतिशत वायु सेना को ही मिलता है, जबकि भारतीय थलसेना और जलसेना के क्रमशः 25 से 20 प्रतिशत हिस्सा ही मिलता है. शेष राशि रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान व विकास और सैन्य उत्पादन के तत्वों पर ख़र्च की जाती है.

परंतु अतीत के विपरीत भारत को आशा है कि सैन्य आधुनिकीकरण के वर्तमान प्रयास आयात पर बहुत हद तक निर्भर नहीं होंगे. जनवरी, 2011 में रक्षा मंत्री ने भारत की अब तक की पहली रक्षा उत्पादन नीति को अनावृत किया है. इस रक्षा उत्पादन नीति को सरकार और उद्योग जगत के विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेकर तैयार किया गया था. इनमें तटरक्षक, समन्वित रक्षा कर्मचारी और रक्षा अनुसंधान व रक्षा विकास संघ (डीआरडीओ) की तीनों सेवाएं, भारतीय उद्योग संगठन (आईएलए), भारतीय उद्योग संघ (सीएआई) और भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ (एफआईसीसीआई) शामिल थे.

घरेलू उद्योग आधारित रक्षा की क्षमता को बढ़ाने की इच्छा में दो बातें महत्वपूर्ण थीं. उद्योग के घरेलू रक्षा संबंधी क्षेत्रों को बढ़ावा देने की इच्छा और यह विश्वास कि अपनी रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना एक ऐसा संकेत है कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति है. और अतीत में इस बारे में किए गए प्रयासों के ठीक विपरीत हाल ही में जारी रक्षा उत्पादन नीति इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें संक्षेप में प्राप्ति संबंधी गूढ़ दस्तावेज़ों में इस आशय को छिपाकर रखने के बजाय घरेलू रक्षा के औद्योगिक आधार का समर्थन करने वाला रक्षा मंत्रालय का एजेंडा स्पष्ट रूप से झलकता है. इसके अलावा रक्षा उत्पादन नीति में देश के निजी क्षेत्र (लघु व मझौले आकार के उद्यम सहित) की भूमिका को और अधिक रेखांकित किया गया है और साथ ही देश के रक्षा अनुसंधान व विकास के आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया है.

घरेलू उद्योग आधारित रक्षा की क्षमता को बढ़ाने की इच्छा में दो बातें महत्वपूर्ण थीं. उद्योग के घरेलू रक्षा संबंधी क्षेत्रों को बढ़ावा देने की इच्छा और यह विश्वास कि अपनी रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना एक ऐसा संकेत है कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति है.

तत्काल प्रभाव से लागू इस रक्षा उत्पादन नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि इसमें प्राथमिकता रक्षा उपकरणों के देशी डिज़ाइन, विकास और विनिर्माण को ही दी जाएगी. उदाहरण के लिए केवल उन्हीं मामलों में विदेशी स्रोतों से प्राप्ति की जाएगी, जिनमें भारतीय उद्योग डिलीवरी करने की स्थिति में नहीं होंगे. विदेशी स्रोतों से प्राप्ति का निर्णय इस बात पर निर्भर होगा कि उपकरणों की कितनी शीघ्र आवश्यकता है और उपकरण की डिलीवरी में कितना समय लग सकता है. जिन मामलों में विदेशी स्रोतों के बारे में विचार किया जाएगा उनके बारे में रक्षा मंत्रालय सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी, संयुक्त वेंचर और कन्सोर्शिया का निर्माण जैसे अनेक मुद्दों को ध्यान में रखकर ही विचार करेगा. रक्षा उत्पादन नीति को लागू करने में भी भारत के नीति निर्माताओं और भारतीय उद्योग व अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के सामने अनेक चुनौतियां और अवसर हैं. भारत के रक्षा कर्मचारियों के सामने जो चुनौतियां हैं, वे इस प्रकार हैं– घरेलू औद्योगिक आधार से हमारी अपेक्षाएं क्या हैं? क्या भारत के पास अपेक्षित कार्यबल है? क्या रक्षा निवेश का स्तर इसकी अपेक्षाओं के अनुरूप है? घरेलू औद्योगिक आधार के निर्माण में भारत अन्य क्षेत्रों से क्या सीख सकता है? मुख्य अवसरों में निम्नलिखित शामिल हैं, औद्योगिक और राजनीतिक दृष्टि से अनूठी और नवोन्मेषकारी भागीदारी करने के अवसर का लाभ उठाना, अधिक उदार प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए समझौते करना और वैश्विक दृष्टि से रक्षा और सुरक्षा का प्रतियोगी औद्योगिक आधार तैयार करना. भारत के अंतरराष्ट्रीय भागीदारों, विशेषकर अमेरिका के लिए, जिसके लिए अपने रक्षा बजट में कटौती करना आवश्यक हो गया है. भारत का रक्षा बाज़ार बहुत आकर्षक होगा. परंतु जब भारत में व्यापार के अवसर बहुत बढ़ जाएंगे तो इन भागीदारों को सलाह दी जा सकती है कि वे भारत के रक्षा बाज़ार को एक ऐसी रणनीतिक भागीदारी के संदर्भ में देखें, जिसमें आतंकवाद के प्रतिरोध, समुद्री डोमेन की जागरूकता और अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता जैसे मुद्दों से जूझने के अवसर भी मिलेंगे. जैसे–जैसे रक्षा उत्पादन नीति लागू होती जाएगी, इसमें न केवल रक्षा कंपनियां होंगी, बल्कि एयरोस्पेस, सूचना प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षेत्र जैसे व्यापक क्षेत्र भी शामिल होंगे और अंतरराष्ट्रीय भागीदार उन्हें पहले से ही चिन्हित कर सकेंगे. भारत का रक्षा उत्पादन नीति संबंधी दस्तावेज़ इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसा एजेंडा तैयार किया है, जिससे रक्षा आधारित घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा रक्षा उत्पादन नीति के इस दस्तावेज़ में देश के निजी क्षेत्र (लघु व मझौले आकार के उद्यम सहित) को शामिल करने और साथ ही देश के रक्षा अनुसंधान व विकास के आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया है. भारत की रक्षा उत्पादन नीति का यह दस्तावेज़ भारत और उसके अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है. भारत के रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह नवोन्मेषकारी और रचनात्मक भागीदारी के समझौतों के प्रति अधिक ग्रहणशील होकर अपनी स्थिति को और मज़बूत बनाए और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को चाहिए कि वे देश में रक्षा और सुरक्षा के उदीयमान औद्योगिक आधार पर रणनीतिक रवैया अपनाते हुए उसका लाभ उठाएं.

भरत गोपालस्वामी और गाय बैन ऐरी
feedback@chauthiduniya.com

(भारत गोपालस्वामी कॉर्नेल विश्वविद्यालय में शांति व संघर्ष अध्ययन कार्यक्रम के रेपी संस्थान में स्कॉलर हैं. गाय बैन ऐरी रणनीतिक व अंतरराष्ट्रीय केंद्र में फ़ैलो हैं और इसके रक्षा औद्योगिक पहल समूह के उप निदेशक हैं.)

मेरी दुनिया.... प्रधानमंत्री जी और महंगाई!

सामुदायिक रेडियो

बदलाव का सशक्त माध्यम

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं से इतर संगठनों के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत जटिल है और उनके लिए आवश्यक है कि वे सामुदायिक रेडियो स्टेशन को ऑपरेशन बनाने से पहले कई मंत्रालयों की स्वीकृति प्राप्त करें. कुछ हद तक यह भी एक कारण है कि नीति की घोषणा के चार वर्षों के बाद भी सौ में से एक तिहाई रेडियो स्टेशन ही भारत में ज़मीन से जुड़े संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं और शेष कैंपस रेडियो हैं.

22 वर्षीय मंजुला पिछले वर्ष एक दिन अगस्त माह में रेडियो स्टेशन जा पहुंची और सुबह 5 बजे सुनामी के लिए सावधान रहने की घोषणा प्रसारित करने लगी. सवेरे रेडियो के श्रोता सकते में आ गए, क्योंकि वे इतने सवेरे तो आठ बजे से पहले शुरू होने वाले कलंजियम वानोली सामुदायिक रेडियो स्टेशन के प्रसारण सुनने के ही आदी थे. सुबह-सुबह ही तमिलनाडु और उसके आसपास के इलाक़े नागपत्तिनम में ज़िला प्रशासन ने सब कुछ ठीक-ठाक है अर्थात ऑल क्लीयर की सूचना प्रसारित की थी, लेकिन उस दिन मंजुला ने अपना काम असरदार ढंग से और बख़ूबी तौर पर कर दिया था. धन प्रतिष्ठान के सहयोग से यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन 2009 में नागपत्तिनम ज़िले के कीलैयूर ब्लॉक के एक छोटे से गांव विलुंतमवड़ी में शुरू किया गया था. यह गांव उस स्थान से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर है जहां 2004 में सुनामी ने ज़बरदस्त तबाही मचाई थी.

मध्य प्रदेश के ओरछा क़स्बे से हज़ारों किलोमीटर दूर अनुजा शुक्ला और उसके सहयोगी रेडियो बुंदेलखंड चलाते हैं. यह रेडियो 2008 से स्थानीय संदर्भों के अनुरूप सूचना और मनोरंजन का ज़बरदस्त मिलाजुला कार्यक्रम बुंदेली भाषा में प्रसारित कर रहा है. विकास अल्टरनेटिव्स द्वारा समर्थित सामुदायिक रेडियो स्टेशन बीस किलोमीटर के अर्धव्यास के दायरे में श्रोताओं तक पहुंचता है. इस प्रसारण में महिलाओं, युवाओं और सीमांत वर्ग के लोगों को विशेष रूप से संबोधित किया जाता है. एक नवोन्मेषकारी अभियान के दौरान इस स्टेशन ने बुंदेली में स्थानीय शौक़िया कलाकारों की मदद से स्थानीय आइडल नाम के एक शो के माध्यम से हज़ार से अधिक गीत रिकॉर्ड किए थे. यह शो अमेरिकन/इंडियन आइडल शो नाम के लोकप्रिय रियलिटी टी.वी. शो का बुंदेली संस्करण था.

यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन और आंध्र प्रदेश के मेदक ज़िले में डक्कन विकास संघ द्वारा शुरू किए गए संघम रेडियो भारत के मीडिया परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर रहे हैं. भारत में हवाई तरंगों की यह आंधी 2005 में एक सशक्त स्वर के रूप में उस समय उभरकर सामने आई, जब एफएम रेडियो की यह क्रांति महानगरों से आगे बढ़कर अनवरत बजने वाले फिल्मी गीतों और अक्सर होने वाली बकवास और गपशप के साथ लोगों की मीडिया उपभोग की आदतों पर दस्तक देने लगी. हालांकि इस स्थिति के कारण मल्टीपल आउटपुट और उपभोक्ता की पसंद के उदारवादी पूंजीवादी शब्दाडंबर के साथ अनायास ही कुछ प्रेक्षक उभर आए हैं, जिनके कारण बीस के दशक का बेर्टोल्ट ब्रेख्त का विलाप फिर से दोहराया जाने लगा है कि रेडियो एकाउस्टिकल डिपार्टमेंटल स्टोर के रूप में केवल वितरण प्रणाली बनकर रह गया है. उन्होंने रेडियो को दोतरफ़ा संवाद का माध्यम बनाने के लिए सचमुच कुछ लोकतांत्रिक बनाने की वकालत की, ताकि इससे सार्वजनिक मामलों में नागरिकों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके. भारत में सामुदायिक रेडियो के लिए संघर्ष का इतिहास इसी ब्रेख्तियन सिद्धांत को मूर्त रूप देने का एक प्रयास है, जिसकी परिणति नवंबर, 2006 में भारत सरकार की इस नई नीति में हुई कि देश में सुदृढ़ नागरिक समाज के निर्माण के साधन के रूप में सामुदायिक रेडियो का उपयोग किया जा सकता है.

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में मीडिया उद्योगों के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने विषयवस्तु के समांगीकरण, सत्ता और नियंत्रण के केंद्रीकरण और ग़रीबों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हाशिए पर लाने के प्रयासों को बढ़ाने और मुख्यधारा के मीडिया को डिसफ्रेंचाइज़ करने से संबंधित सरोकारों को बढ़ा दिया है. रेडियो के स्पैक्ट्रम को मुक्त करने की लड़ाई प्रमुख मीडिया के लिए विकल्प प्रदान करने और सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सत्ता से च्युत सामाजिक कारकों के व्यापक स्पैक्ट्रम को अभिव्यक्ति के साधनों के रूप में विकसित करने के लिए रही है. अन्य लोकतांत्रिक देशों के अनुभवों और नीतिगत उदाहरणों को देखते हुए सामुदायिक रेडियो के कार्यकर्ताओं ने अपील की है कि भारत में प्रसारण सार्वभौमिक पहुंच, संसाधनों के समान वितरण, संचार के लोकतंत्रीकरण और समाज के ऐतिहासिक दृष्टि से नुक़सान में रहे वर्गों के सशक्तीकरण के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए.

फरवरी, 1995 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यह व्यवस्था दी थी कि हवाई लहरें सार्वजनिक संपत्ति हैं और इनका उपयोग आम लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए. इस निर्णय में यह भी कहा गया था कि प्रसारण मीडिया को समग्र रूप में अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना चाहिए. इसलिए आवश्यक है कि प्रसारण मीडिया को सरकारी एकाधिकार से मुक्त होना चाहिए और इसके विषय का नियंत्रण सार्वजनिक निकाय के विनियमों के अधीन होना चाहिए. इस निर्णय के बाद ही भारतीय सामुदायिक रेडियो के प्रचारकों ने स्थानीय लोगों द्वारा ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाक़ों में स्वाधिकृत और चलाए जाने वाले लाभकारी रेडियो स्टेशनों के नए रूप के निर्माण के लिए लगभग एक दशक तक संघर्ष किया, ताकि हाशिए पर आए समुदायों के सामाजिक परिवर्तन, सामंजस्य और समावेश के लिए तथा रचनात्मक व सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए अवसर जुटाए जा सकें. सामाजिक क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो के प्रसारण के लिए इस तरह की वकालत के सघन प्रयासों और गरमा-गरम बहस की परिणति 2006 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा समावेशी सामुदायिक रेडियो नीति के अनुमोदन के रूप में हुई.

सामुदायिक रेडियो स्टेशन और आंध्र प्रदेश के मेदक ज़िले में डक्कन विकास संघ द्वारा शुरू किए गए संघम रेडियो भारत के मीडिया परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर रहे हैं. भारत में हवाई तरंगों की यह आंधी 2005 में एक सशक्त स्वर के रूप में उस समय उभरकर सामने आई, जब एफएम रेडियो की यह क्रांति महानगरों से आगे बढ़कर अनवरत बजने वाले फिल्मी गीतों और अक्सर होने वाली बकवास और गपशप के साथ लोगों की मीडिया उपभोग की आदतों पर दस्तक देने लगी. हालांकि इस स्थिति के कारण मल्टीपल आउटपुट और उपभोक्ता की पसंद के उदारवादी पूंजीवादी शब्दाडंबर के साथ अनायास ही कुछ प्रेक्षक उभर आए हैं, जिनके कारण बीस के दशक का बेर्टोल्ट ब्रेख्त का विलाप फिर से दोहराया जाने लगा है कि रेडियो एकाउस्टिकल डिपार्टमेंटल स्टोर के रूप में केवल वितरण प्रणाली बनकर रह गया है.

जब 1999 में एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसियों को सबसे ऊंची बोली बोलने वालों को नीलाम करने से संबंधित हवाई तरंगों का एकाधिकार समाप्त करने की नीति कार्यान्वित की गई तो इस अभियान के प्रचारकों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय की भारत सरकार की ओरवेलियन व्याख्या पर ही संतोष करना पड़ा. इस अपरिहार्य प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने हवाई तरंगों को भारत के शहरी परिदृश्य में व्यवसायिक खिलाड़ियों के लिए बेहद सरल और संभव बना दिया. जैसे ही हवाई तरंगें सरकारी नियंत्रण से मुक्त हुईं, वैसे ही भारत के रेडियो में अनेक प्रकार के परिवर्तन होने लगे. परंतु सामाजिक क्षेत्र सूना ही रह गया और अपने रेडियो का सपना देखने वाले ग्रामीण क्षेत्र की आवाज़ को सुनने में किसी को दिलचस्पी न रही. देश में तीन स्तरीय स्वतंत्र और अलाभकारी प्रसारण की एक अरसे से चली आ रही मांगों के फलस्वरूप आरंभ में 2003 की पहली तिमाही में सामुदायिक रेडियो का सीमित कैंपस अवतार सामने आया.

इसके कारण प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं ने एफएम ट्रांसमीटर लगाना और रेडियो स्टेशन चलाना शुरू कर दिया. इस निर्णय के कारण राज्य की चौधराहट कुछ हद तक कम हुई और रेडियो पर मार्केटिंग शुरू हुई. लेकिन शहरी और शिक्षित भद्रलोक के लिए ऐसे इलाक़े में जहां मीडिया पहले से ही जमा हुआ हो, प्रसारण क्षेत्र के खुलने से सामुदायिक रेडियो अभियान की मूल भावना को ही क्षति पहुंची. सरकार बहुत समय तक इस अनावश्यक आशंका के कारण कि अलगाववादी, आतंकवादी और विनाशक तत्व इस माध्यम का दुरुपयोग कर सकते हैं, इस क्षेत्र में प्रसारण क्षेत्र खोलने के प्रस्ताव को टालती रही, कांग्रेसनीत यूपीए की केंद्र सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी (मनरेगा) अधिनियम जैसी ग़रीब समर्थक नीतियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए सामुदायिक रेडियो की वास्तविक मांग को अंततः मान लिया. 2006 से नई विस्तारित नीति के कारण पहले से भली-भांति सामुदायिक विकास कार्यों में संलग्न ग़ैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दे दी गई. इस समुदाय को स्वामित्व और प्रबंधन का अधिकार देने के साथ-साथ नीति में यह व्यवस्था भी की गई कि कम से कम 50 प्रतिशत विषयवस्तु स्थानीय भाषा में उनके समुदाय की सहभागिता के साथ होनी चाहिए. नई नीति के मौजूदा ढांचे में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को समाचार और सामयिक विषयों को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी गई.

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं से इतर संगठनों के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत जटिल है और उनके लिए आवश्यक है कि वे सामुदायिक रेडियो स्टेशन को ऑपरेशन बनाने से पहले कई मंत्रालयों की स्वीकृति प्राप्त करें. कुछ हद तक यह भी एक कारण है कि नीति की घोषणा के चार वर्षों के बाद भी सौ में से एक तिहाई रेडियो स्टेशन ही भारत में ज़मीन से जुड़े संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं और शेष कैंपस रेडियो हैं. इस उदीयमान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सामुदायिक रेडियो मंच जैसे समूह अधिक उदार लाइसेंसिंग कार्याविधि के लिए सामुदायिक रेडियो सहायता निधि द्वारा सार्वजनिक वित्त के सृजन की प्रक्रिया चलाने के लिए सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ काम कर रहा है.

इस बीच जनरल नरसम्मा और उनकी सहयोग एल्गोल नरसम्मा नाम की दो दलित महिलाएं, जो संघम रेडियो चलाती हैं, अपने यरंदला मुचातलु नाम के तेलुगू शो से दर्शकों का मनोरंजन करती हैं. इस शो में दो ननदों के गपशप भरे संवादों की मिमिक्री के माध्यम से वे अपने समुदाय में सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती हैं.

विनोद पावराला
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस के डीन और भारतीय सामुदायिक रेडियो मंच के अध्यक्ष हैं.)

कभी-कभी ये योजनाएं निष्फल भी हो जाती हैं, पर फिर भी चूंकि आप अपना भोजन बचाकर रख नहीं सकते. आपको तो ख़र्च करना ही है.

हाल फ़िलहाल में अमेरिकी राजनीतिक चिंतक पॉल ब्रास ने चौधरी चरण सिंह की जीवनी भारतीय राजनीतिक जीवन: चरण सिंह और कांग्रेस राजनीति 1937 से 1961 तक नामक पुस्तक लिखी है.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

फ़ालतू धन की माया

ज़मीन या मकान ही ऐसी निजी संपत्ति नहीं थी जिसकी आय पर आदमी बिना कुछ करे घर बैठे खाता-पीता रहे. किराये के धन से भी कहीं ज़्यादा जो फ़ालतू धन लोगों के पास पड़ा है, उसका किराया पूंजीवादियों की दूसरी निजी संपत्ति है. फ़ालतू धन के किराये को हम ब्याज के नाम से पुकारते हैं.

कोई भी व्यक्ति अपने खाने-पीने, पहनने या रहने के ख़र्च से ज़्यादा कमाता है, तो वह कुछ बचा ही सकता है. पहले कहा जा चुका है कि असल धन रोटी, कपड़ा इत्यादि बचाकर रखा नहीं जा सकता. दूसरा धन है-सोना, चांदी, रुपये, नोट इत्यादि. ये सभी चीज़ें हैं, जो बचाई नहीं जा सकतीं. इनका मूल्य तब तक है, जब तक इनसे आप जीवन की आवश्यक सामग्री ख़रीद सकते हैं. अगर किसी कारणवश आप अपने रुपयों से या नोटों से दो सेर आटा न ख़रीद सकें तो फिर यह सब इकट्ठी की हुई या बचाई हुई रक़म किस काम की? सोना-चांदी ऐसी धातु हैं जिनकी क़ीमत शताब्दियों से कम-बेशी चली आ रही है. पर फिर भी इसको बचाकर रखा तो नहीं जा सकता. पूंजीवाद के सिद्धांत के अनुसार जिसके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामग्री है, वह उसे ख़र्च नहीं करता, बचाकर रख नहीं सकता, तो फिर क्या करे? वह उसे दूसरे किसी भी व्यक्ति को, जिसे उसकी इस वक़्त ज़रूरत है, उधार दे देता है और उसका कुछ किराया हर साल या हर माह लेता रहता है. इस तरह से पूंजीवादी लोग ज़मीन या मकान के किराये के अलावा अपनी पूंजी का किराया भी वसूल करते हैं और यह सारी कमाई बिना श्रम किए अनार्जित आय कहलाती है. आपके पास मान लीजिए, थोड़ी बची हुई फ़ालतू रक़म है. उसे आप बचाकर रख नहीं सकते, क्योंकि अभी जितनी वह है शायद 10 साल बाद, 10 महीने बाद या 10 मिनट बाद भी उतनी न रहे. कारण स्पष्ट है, पिछले 20 सालों से जो रक़म का मूल्य ह्रास हुआ है या जो कहें आवश्यक वस्तुओं की महंगाई आई है, उसे देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि रक़म का जो मूल्य आज है वही बाद में भी रहेगा. इसलिए रक़म को तुरंत ख़र्च कर देना आवश्यक है. ख़र्च करके आप उपार्जन करते रहें- ऐसी तरकीब से ख़र्च करने को निवेश या लागत पूंजी कहते हैं.

लागत पूंजी के विभिन्न रूप

आप भोजन कर चुके, उसके बाद भी अगर आपके पास भोजन बच जाए और वह भोजन आप किसी भूखे आदमी को दे दें जिस पर आप किसी कारणवश भरोसा करते हों कि वह एक साल बाद आपका वैसा ही उतना भोजन लौटा देगा, तो कह सकते हैं कि आपने अपना रुपया उसी वक़्त ख़र्च भी कर दिया और एक साल के लिए बचा भी लिया. यूं कहें कि आपके पास जो ताज़ा भोजन था, वह आपने खा भी लिया और अगले साल में ताज़ा भोजन खा सकने की व्यवस्था भी कर ली.

आप तुरंत ही कह देंगे कि भोजन खाने वाले लाखों आदमी मिल जाएंगे, पर भरोसे का पात्र मिल सकना मुश्किल है कि साल भर बाद वह हमको भोजन खिला सके. भरोसा कैसे किया जाए? आज जो ख़ुद भूखे हैं, साल भर बाद वे अपने लिए भी कुछ जुटा पाएंगे कि नहीं, इसमें ही शंका है. हमें हमारा भोजन लौटाना दूर की बात है. इस कठिनाई का एक हल है. जो भूखे आदमी हैं उनमें से तो आप शायद भरोसा-पात्र नहीं पा सकें, पर आपके बैंक या आपके शेयरों के दलाल या आपके वकील ज़रूर ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ देंगे जिनका भरोसा किया जा सकता है और बहुधा वे व्यक्ति काफ़ी धनी होंगे.

आप कहेंगे कि अगर वे धनी हैं तो उन्हें बचे हुए भोजन की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी? हां, उनका ख़ुद का तो पेट इतना भरा हुआ है कि उन्हें अपने लिए भोजन बिलकुल नहीं चाहिए, पर उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में भोजन की आवश्यकता रहती है. क्योंकि वह भोजन उन भूखे आदमियों को खिलाना ज़रूरी है, जिनका विश्वास या भरोसा नहीं किया जा सकता कि अगले साल वे भोजन लौटा देंगे. वे भी उनका भरोसा नहीं करते. पर वे उन भूखों से भोजन के बदले कुछ काम करा लेते हैं, जो उनको बाद में रुपये प्राप्त करा देता है. कोई भी बुद्धिमान या प्रतिभाशाली व्यक्ति आसानी से यह व्यापार कर सकता है.

मान लीजिए देहात में आपका एक बड़ा खेत है और जो सड़क उसके पास से जाती है वह बड़ी ऊबड़-खाबड़ भूमि से गुज़रती है. अब आप उन लोगों से जिनको आप भोजन देते हैं, एक काम करवाते हैं कि वे आपके खेत के बीच से अच्छी सड़क बना डालें. सड़क बना लेने के बाद वे आदमी कोई दूसरा काम ढूंढें और किसी दूसरे व्यक्ति से भोजन प्राप्त करें.

आपने अपनी उस सड़क से आने-जाने वालों से कुछ कर या फीस लेना शुरू कर दिया. मान लीजिए अगर राहगीरों की संख्या बहुत है तो आप थोड़े ही दिनों में काफ़ी रुपया जमा कर लेंगे. जो रुपया या धन इस तरह से आपके पास इकट्ठा होगा, उससे भी उसी तरह से बचे हुए भोजन के रूप में आप भूखों को काम के एवज में भोजन करा देंगे और लीजिए उसी सड़क के आसपास कई मकान आप बनवा लें, उन मकानों को आप किराये पर दे दें, तो जो किराया इकट्ठा होगा उससे उसी तरह से फिर बचे हुए भोजन के रूप में आप अन्य भूखों को भोजन कराएंगे और अन्य दूसरे काम उनसे करवाते रहेंगे. इसी तरह आप मकान, फैक्ट्री, कारख़ाने बनवा लेंगे. हज़ारों आदमियों को फैक्ट्रियों में काम पर लगाकर और बदले में वही बचा हुआ भोजन देते जाएंगे. ज्यों-ज्यों काम करते जाएंगे त्यों-त्यों बचे हुए भोजन की मात्रा आपके पास बढ़ती ही चली जाएगी. इस तरह बचे हुए भोजन से आप अनेकानेक काम करवाते ही रहेंगे और इस व्यापार का अंत ही नहीं होगा.

इसी बचे हुए भोजन को आप अपने शेयर दलाल या बैंक के मार्फ़त जिस व्यक्ति को दे देते हैं वही तो पूंजीवादी उद्योगपति है और जो आप देते हैं, वही तो शेयर-कैपिटल है, जिससे कंपनियों के कारोबार चलते हैं. कभी-कभी ये योजनाएं निष्फल भी हो जाती हैं, पर फिर भी चूंकि आप अपना भोजन बचाकर रख नहीं सकते. आपको तो ख़र्च करना ही है. जिस पर भरोसा कर सकते हों, उसे देना ही है तो यह ख़तरा आपको उठाना ही पड़ेगा. हमेशा बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए या उनकी कंपनियों के लिए बचा हुआ भोजन या शेयर कैपिटल प्राप्त होता ही रहता है. इसी तरह अजीब तरीक़े से वे बड़े धनिक आदमी निरंतर अधिक धनवान होते चले जाते हैं. देखते-देखते दुकानें, कारख़ाने, रेलवे, खानें, स्टीमर, अट्टालिकाएं, महल, टेलीफोन, हवाई जहाज़, मोटरें इत्यादि अनेक चीज़ें खड़ी हो जाती हैं.

इस बचत किए हुए भोजन का यह विस्तार इस तरह से जादू का सा काम करता है. बहुत से वे आलसी आदमी जिनके पास ज़मीन जायदाद है, पूंजी है, वे अत्यधिक धनवान हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कि वे कैसे करोड़पति बन गए. उनके बच्चे जन्मते ही लखपति बन जाते हैं. जबकि वे मज़दूर या किसान जो यह सब करने में सहायक होते हैं या जिनके श्रम से यह सब हो पाता है, वे उसी भूख को मिटाने में उसी तरह काम की तलाश में भटकते फिरते हैं. वे अब भी वैसे ही दरिद्र रहते हैं जैसे पहले थे.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

कमल मोरारका का ब्लॉग

www.kamalmorarka.com

प्रधानमंत्री जी, चुप रहने का वक़्त नहीं है

सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत हुए जस्टिस काटजू को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. पहले से ही यह शिकायत थी कि प्रेस काउंसिल एकदम कमज़ोर संस्था है और इसके पास अधिकार इतने कम हैं कि इसका प्रेस पर कोई नियंत्रण नहीं है. जस्टिस काटजू ने दो सच बातें कह दीं तो लोग उछल पड़े. उन्होंने कहा कि आजकल के संवाददाता, पत्रकार और प्रेस में काम करने वाले लोगों का स्तर काफ़ी गिर गया है. वे उस बौद्धिक स्तर के नहीं हैं, जिसकी पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है. अब इसमें ग़लत क्या है? चार पूंजीपति जो पब्लिशर हैं और उनके जो नुमांइदे हैं प्रेस काउंसिल में, वॉक आउट कर गए. दरअसल, जब काटजू अपने बयान को सही बताते हुए उस पर क़ायम रहे तब वे वॉक आउट कर गए. क्यों वॉक आउट कर गए? शायद शर्म के मारे वॉक आउट किया होगा. क्योंकि वे जानते हैं कि वे ऐसे लोगों के साथ अख़बार चला रहे हैं, जो जर्नलिस्ट होने के क़ाबिल ही नहीं हैं. जर्नलिज्म के लिए मापदंड होना चाहिए. कोई भी सिर्फ़ बीए या एमए होने से जर्नलिस्ट होने का अधिकारी नहीं हो जाता.

इसके लिए उसके पास पत्रकारिता के लिए आवश्यक योग्यता भी होनी चाहिए. जस्टिस काटजू ने तो बहुत मामूली बातें कही हैं और ये लोग इसी पर नाराज़ हो गए. जस्टिस काटजू ने दूसरी बात यह कही कि जब प्रेस काउंसिल बना था, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था ही नहीं. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इसके दायरे में रखना चाहिए. वे लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं. यह तो हास्यास्पद बात है. मैं प्रेस नियंत्रण के ख़िलाफ़ हूं. प्रिंट मीडिया रहेगी दायरे में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं रहेगी. ऐसा क्यों? यह तो जनभावना को ज़्यादा प्रभावित करता है. यह कहना कि हर अख़बार वाला, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला पाक-साफ़ है. उसका दामन साफ़ है. यह तो सही नहीं है. फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात तो संविधान में है ही नहीं. फ्रीडम ऑफ स्पीच है. लेकिन उस अधिकार को आपने एक्स्टेंड कर दिया. एक पूंजीपति अख़बार वाला अपने मुलाज़िमों के माध्यम से एक लाख कॉपी छपवा कर किसी का चरित्र हनन कर देगा. उस आदमी के पास क्या बचाव है? कोर्ट में जाना. सब जानते हैं, इंडिया में डिफेमेशन लॉ कितना कमज़ोर है. 20 साल तक तो सुनवाई नहीं होगी उसकी यानी उसका चरित्र गया. यह अधिकार प्रेस को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं होना चाहिए. इसलिए ज़रूरी है कि एक मज़बूत प्रेस कांउसिल हो. ज़रूरी नहीं कि आप जस्टिस काटजू के बयान से सहमत हों. यह उनकी निजी राय है. लेकिन प्रेस कांउसिल एक प्रभावशाली संस्था हो, इसमें क्या मतभेद हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके दायरे में आए, इसमें क्या मतभेद हो सकता है. मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि दो टूक बात की जानी चाहिए. जिसे दो टूक बात करनी चाहिए, उसकी दो टूक बात सुनने की आदत चली गई है. सब घुमा-फिराकर बात करते हैं और नतीजा कुछ नहीं होता है. ये 2जी और अन्य घोटाले, सब इसी के परिणाम हैं. इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है. प्रधानमंत्री जी, अपनी चुप्पी तोड़ें और इस मामले में हस्तक्षेप करें.

दूसरी तरफ़ इस बात की चर्चा है कि किंगफिशर एयरलाइंस बहुत घाटे में है, उसको बचाने की कोशिशें जारी हैं और सरकार अपने बैंकों द्वारा कुछ न कुछ रियायत देना चाहती है. लेकिन प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर को बचाने के लिए टैक्स पेयर का पैसा लगाना ग़लत है. जो प्राइवेट सेक्टर नहीं चल पा रहे हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए. यह बात तो अपनी जगह है. लेकिन इससे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि एयर इंडिया जो शत-प्रतिशत सरकार की संस्था है, चार महीने से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है. सिर्फ़ पायलट ही नहीं अन्य कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिल पा रहा है. यह तो बहुत निंदनीय है. प्राइवेट सेक्टर को ऐसा अधिकार नहीं है. अगर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिलता है तो वे लेबर कमिश्नर के पास जा सकते हैं. निजी क्षेत्र को धन की समस्या हो सकती है, लेकिन सरकार के साथ तो ऐसी समस्या नहीं है. सरकार पैसा निकालकर दे या फिर बैंकों को कहे उनको लोन दें, लेकिन वेतन देने में अगर एक दिन का भी विलंब होता है तो यह साज़िश मानी जाएगी कि सरकार चाहती है कि सरकारी कारख़ाने बंद हो जाएं और उन्हीं पैसों से प्राइवेट कारख़ानों को बचाया जाए. यह उदारीकरण की नीति 1991 से शुरू हुई है. यह 20 सालों में किस हद तक चली गई, प्रधानमंत्री को इस पर ग़ौर करना चाहिए. इसके साथ ही उनको सबसे पहले एयर इंडिया के कर्मचारियों का तीन-चार महीने का बक़ाया वेतन चुका देना चाहिए. साथ ही कर्मचारियों को हर महीने 30 तारीख़ को वेतन देने की व्यवस्था करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी को भी अपना उद्यम या उद्योग बंद करने का अधिकार है, लेकिन चालू रखकर वेतन न देने का अधिकार नहीं है. एयर इंडिया को बंद करना है तो सरकार हिम्मत कर के तय करे. एयर इंडिया चालू भी रखेंगे, पायलटों और इंजीनियरों आदि से काम भी लेंगे, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं देंगे. यह बिलकुल क्षमा करने लायक़ अपराध नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

लड़कियां घर में भी सुरक्षित नहीं

देश में आज भी सम्मान के नाम पर महिलाओं की हत्याएं की जा रही हैं. यह विडंबना ही है कि एक ओर भारतीय समाज में देवियों की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है. आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं जब परिवार वालों ने सम्मान के नाम पर अपनी ही बहन या बेटी की हत्या कर दी. इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज भी लड़कियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है. उन्हें आज भी दोयम दर्जे का माना जाता है. लड़कियां अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं.

–**शुभा शिवम,** *वाराणसी, उत्तर प्रदेश*

ग़रीबों से मज़ाक़

चौथी दुनिया में ग़रीबों का मज़ाक़ मत उड़ाइए, पढ़ा. सरकार ने ग़रीबी रेखा का जो पैमाना लागू किया एवं योजना आयोग ने तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को मंज़ूरी दे दी, जिसमें शहरों में 32 रुपये और गांवों में 26 रुपये प्रतिदिन पर जीने वालों को ग़रीबी रेखा से बाहर करने की सिफ़ारिश की गई है. वास्तव में ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वालों की पहचान आसान नहीं है. यह भी देखने में आया है कि बहुत सारे ग़रीबों के नाम बीपीएल सूची में नहीं हैं, जबकि अमीरों के नाम इसमें शामिल हैं. तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देश में सिर्फ़ 37 प्रतिशत लोग ग़रीब हैं, जबकि अर्जुनसेन गुप्ता की रिपोर्ट कहती है कि देश में 77 प्रतिशत लोग ग़रीब हैं. सरकार को उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के चश्मे को उतार कर ग़रीबों की संख्या के बारे में जानना होगा.

–**शंकर शर्मा,** *बेगूसराय, बिहार*

राह से भटकता आंदोलन

किसी भी जन आंदोलन केलिए सदैव ही यह समस्या रहती है कि वह अपने मूल उद्देश्य से न भटके और अपनी मर्यादा में रहे. अन्ना के आंदोलन से लोगों में एक आस जगी थी, लेकिन टीम अन्ना के कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण यह आंदोलन अपनी राह से भटक गया है. बात चाहे हिसार उप-चुनाव में एक पार्टी विशेष का खुलेआम विरोध करने की हो या फिर कश्मीर पर प्रशांत भूषण का विवादस्पद बयान हो या फिर आपसी तू-तू मैं-मैं, सभी ने आंदोलन केलिए बिखराव का धरातल तैयार किया. ऐसे में सवाल उठाना लाज़िमी है कि अवाम अब करे तो क्या करे.

–**हर्षवर्धन कुमार,** *पटना, बिहार*

मिलावटख़ोरी बंद हो

चौथी दुनिया में नक़ली घी का कारोबार पढ़ा. आज अधिकतर व्यापारियों का मक़सद मुनाफ़ाख़ोरी ही हो गया है. उनका अपनी सेवा या गुणवत्ता से कोई सरोकार नहीं रह गया है. अब लोग ब्रांडेड वस्तुएं ही ख़रीदने पर ज़ोर दे रहे हैं. सरकार को चाहिए कि वह मिलावटख़ोरों के प्रति सख्ती बरते, ताकि लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सकें.

–**चंद्रकांत यादव,** *चंदौली, उत्तर प्रदेश*

मीडिया की शानदार मुहिम

चौथी दुनिया सिर्फ़ एक साप्ताहिक अख़बार ही नहीं, बल्कि समूचे देश की समस्याओं पर एक गहन विचार है. प्रिंट मीडिया की एक ऐसी शानदार मुहिम है, जो पूरे देश की जनता को जागरूक करती है. वैसे आजकल हमारे जीवन को राजनीति, क्रिकेट और सिनेमा ने सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रखा है. चौथी दुनिया का हर आलेख सोचने को विवश करता है. इतना ही नहीं इससे जीवन की बहुत सी समस्याओं को सुलझाने का रास्ता मिल जाता है.

सीताराम शर्मा, *गांव भूमा बड़ा, सीकर, राजस्थान*

अन्ना का नुक़सान

चौथी दुनिया की आवरण कथा संघ ने अन्ना का सबसे बड़ा नुक़सान किया. इस बात का सबूत है कि राजनीति को हमेशा अच्छाई से दुश्मनी रही है. अन्ना ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया तो राजनीति इसके पीछे पड़ गई. भाजपा से जुड़ा होने के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी राजनीति की झलक मिलती है. इस तरह संघ के नेताओं ने भी अन्ना को नुक़सान ही पहुंचाया.

–**रविकांत शर्मा,** *हुबली, पश्चिम बंगाल*

युवाओं की भूमिका

भारत गांवों का देश है और देश की आत्मा गांवों में बसती है. महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर देश को मज़बूत बनाना है तो गांवों को मज़बूत करना होगा. गांव का अपना अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र है. इसे कभी नहीं भूलना चाहिए. एक ज़माने में गांव काफ़ी समृद्ध और ख़ुशहाल थे, लेकिन आज़ादी के बाद की सरकारों की नीतियों से गांवों का जितना भला होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया. ऐसे में जब देश की आधी आबादी युवाओं की है तो देश के नवनिर्माण में उनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है.

–**सिकंदर आज़ाद वक़्त,** राजाजान, खगड़िया, बिहार

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

अन्ना ने एक अच्छा मौक़ा गंवा दिया

अन्ना हजारे पर चारों तरफ़ से हमला हो रहा है. एक तरफ़ राजनीतिज्ञ हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ़ मीडिया हमला कर रहा है. राजनीतिज्ञ दो तरह से हमले कर रहे हैं. पहला हमला उनकी छवि को बिगाड़ने का हो रहा है, जिसका नेतृत्व श्री दिग्विजय सिंह कर रहे हैं. और दूसरा हमला उनकी छवि को भुनाने का हो रहा है, जिसका नेतृत्व श्री मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं. दोनों ही लोग अन्ना हजारे को देश के राजनीतिक परिदृश्य से ख़त्म कर देना चाहते हैं. शायद अन्ना हजारे इस लायक़ हैं भी. जो आदमी वहां चूक करे, जहां देश के भविष्य की बात हो, तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए. अन्ना हजारे ने ख़ुद कोई प्रयास नहीं किया और न ही उनके साथियों ने प्रयास किया कि देश की जनता उनके साथ जुड़े. उन्होंने एक सही मुद्दा चुना और देश के लोगों को लगा कि हां, यही वह व्यक्ति है, जो उनके सपनों को साकार करने की दिशा में कम से कम एक क़दम चल सकता है. उसका कोई स्वार्थ नहीं. लोगों ने अन्ना में गांधी, जयप्रकाश और लोहिया की छवि देखी. इसलिए सारे देश के वे लोग जो तकलीफ़ में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वे नौजवान जिनके सामने भविष्य नहीं है, वे औरतें जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर हमेशा चिंतित रहती हैं. सभी लोग चाहे वे उत्तर के रहने वाले हों या पूरब के हों, पश्चिम के हों या दक्षिण के हों, अन्ना हजारे के पक्ष में लामबंद हो गए. अन्ना हजारे को यह पता भी नहीं है कि जिन दिनों उन्होंने उपवास किया या अनशन किया, उस दौरान देश में हज़ारों लोगों ने अनशन किया. मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, जो अनशन करते हुए मृत्यु के दरवाज़े तक पहुंच गए थे. उनमें शहडोल के श्याम बहादुर नम्र एक नाम है, जिन्हें पुलिस ने उनके अनशन के 12वें दिन गिरफ़्तार किया. उसके एक दिन बाद अन्ना हजारे का अनशन टूटा. मैं इसलिए कह रहा हूं कि अन्ना हजारे इसी व्यवहार के लायक़ हैं, क्योंकि अन्ना हजारे को जो करना चाहिए था, उन्होंने वह नहीं किया. अन्ना हजारे को यह समझना चाहिए, जब लोगों की आकांक्षाएं, लोगों के सपने किसी बात से जुड़ते हैं तो फिर व्यक्तिगत फ़ैसले के दायरे में अपने क़दम का निर्धारण करना, लोगों के साथ छल करना है. अन्ना हजारे की मांग के समर्थन में सारा देश खड़ा हुआ, लेकिन देश जन लोकपाल के अलावा भी बहुत सारे सवालों पर खड़ा हुआ. उसे लगा कि चलो एक मुद्दा यह मिला. पर एक आदमी शायद बाक़ी मुद्दों को भी सामने लेकर आए और देश को असली लोकतंत्र के दायरे में ले जाने की कोशिश करे. इसलिए बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, अमीर-ग़रीब हर जाति के लोगों ने अन्ना हजारे को समर्थन दिया. हो सकता है, राजनीतिक दलों के लोग उनके साथ खड़े हुए हों, पर कोई भी अपना झंडा लेकर खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाया. भारतीय जनता पार्टी के नेता शिव पुरोहित जब अपनी पार्टी का झंडा लेकर आज़ाद मैदान में अन्ना हजारे का समर्थन करने पहुंचे तो अन्ना के लोगों ने उनको वापस कर दिया. अगर बिना झंडे के कोई गया तो वह इस देश के नागरिक की हैसियत से गया. जो भी बिना झंडे के देश के नागरिक होने की हैसियत से गया, उसका स्वागत होना चाहिए. हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अन्ना के आंदोलन में थे. अन्ना इस ताक़त को नहीं पहचान पाए. अन्ना हजारे अगर इस ताक़त को पहचानते तो वह इतने बीमार नहीं थे कि वह चल फिर नहीं सकते थे. वह नरेश त्रेहान के अस्पताल से निकले और हवाई जहाज़ और कार में बैठकर अपने गांव पहुंचे. गांव से वैसे ही वह वापस आ सकते थे. देश की उन तमाम जगहों पर जा सकते थे, जहां के लोगों ने सारे ख़तरे उठाकर अपने काम को रोका और अपना निस्वार्थ समर्थन अन्ना हजारे को दिया. अन्ना हजारे ने सोचा, अब तो ये लोग खड़े ही हो गए हैं हमारे पक्ष में. हम जब आवाज़ देंगे, तब लोग फिर खड़े हो जाएंगे. अन्ना हजारे यह भूल गए कि जनता का उभार, अगर उसमें विश्वास का जामन न डाला जाए तो फिर विश्वास दूध ही दूध रहता है, दही नहीं बन पाता. दूध ख़राब हो जाता है थोड़े दिनों के बाद. विश्वास का जामन अन्ना हजारे ने लोगों के मन में नहीं डाला. डालने का एक ही तरीक़ा था कि वह देश में हर जगह जाते. उत्तर से शुरू करते, दक्षिण से शुरू करते, कहीं से भी शुरू करते. लेकिन लोगों के बीच जाकर यह कहते कि यह मेरा आंदोलन है, आप मेरे साथ रहिए. अगर अन्ना हजारे यह करते तो, न उनके ख़िलाफ़ दिग्विजय सिंह की रणनीति सफल हो पाती, न मोहन भागवत की उनके श्रेय को छीनने की और न ही अन्ना के चेहरे पर कोई नक़ाब चढ़ाने की कोशिश सफल हो पाती.

अन्ना हजारे के पास आख़िरी मौक़ा बचा है. अगर वह सोचेंगे कि जब चाहें देश में निकलेंगे और लोगों का समर्थन उन्हें मिल जाएगा, जो शायद मुमकिन नहीं. अगर वह तीन या चार महीने के बाद निकलते हैं, तो बहुत देर हो चुकी होगी. तब वह उन लोगों को एक वाजिब तर्क दे देंगे, जिनका लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है. जो या तो तानाशाह हैं या अतिवादी हैं.

दूसरी तरफ़ मीडिया, जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर न केवल बड़े पैसे वालों से निर्देशित होता है, चूंकि वे मालिक हैं, बल्कि अख़बार वालों में बहुत सारे ऐसे हैं, जो राजनीतिक दलों के नेताओं के हमप्याला, हमनिवाला हैं. वे अपने राजनीतिक मित्रों को उपकृत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ये सारे लोग अन्ना पर हमला कर रहे हैं और अन्ना के साथी परेशान हैं. उनका कहना है कि यह तो हमने कहा ही नहीं. ये हमले हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं. शायद ये हमले नहीं हो पाते. अरविंद केजरीवाल से मेरी बात हो रही थी. उन्हें बहुत दुख था कि न उनका किरण बेदी से कोई झगड़ा है और न ही किसी और से कोई विवाद है, लेकिन लोग उनको एरोगेंट क्यों कह रहे हैं? रोज़-रोज़ उन्हें नए विभूषण क्यों दिए जा रहे हैं? विशेषण क्यों दिए जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की समझ में मुश्किल से आएगा कि इनका जवाब क्या है. इनका एक ही जवाब था, जो उन्होंने नहीं दिया, और एक ही जवाब है, जो वह अगर चाहें तो दे सकते हैं. अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, मनीष सिसौदिया या किसी और के लोगों के बीच जाने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि लोगों ने उन्हें विश्वास नहीं दिया था, समर्थन नहीं दिया था. लोगों ने अन्ना हजारे को समर्थन दिया था. अन्ना हजारे बीमार ही सही. कुर्सी पर ही बैठकर अगर देश में घूमते हैं और सिर्फ़ हाथ हिलाते हैं तो चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा. साथ ही उस समय मीडिया के वे लोग जो अन्ना हजारे की छवि धूमिल कर रहे हैं या राजनीतिक दलों के लोग, जो येन-केन-प्रकारेण उन्हें राजनीतिक प्रदृश्य से ग़ायब करना चाहते हैं, वे सारे लोग मुंह की खाएंगे और फिर उनकी हिम्मत अन्ना हजारे का विरोध करने की नहीं होगी.

गांधी के ज़माने में अंग्रेजों के दलाल कम नहीं थे, लेकिन देश में उनकी कोई नहीं सुनता था. बड़े-बड़े अख़बारों में गांधी के ख़िलाफ़ अभियान चलता था, लेकिन लोग उनकी नहीं सुनते थे, गांधी की सुनते थे. जयप्रकाश नारायण के ज़माने में उनके ऊपर हमला होता था, लेकिन लोग जयप्रकाश की बात को ही सही मानते थे. गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया और देश को आज़ाद सरकार दी. जयप्रकाश ने देश से कांग्रेस की सरकार हटाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहली ग़ैर कांग्रेसी सरकार दी. तीसरा आंदोलन विश्वनाथ प्रताप सिंह का था. वीपी सिंह ने जनता को साथ लिया. उन पर भी बहुत हमले हुए, लेकिन उन्होंने भी ग़ैर कांग्रेसी सरकार इतिहास में दूसरी बार देश को दी. अब यह उन सरकारों को चलाने वालों की नालायक़ी थी, जो जनहित के अपने एजेंडे को पूरा नहीं कर पाए और राजनेताओं की छवि सत्ता के लिए लड़ने-झगड़ने वालों की बन गई. जनता में यह संदेश गया कि उन्हें सरकार चलानी नहीं आती. इन दोनों से ज़्यादा भरोसा लोगों ने अन्ना हजारे को दिया. उन्हें चाहिए था कि लोगों के भरोसे को और मजबूत करने के लिए वह देश भर में घूमते. वह देखते कि इस देश में किस तरह नए परिवर्तन की संभावना उन्होंने पैदा कर दी है. पर अन्ना हजारे ने यह नहीं किया. इसलिए आज वह ऐसे आरोप झेल रहे हैं, जिसे लेकर वह और उनके साथी तिलमिला रहे हैं. आज भी अगर अन्ना हजारे और उनके साथी देश में, देश के सवालों को लेकर घूमना शुरू करें तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. उनके साथी अकेले नहीं घूमें, क्योंकि उनमें से किसी को यह हक़ नहीं है कि वे जनता से कहें कि तुम ऐसा करो. क्योंकि उनका सार्वजनिक जीवन में उतना योगदान नहीं है, जिस योगदान की बदौलत लोग उनके साथ खड़े हों. वे लोग अन्ना के साथ जुड़कर ही बड़ा काम कर सकते हैं. अगर ये अन्ना हजारे की बायीं तरफ़ खड़े होंगे तो शून्य माने जाएंगे और अगर अन्ना हजारे की दायीं तरफ़ खड़े होंगे तो उनकी संख्या सौ, हज़ार, दस हज़ार, एक लाख, दस लाख, दस करोड़ हो जाएगी. क्योंकि एक अंक के दाहिनी तरफ़ लगे हुए शून्य ही कोई मतलब रखते हैं, बायीं तरफ़ लगे शून्य कोई मतलब नहीं रखते. अन्ना हजारे के पास आख़िरी मौक़ा बचा है. अगर वह सोचेंगे कि जब चाहें देश में निकलेंगे और लोगों का समर्थन उन्हें मिल जाएगा, जो शायद मुमकिन नहीं. अगर वह तीन या चार महीने के बाद निकलते हैं, तो बहुत देर हो चुकी होगी. तब वह उन लोगों को एक वाजिब तर्क दे देंगे, जिनका लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है. जो या तो तानाशाह हैं या अतिवादी हैं. ऐसे लोग कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने वाले न तो आंदोलन चलाना जानते हैं और न ही सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को मानती है. इसलिए हमें ग़ैर संवैधानिक और हिंसक आंदोलन चलाने चाहिए. अन्ना हजारे एक बात क्यों भूल जाते हैं कि शेर की सवारी का एक ही मूल्य है. या तो शेर की पीठ पर बैठकर आप रास्ता पार कर जाएंगे या शेर आपको गिराकर खा जाएगा. हमारी कामना है कि अन्ना हजारे शेर की पीठ पर बैठकर सवारी करते हुए दिखाई दें, न कि शेर उन्हें गिराकर खा जाए. अब यह अन्ना हजारे के ऊपर है कि वह शेर को साधते हैं या फिर शेर का शिकार बनते हैं.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

सत्ता का दुरुपयोग रोकना होगा

क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं है कि गुजरात के दो विधायक अहमदाबाद के पास उत्पात मचाते हुए पाए गए. जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो वे हिंसा पर उतारू हो गए. इसकी ख़बर जब नरेंद्र मोदी तक पहुंची तो वह पुलिस स्टेशन गए तथा विधायकों को गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों को डांट लगाई और विधायकों को छुड़ाया. क्या यह क़ानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं है. क्या गुजरात में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए? ऊपर का वाक़िया ग़लत नहीं है, लेकिन यह घटना अहमदाबाद की नहीं, बल्कि कोलकाता की थी और नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि दीदी ने ऐसा दुर्व्यवहार किया था. क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि कितनी तेज़ी से सत्ता भ्रष्ट होती जा रही है. ऐसी स्थिति में जनता और पुलिस को किस तरह से आश्वासन दिया जा सकता है. साथ ही पश्चिम बंगाल की पुलिस को ऐसे स्वेच्छाचारी व्यवहार से कैसे बचाया जा सकता है. क्या इसी को परिवर्तन कहा जाता है?

अमेरिकी राजनीतिक चिंतक पॉल ब्रास ने चौधरी चरण सिंह की जीवनी भारतीय राजनीतिक जीवन: चरण सिंह और कांग्रेस राजनीति 1937 से 1961 तक नामक पुस्तक लिखी है. यह चौधरी चरण सिंह पर उनके द्वारा लिखी जा रही पुस्तक का पहला खंड है. इसमें इस बात का ज़िक्र है कि 1946 में भी सत्ता में वैसे ही भ्रष्टाचार था जैसा कि आजकल है. इसमें ब्रास ने राम मनोहर लोहिया के माध्यम से भ्रष्टाचार की बात लिखी है.

अगर देखा जाए तो सत्ता का दुरुपयोग उस भ्रष्टाचार से ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसमें पैसे लिए जाते हैं. भारत में यह बात विचार करने योग्य है कि यहां सत्ता में बैठे लोग अनियंत्रित हैं. उनकी शक्तियों पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं है जैसा कि अन्य कई देशों में है. ऐसी ही एक घटना ब्रिटेन की है, जब गृह सचिव थेरेसा मेय ने अपने पासपोर्ट और वीजा के सिलसिले में अपने निर्देशों का पालन न करने के कारण एक अधिकारी को निलंबित कर दिया. इसके बाद उस अधिकारी ने इस्तीफ़ा दे दिया और संघ की सहायता से मेय के ऊपर अभियोग चलाया. इसके बाद मेय को गृह मामलों के प्रवर समिति के समक्ष उपस्थित होना पड़ा. ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें मेय को भी इस्तीफ़ा देना पड़ सकता था. अब इसकी तुलना अगर पश्चिम बंगाल की घटना से करें तो कितना दुख होता है. ममता बनर्जी के इस व्यवहार की निंदा नहीं की जाएगी. न तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में और न ही लोकसभा में इस पर कोई प्रश्न उठाया जाएगा. इससे वे पुलिस वाले जिन्होंने क़ानून का पालन किया हतोत्साहित होंगे. यही नहीं उनके बीच यह संदेश जाएगा कि वे क़ानून का पालन करने के लिए नहीं हैं, बल्कि मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस के विधायकों यहां तक कि उनके सगे-संबंधियों के आदेशों का पालन करने के लिए हैं. इसी तरह सत्ता में फैला भ्रष्टाचार नीचे तक फैलता जाता है और शक्तिशाली लोग हत्या जैसे अपराध करके भी क़ानून के शिकंजे से निकल जाते हैं.

हाल फ़िलहाल में अमेरिकी राजनीतिक चिंतक पॉल ब्रास ने चौधरी चरण सिंह की जीवनी भारतीय राजनीतिक जीवन: चरण सिंह और कांग्रेस राजनीति 1937 से 1961 तक नामक पुस्तक लिखी है. यह चौधरी चरण सिंह पर उनके द्वारा लिखी जा रही पुस्तक का पहला खंड है. इसमें इस बात का ज़िक्र है कि 1946 में भी सत्ता में वैसा ही भ्रष्टाचार था जैसा कि आजकल है. इसमें ब्रास ने राम मनोहर लोहिया के माध्यम से भ्रष्टाचार की बात लिखी है. उन्होंने लिखा है कि एक बार जवाहर लाल नेहरु ने लोहिया से कहा था कि किस तरह कांग्रेस के लोगों का पतन हो रहा है. वे एक-दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं और इस झगड़े में भारतीय क़ानून संहिता की हर धारा की अवहेलना करते हैं. ग़ौर करने वाली बात है कि 1946 से पहले कांग्रेस के नेता स्वतंत्रता सेनानी थे, वे इसके बाद सत्ता में आ गए थे. इससे तो यही समझा जा सकता है कि जितनी अधिक ताक़त किसी के पास आती है, उतना ही वह भ्रष्ट हो सकता है. ऐसी स्थिति में अगर कोई ईमानदार है तो उसे फंसाना कोई मुश्किल काम नहीं है. चौधरी चरण सिंह एक ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन वह हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि उनके सहयोगी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं. समय के साथ-साथ सत्ता के दुरुपयोग की क्षमता बढ़ती गई, साथ ही भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया. जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को विभाजित किया और अपनी पार्टी बनाई तो उनकी पार्टी में ऐसा कोई नहीं था, जो उन्हें नियंत्रित कर सके. इसके साथ ही सत्ता का दुरुपयोग भी बढ़ता गया और जब कांग्रेस का सत्ता से एकाधिकार समाप्त हो गया तो अन्य दलों को भी अपनी ताक़त के दुरुपयोग का मौक़ा मिल गया. इस तरह से भ्रष्टाचार का दायरा बढ़ता ही गया. अब ऐसी स्थिति में यह कहना सही नहीं होगा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकपाल की आवश्यकता है. इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता में बैठे लोगों की ताक़त को नियंत्रित किया जाए. जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री पुलिस को उसका कार्य करने से न रोके तो किसी लोकपाल की ज़रूरत ही नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

मरीज़ से कहा जाएगा कि वह इस ई नाक में सांस छोड़े. उपकरण में लगे सेंसर टीबी के अंदेशे को भांप लेंगे. इसके नतीजे एकदम मिलेंगे और काफ़ी हद तक सटीक भी.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 28 नवंबर–04 दिसंबर 2011

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

घूस का जवाब आरटीआई

घूस का जवाब आरटीआई. चौंकिए मत. यही इलाज है भ्रष्ट और रिश्वतख़ोर कर्मचारियों का जो आपसे किसी भी काम के बदले घूस की मांग करते हैं. हर आम या ख़ास आदमी का पाला कभी न कभी, किसी न किसी सरकारी विभाग से पड़ता ही है. चाहे वह राशन कार्ड बनवाने के लिए हो या पासपोर्ट बनवाने का काम. आप चाहे शहर में रहते हों या गांव में, सरकारी बाबुओं की फाइल दबाने और फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग से आप सभी का सामना ज़रूर हुआ होगा. गांवों में वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुज़ुर्गों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है. शहरों में भी लोगों को आयु/जन्म–मृत्यु/आवास प्रमाण पत्र बनवाने या इनकम टैक्स रिफंड लेने में नाकों चने

चबाने पड़ते हैं. ऊपर से, काम करवाने के लिए घूस भी देनी पड़ती है. अब सवाल यह है कि जो आदमी रिश्वत देने की स्थिति में नहीं है तो क्या उसका काम नहीं होगा. ऐसा नहीं है. काम ज़रूर होगा. वह भी बिना रिश्वत दिए. ज़रूरत है सिर्फ़ अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की. और वह अधिकार है, सूचना का अधिकार. यह अधिकार एक क़ानून है. महज़ एक आवेदन देकर आप घूसखोर अधिकारियों की नींद हराम कर सकते हैं. यह आज़माया और सफल नुस्ख़ा है. जैसे ही आप अपने रुके हुए काम से संबंधित एक आरटीआई आवेदन डालते हैं. भ्रष्ट और रिश्वतख़ोर अधिकारियों और बाबुओं की समझ में आ जाता है कि जिसे वह परेशान कर रहा है वह आम आदमी तो है, लेकिन अपने अधिकारों और नियमों के प्रति जागरूक भी है. तय मानिए, सरकारी विभागों में भी आमतौर पर उन्हीं लोगों को ज़्यादा परेशान किया जाता है जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है. सूचना क़ानून में इतनी ताक़त है कि छोटे–मोटे काम तो आवेदन देने के साथ ही हो जाते हैं. इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, बजाय घूस देकर काम कराने के. चौथी दुनिया, आपके हर क़दम पर आपका साथ देने को तैयार है. कोई भी समस्या हो, कोई सुझाव चाहिए या आप अपना अनुभव हमसे बांटना चाहते हों तो हमें पत्र लिखें या ई–मेल करें. हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

किसी भी सरकारी विभाग में रुके हुए काम

(राशन कार्ड, पासपोर्ट, वृद्धावस्था पेंशन, आयु–जन्म–मृत्यु–आवास प्रमाण पत्र बनवाने या इंकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी होने, रिश्वत मांगने या बिना वजह परेशान करने की स्थिति में निम्न प्रश्नों केआधार पर सूचना के अधिकार का आवेदन तैयार)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना केअधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
मैंने आपके विभाग में .... तारीख़ को .... के लिए आवेदन किया था. (आवेदन की प्रति संलग्न है) लेकिन अब तक मेरे आवेदन पर संतोषजनक क़दम नहीं उठाया गया है.
कृपया इसके संदर्भ में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं

1. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्रवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. मेरा आवेदन किन–किन अधिकारियों के पास गया तथा किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा और इस दौरान उन अधिकारियों ने उस पर क्या कार्रवाई की? पूरा विवरण उपलब्ध कराएं.
2. विभाग के नियम के अनुसार मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए थी? क्या मेरे मामले में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया है?
3. कृपया उन अधिकारियों के नाम तथा पद बताएं जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्रवाई करनी थी? लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.
4. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी? यह कार्रवाई कब तक की जाएगी?
5. अब मेरा काम कब तक पूरा होगा?
(कुछ अतिरिक्त प्रश्न: यदि आवश्यक हो)
6. कृपया मुझे सभी आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत की सूची उपलब्ध कराएं जो मेरे आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत के जमा करने के बाद जमा की गई है. सूची में निम्नलिखित सूचनाएं होनी चाहिए :–
   1.आवेदक/करदाता/याचिकाकर्ता/पीड़ित का नाम
   2. रसीद संख्या
   3. आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत की तारीख़
   4. कार्रवाई की तारीख़
7. कृपया रिकॉर्ड के उस हिस्से की छाया प्रति दें, जो उपरोक्त आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत की रसीद का ब्यौरा रखते हों?
8. मेरे आवेदन के बाद यदि किसी आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत को नंबर आने से पहले कार्यान्वित किया गया हो तो उसका कारण बताएं?
9. इस आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत के नंबर आने से पहले कार्यान्वयन केमामले में, यदि कोई हो तो, सतर्क पूछताछ कब तक की जाएगी?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा हूं.

भवदीय
नाम ....
पता ....

ज़रा हट के

इलेक्ट्रॉनिक नाक और टीबी

इसे टीबी के मरीज़ों के लिए अच्छी ख़बर कहा जा सकता है. असल में भारतीय वैज्ञानिकों का दावा है कि वे एक इलेक्ट्रॉनिक नाक बना रहे हैं जिससे सांस का परीक्षण किया जाएगा और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का तुरंत पता लगाया जा सकेगा. इस तेज़ जांच से कई हज़ार ज़िंदगियां बचाई जा सकेंगी. ई नोज यानी इलेक्ट्रॉनिक नाक बैटरी से चलेगी और बहुत छोटा सा उपकरण होगा. ठीक उसी तरह का जैसे पुलिस सांस में अल्कोहोल की मात्रा जांचने के लिए रखती है. मरीज़ से कहा जाएगा कि वह इस ई नाक में सांस छोड़े. उपकरण में लगे सेंसर टीबी के अंदेशे को भांप लेंगे. इसके नतीजे एकदम मिलेंगे और काफ़ी हद तक सटीक भी. ई नाक नई दिल्ली के जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी अंतरराष्ट्रीय सेंटर और कैलिफोर्निया की नेक्स्ट डाइमेंशन टेक्नोलॉजी का साझा प्रयास है. दुनिया भर में हर साल टीबी या क्षय रोग के कारण 17 लाख लोगों की मौत हो जाती है और शोधकर्ताओं का मानना है कि ई नोज के कारण विकासशील देशों में सालाना कम से कम चार लाख लोगों की ज़िंदगियां बच जाएंगी, क्योंकि क्षय रोग जल्दी पकड़ में आ जाएगा और इसलिए इलाज भी वक़्त से होगा.

अभी हाल में इस प्रोजेक्ट को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा की ओर से साढ़े नौ लाख डॉलर की मदद मिली है. वैज्ञानिकों के मुताबिक़, हमारा शोध दिखाता है कि नई तकनीक की मदद से दूसरी बीमारियों जैसे फेफड़ों के कैंसर और न्यूमोनिया जैसी बीमारियों का भी जल्दी पता लग सकता है. ई नोज की क़ीमत 20 से 30 डॉलर होगी. छोटे आकार और बैटरी से चलने के कारण यह गांवों में भी आसानी से इस्तेमाल की जा सकेगी. ऐसे इलाक़ों में भी जहां बिजली की समस्या है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक़, भारत में सबसे ज़्यादा टीबी का संक्रमण है और वहां हर रोज़ एक हज़ार लोग क्षय रोग के संक्रमण का शिकार होते हैं. नंदा ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक नाक ग़रीब और दूर–दराज़ के इलाक़ों में उपलब्ध करवाई जाए, जहां अक्सर ट्यूबरकुलोसिस के बहुत मामले सामने आते हैं और जानलेवा बन जाते हैं. इस अजीबो–ग़रीज ई नोज से टीबी का इलाज वाक़ई दिलचस्प है.

अब गैंडों की बारी

टाइगर की घटती संख्याओं से तो सब वाक़िफ़ हैं. लेकिन अब बारी सफ़ेद गैडों की है. बात भारत की नहीं मध्य अफ़्रीका की है. जी हां, अब मध्य अफ़्रीका के सफ़ेद गैंडे भी ख़ात्मे की कगार पर हैं. अफ़्रीका के अलावा वियतनाम में जावन गैंडे भी क़रीबन लुप्त हो चुके हैं. संस्था का कहना है, गैंडों की पनाहगाहों को बचाने के लिए ज़रूरी राजनीतिक समर्थन और इच्छाशक्ति की कमी है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े आपराधिक संगठन ग़ैर क़ानूनी मांग और सींगों के लिए गैंडों का शिकार कर रहे हैं. पैसे के लिए हो रहा शिकार गैंडों के सामने सबसे बड़ा ख़तरा है. यह तस्वीर सिर्फ़ गैंडों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ख़राब है. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक़, एक चौथाई स्तनधारी जानवर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. विज्ञान और संरक्षण की बदौलत कुछ ही प्रजातियों को किसी तरह बचाया जा रहा है. इसका अच्छा उदाहरण दक्षिण अफ़्रीका के सफ़ेद गैंडे हैं. 19वीं सदी के अंत तक सिर्फ़ 100 गैंडे बचे थे, लेकिन संरक्षण की कोशिशों के चलते अब इनकी संख्या 20,000 पहुंच गई है. मध्य एशिया के लुप्तप्राय जंगली घोड़ों को भी संरक्षण की बदौलत वापस बसाया जा सका. लेकिन अब भी जीव जंतुओं और पौधों की 62,000 प्रजातियां ख़तरे की लाल सूची में हैं. आशंका है कि अगर जल्दी संरक्षण की कोशिशें नहीं की गईं तो सात अरब इंसानों की दुनिया को कई जीव और पौधे हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे. सोचने वाली बात है कि नहीं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह के आरंभ में कुछ अटकलें लग जाने से योजनाएं निष्क्रिय हो सकती हैं. सप्ताह के मध्य में आपको सभी कार्यक्रमों को स्थगित करके अपने आर्थिक क्षेत्र को सफल बनाने में जुट जाना चाहिए. काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद सप्ताहांत तक कुछ अच्छे परिणाम मिलने की आशा रहेगी.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह के आरंभ में बौद्धिक और धार्मिक कर्म भी सफल होगा. काफ़ी मेहनत और प्रयास करने के बावजूद इस सप्ताह के मध्य में आपके फ़ायदे कम और नुक़सान अधिक रहेंगे. जिस वांछित धन की आप आशा लगाकर बैठे हैं वह अभी आपके हाथ में आने से रह जाएगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह के आरंभ में लाभ की प्राप्ति से प्रसन्नता रहेगी. आपको अपने मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि आपके सभी रुके हुए काम अचानक ही पूरे हो जाएंगे. सप्ताह मध्य तक कारोबार या काम–धंधे में आपकी पहुंच गहरी होगी.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह के आरंभ में आप सुनी–सुनाई बातों पर यक़ीन कर गृह कलह को जन्म दे सकते हैं. यदि आप युवा या विद्यार्थी वर्ग से संबंध रखते हों तो यह सप्ताह आपके एजुकेशन और प्रोफेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. आपको अपने पूर्व नियोजित कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में मदद मिलेगी.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह के आरंभ में निकट –दूर की यात्राएं मार्ग प्रशस्त करेंगी. आपको अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद मिलेगी. कुछ अतिरिक्त काम का बोझ जो पिछले काफ़ी समय से आपके लिए सरदर्द बना हुआ था. इस सप्ताह कम हो जाएगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
इस सप्ताह के आरंभ में आपको सुख– समृद्धि मिलेगी. आपके मन की मुराद पूरी होगी. काफ़ी समय से अटका हुआ कोई अच्छा काम आपके लिए लाभदायक संदेश ला सकता है. सप्ताहांत में अपनी मनोदशा पर ज़्यादा चिंतित नहीं हों.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह के आरंभ में उत्तम प्रकार का रहन–सहन वातावरण तैयार होगा. अतः घर से निकलने से पहले ही अपने सभी ज़रूरी सामान को संभाल कर रख लें. सप्ताह मध्य में किसी सामान के गुम हो जाने या लुप्त हो जाने का अंदेशा रहेगा.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह के आरंभ में परिस्थितियां एकाएक जटिल हो सकती हैं. आपको अपने अटके हुए काम पूरे करने में काफ़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा. आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परिस्थितियों में सामूहिक तौर पर संघर्ष कर रहे हैं.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह के आरंभ में मित्रों से मिलाप हेतु यात्रा आयोजन के प्रसंग प्रबल होंगे. अगर आप थोड़ा बहुत भी हाथ–पांव मारेंगे या परिश्रम करेंगे , तो तत्काल ही फ़ायदा हो सकता है. राजकीय पक्ष से कोई अच्छी ख़बर या संदेश पत्र आपको मिल सकता है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह के आरंभ में आपके छोटे–मोटे प्रयास से ही कुछ अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं. जिस काम को आप काफ़ी समय से पूरा नहीं कर पा रहे थे, वही कार्य सप्ताह मध्य तक अचानक ही बनता हुआ नज़र आएगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह के आरंभ में आपको अपने जनसंपर्क और उच्चस्तर के शुभचिंतकों का लाभ मिलेगा. यदि आप घर से किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो अच्छे से तैयार होकर जाएं.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस सप्ताह के आरंभ में कुछ शारीरिक और मानसिक विकार भी तनाव पैदा कर रहे हैं. इस सप्ताह के मध्य आपको अपने विरोधियों और आलोचकों का भी सामना करना पड़ सकता है. यदि आप काफ़ी समय से कार्यहीन या बेरोज़गार हैं तो आपको अपने लिए किसी नए काम की तलाश करनी होगी.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

इटली की आर्थिक समस्याएं अल्पकाल में ठीक नहीं होने वाली हैं. निवेशकों को इस बात का भरोसा चाहिए कि इटली अपने सभी पिछले क़र्ज़ चुका पाएगा.

भारत-मालदीव

बेहतर संबंध बनाने की क़वायद

राजीव कुमार

हिंद महासागर में अपनी स्थिति मज़बूत करने और दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने पड़ोसियों को विश्वास में ले. मालदीव के साथ हाल में हुआ समझौता इसी दिशा में उठाया गया एक अच्छा क़दम माना जा सकता है. दक्षेस की बैठक में भाग लेने गए भारतीय प्रधानमंत्री ने मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंध को मज़बूत करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उससे भारत को सामरिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर लाभ होगा. दोनों देशों ने विकास के लिए व्यवस्थागत समझौते और आतंकवाद से लड़ने में आपसी सहयोग सहित छह समझौते किए. विकास समझौते के तहत मालदीव की राजकोषीय स्थिति को स्थिरता प्रदान करने के लिए भारत उसे 10 करोड़ डॉलर की वैकल्पिक सुविधा देगा. भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि दस करोड़ डॉलर का यह क़र्ज़ एक वर्ष पहले मालदीव में 500 घरों के निर्माण के लिए घोषित 4 करोड़ डॉलर के क़र्ज़ के अतिरिक्त होगा. दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में व्यापार और निवेश, खाद्य सुरक्षा, मत्स्य विकास, पर्यटन, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा, संचार और वायु तथा समुद्री मार्गों के ज़रिये संपर्क बढ़ाने में आपसी सहयोग की योजना का ख़ाका है. इसके अलावा मनमोहन सिंह ने 200 बिस्तरों वाले इंदिरा गांधी स्मृति अस्पताल के जीर्णोद्धार की भी घोषणा की है. भारत मई 2013 तक इस अस्पताल को सुविधा संपन्न बनाकर मालदीव को सौंप देगा. दोनों देशों ने कोच्ची और माले के बीच एक यात्री व माल परिवहन सेवा प्रारंभ करने के प्रस्ताव में तेज़ी लाने का भी निर्णय लिया है. इसके साथ-साथ माले के उत्तर में एक बंदरगाह विकसित करने के मुद्दे पर भी बात की गई. इस बंदरगाह को विकसित करने में भारत सहयोग देगा. हिंद महासागर की समुद्री डाकुओं से सुरक्षा में मालदीव की महत्वपूर्ण भूमिका है. मालदीव की समुद्री सुरक्षा संबंधी क्षमता में विस्तार के लिए भारत ने वहां नेशनल पुलिस एकेडमी बनाने में सहयोग देने की भी घोषणा की है. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत के साथ हुए इन समझौते से दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती आने की बात कही है. उन्होंने भारत द्वारा की गई आर्थिक सहयोग की घोषणा को अपने देश के आर्थिक विकास को गति देने वाला बताया है तथा कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच के आर्थिक संबंधों को एक नया आधार मिलेगा.

वैसे भारत और मालदीव के बीच शुरू से ही अच्छे संबंध रहे हैं. भारत हमेशा से उपनिवेशवाद का विरोध करता रहा है और अपनी आज़ादी के बाद उपनिवेशवाद विरोधी प्रयास को इसने तेज़ कर दिया था. 1966 में ब्रिटिश गुलामी से मालदीव की मुक्ति में भारत के प्रयासों का भी योगदान रहा है. दोनों देशों ने 1976 में समुद्री सीमा का निर्धारण किया था एवं 1981 में कंप्रिहेंसिव ट्रेड अग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए हैं. मालदीव और भारत दोनों ही सार्क के संस्थापक सदस्य हैं. 1988 में जब पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के कुछ आतंकवादियों ने मालदीव पर हमला किया था तो मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने भारत से ही सहायता मांगी थी. भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर आतंकियों के मंसूबों को नाकामयाब कर दिया था. लेकिन कुछ समय से चीन ने मालदीव में अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं. वह मालदीव में कई परियोजनाएं चला रहा है. मालदीव के द्वीपों को विकसित करने तथा उसके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का विस्तार करने में उसकी अभिरुचि बढ़ती जा रही है. हाल में चीन ने इस देश में अपना दूतावास भी खोला है. चीन हिंद महासागर में अपनी स्थिति मज़बूत करने के लिए तथा भारत की घेरेबंदी के लिए पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ-साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका आदि देशों में अपनी उपस्थिति बढ़ा चुका है. सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोणों से यह भारत के प्रतिकूल है. भारत ने भी इन देशों के साथ संबंध मज़बूत करने का प्रयास किया है. मालदीव के साथ भारत ने रक्षा संबंध मज़बूत किए हैं. अगस्त 2009 में रक्षा मंत्री एके एंटनी के मालदीव दौरे के बाद से भारतीय जंगी जहाज़ और डॉर्नियर विमान समुद्री गश्त और सर्विलांस में मालदीव की मदद कर रहे हैं. इसके अलावा भारत इस देश के 26 द्वीपों पर ग्राउंड राडार नेटवर्क स्थापित करने और उन्हें भारतीय सेना के सर्विलांस सिस्टम से जोड़ने में इसकी मदद कर रहा है. इससे पूर्व भी भारत ने हाइड्रोग्राफिक सर्वे और अन्य सैनिक सहायता मालदीव को दी है. भारत ने 260 फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस चिल्लांचांग भी मालदीव को दिया है. भारत की इस सहायता का फ़ायदा मालदीव को मिला है. लेकिन हर देश की अपनी समस्याएं होती हैं. अगर भारत मालदीव को एकतरफ़ा रियायत नहीं देगा और उसे आर्थिक सहायता नहीं देगा तो धीरे-धीरे वह चीन के नज़दीक जा सकता है. और एक बार अगर चीन यहां सैनिक बेस बना लेता है तो फिर भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी. एक तो भारत का व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध होगा और दूसरा यह सामरिक तौर पर भी कमज़ोर हो जाएगा. ऐसे ही चीन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा उत्तर में समस्याएं खड़ी कर रहा है. आए दिन सीमा उल्लंघन के समाचार आते रहते हैं. अगर भारत के दक्षिण में भी वह अपनी स्थिति मज़बूत कर लेगा तो हमारे लिए समस्याएं और बढ़ जाएंगी. इसलिए मालदीव के साथ मज़बूत सामरिक गठबंधन चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्यावश्यक हैं. भारत ने जो पहल की है उससे चीन की बौखलाहट बढ़ेगी तथा वह मालदीव को अपने विश्वास में लेने के प्रयासों में तीव्रता लाएगा. अब भारत के समक्ष चुनौती इस बात की है कि वह किस तरह चीन के मंसूबों पर पानी फेरता है तथा मालदीव के साथ अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

बेआबरू होकर बर्लुस्कोनी का जाना

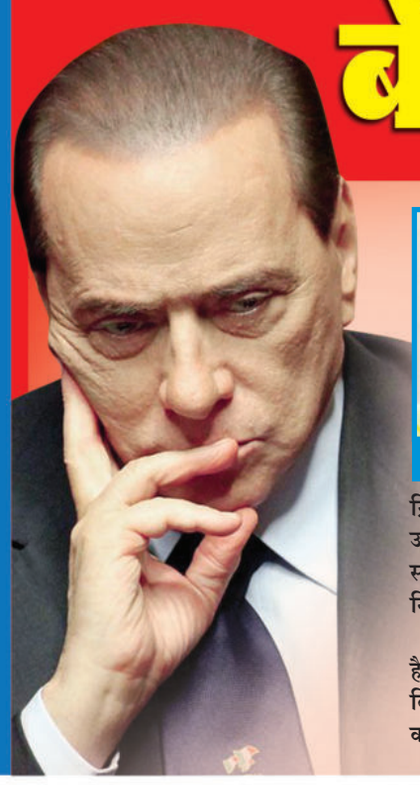

राजीव रंजन तिवारी

कई मसलों पर उदाहरण स्वरूप एक पुरानी कहावत कही जाती है– रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था. यह जुमला इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी पर कुछ ज़्यादा ही फिट बैठता है. वरना, शायद इतने बेआबरू होकर उन्हें सत्ता के गलियारे से नहीं जाना पड़ता. बर्लुस्कोनी जब राष्ट्रपति निवास पर इस्तीफ़ा देने गए थे तो वहां हज़ारों लोगों की भीड़ ने उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए व अपशब्द कहे. लोगों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसमें सबसे विनम्र शब्द डाकुओं का सरगना और मसख़रा था. इस्तीफ़ा सौंपने के बाद प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए वह साइड के एक रास्ते से निकल गए. ख़ैर, बर्लुस्कोनी ने कुर्सी छोड़ दी है.

क़रीब 17 वर्षों से इटली की राजनीति पर बर्लुस्कोनी का दबदबा रहा है. पिछले कुछ समय से विभिन्न घोटालों में उनका नाम आने से उनकी छवि बिगड़ गई थी. बर्लुस्कोनी द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से इटली में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे. उन्होंने संसद में बहुमत गंवाने के बाद घोषणा की थी कि अगर कटौती प्रस्ताव को संसद के दोनों सदन पारित कर देते हैं तो वह इस्तीफ़ा दे देंगे. बर्लुस्कोनी की जगह मारियो मॉन्टी प्रधानमंत्री बन गए हैं. वह एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं. नए प्रधानमंत्री पर नई आर्थिक कटौतियों को लागू करने की ज़िम्मेदारी होगी, ताकि इटली के क़र्ज़ संकट से निपटा जा सके. नए प्रधानमंत्री और नई योजना दोनों को ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, इटली की मौजूदा आर्थिक संकट की स्थिति यह है कि दस वर्ष के इतालवी बॉन्ड कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है. इसके लिए इटली से निवेशक सात प्रतिशत ब्याज़ मांग रहे हैं, जो अपने यूरोपीय संघ के गठन के बाद से अब तक का रिकॉर्ड है. मामले की गंभीरता इसी से समझ में आती है कि ऐसे ही बॉन्ड के लिए जर्मनी सिर्फ़ डेढ़ प्रतिशत ब्याज़ देता है. इटली की अर्थव्यवस्था उसी स्तर पर पहुंच गई है जहां ग्रीस की अर्थव्यवस्था है, जबकि यूरोपीय संघ की भारी आर्थिक सहायता के बिना उसे दिवालिया होने से बचाना मुश्किल है. इटली को अपने पिछले क़र्ज़ों की क़िस्ते चुकाने के लिए और क़र्ज़ चाहिए, जबकि कोई भी इटली को नए क़र्ज़ देने को तैयार नहीं है सिवाय इसके कि उन्हें मिलने वाला ब्याज़ बहुत ऊंचा हो. अब यह इटली के हिसाब से बहुत ही मारक स्थिति है, क्योंकि अगर ऊंचे ब्याज़ दर पर नया क़र्ज़ लिया गया तो क़र्ज़ की क़िस्तें कम होने के बदले बढ़ जाएंगी. बैंकों को डर है कि अगर इटली अपने क़र्ज़ चुका नहीं पाया तो उनका पैसा डूब जाएगा. इटली का सरकारी ख़र्च काफ़ी अधिक है, जबकि उसकी विकास दर बहुत धीमी है. फ्रांस और जर्मनी के बाद इटली यूरोज़ोन की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था है. उसे डूबने से बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह आसान नहीं है. इटली को वर्ष 2012 में 360 अरब यूरो बाज़ार से उधार लेने हैं, ताकि वह अपने पिछले क़र्ज़ चुका सके और डिफाल्टर होने से बच सके.

बताते हैं कि इटली की आर्थिक समस्याएं अल्पकाल में ठीक नहीं होने वाली हैं. निवेशकों को इस बात का भरोसा चाहिए कि इटली अपने सभी पिछले क़र्ज़ चुका पाएगा. जिन देशों और बैंकों का पैसा इटली के क़र्ज़ में फंसा है वे इटली में और पैसा नहीं लगाना चाहेंगे. इटली को अगर आर्थिक सहायता पैकेज की ज़रूरत हुई तो 440 अरब के कोष में सिर्फ़ 250 अरब यूरो बचे हैं जो नाकाफ़ी होंगे. जिन बैंकों और वित्तीय संस्थानों का पैसा क़र्ज़ के रूप में इटली में लगा है वे किसी तरह इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और वे क़र्ज़ औनी-पौनी क़ीमत पर दूसरी कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे माहौल में इटली जब नया क़र्ज़ लेने की कोशिश करेगा तो निवेशकों में कितना उत्साह होगा यह सहज ही समझा जा सकता है. आर्थिक संकट से निपटने के लिए पिछले दिनों सरकार ने सरकारी बॉन्ड के ज़रिये पांच अरब यूरो की राशि जुटाई थी. हालांकि इस राशि पर उसे 6.087 प्रतिशत का भारी भरकम ब्याज़ देना होगा. यूरोपीय संघ की एक टीम रोम में बनने वाली नई सरकार के प्रयासों पर नज़र गड़ाए हुए है कि वह किस तरह क़र्ज़ का बोझ घटाती है, जो इस वक़्त सकल घरेलू उत्पाद का 120 प्रतिशत तक जा पहुंचा है.

पिछले 15 वर्षों में इटली की अर्थव्यवस्था सिर्फ़ 0.75 प्रतिशत की दर से बढ़ती रही है. बीते दिनों जो कटौती प्रस्ताव पारित हुआ उसके ज़रिये सरकारी ख़र्चों में कटौती और टैक्स बढ़ाकर 59.8 अरब यूरो की बचत की उम्मीद है, ताकि वर्ष 2014 तक बजट को संतुलित किया जा सके. प्रस्ताव के पारित होने पर बाज़ार ने इसका स्वागत किया था और शेयर के दाम उछले थे. क़र्ज़ संकट से उबरने के लिए इटली की सरकार की ओर से प्रस्तावित ख़र्च में कटौती के प्रस्ताव को संसद के निचले सदन ने भी पारित कर दिया है. बताते हैं कि बर्लुस्कोनी ने शर्त रखी थी कि यदि कटौती का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो वह अपना पद छोड़ देंगे. उसी के अनुरूप उन्होंने बीते 13 नवंबर को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया. वैसे बर्लुस्कोनी अपनी रंगीन मिज़ाजी के लिए याद किए जाते रहेंगे. बहरहाल, अब देखना यह है कि इटली की संकट में फंसी अर्थव्यवस्था को नई सरकार कैसे उबारती है.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

साई बाबा के भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे लेकिन इसके लिए साई बाबा पर विश्वास रखना ज़रूरी है. साई सबकी सहायता करते हैं.

व्रत कथा और पूजन विधि

अगर संभव हो तो साई बाबा के मंदिर में जाकर भक्तिभाव से बाबा के दर्शन करने चाहिए. शिरडी के साई बाबा के व्रत की संख्या 9 हो जाने पर अंतिम व्रत के दिन पांच ग़रीब व्यक्तियों को भोजन और सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए. इसके साथ ही साई बाबा की कृपा का प्रचार करने के लिए 7, 11, 21 साई पुस्तकें अपने आसपास के लोगों में बांटनी चाहिए. इस प्रकार इस व्रत को समाप्त किया जाता है.

साई बाबा देश के सबसे महान संत हैं और पूज्यनीय संतों में सर्वोपरि हैं. शिरडी के साई बाबा की चमत्कारी शक्तियों की बहुत सी कथाएं हैं. साथ ही साई बाबा के भक्तों की संख्या सबसे ज़्यादा है. साई बाबा के पूजन के लिए वीरवार यानी गुरुवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है. साई व्रत कोई भी कर सकता है चाहे बच्चा हो या बुज़ुर्ग. जाति–पति के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति यह व्रत कर सकता है. वैसे भी हम सभी जानते हैं कि साई बाबा जात–पात को नहीं मानते थे और उनका कहना था कि ईश्वर एक है.

यह व्रत किसी भी गुरुवार को साई बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता. सुबह या शाम को साई बाबा के फोटो की पूजा करना किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साई बाबा का फोटो रखकर स्वच्छ पानी से पोंछकर चंदन का तिलक लगाना चाहिए और उन पर पीला फूल या हार चढ़ाना चाहिए. अगरबत्ती और दीपक जलाकर साई व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और साई बाबा का स्मरण करना चाहिए तथा प्रसाद बांटना चाहिए (प्रसाद में कोई भी फलाहार या मिठाई बांटी जा सकती है). अगर संभव हो तो साई बाबा के मंदिर में जाकर भक्तिभाव से बाबा के दर्शन करने चाहिए. शिरडी के साई बाबा की व्रत की संख्या 9 हो जाने पर अंतिम व्रत के दिन पांच ग़रीब व्यक्तियों को भोजन और सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए. इसके साथ ही साई बाबा की कृपा का प्रचार करने के लिए 7, 11, 21 साई पुस्तकें अपने आसपास के लोगों में बांटनी चाहिए. इस प्रकार इस व्रत को समाप्त किया जाता है.

व्रत कथा

कोकिला बहन और उनके पति महेशभाई शहर में रहते थे. दोनों में एक–दूसरे के प्रति प्रेम–भाव था, परंतु महेशभाई का स्वभाव झगड़ालू था. बोलने की तमीज़ ही न थी. लेकिन कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थीं. भगवान पर विश्वास रखतीं एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेतीं. धीरे–धीरे उनके पति का धंधा–रोज़गार ठप हो गया. कुछ भी कमाई नहीं होती थी. महेशभाई अब दिनभर घर पर ही रहते और अब उन्होंने ग़लत राह पकड़ ली. अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया.

एक दिन दोपहर का समय था. एक वृद्ध महाराज दरवाज़े पर आकर खड़े हो गए. चेहरे पर ग़ज़ब का तेज था और आकर उन्होंने दाल–चावल की मांग की. कोकिला बहन ने दाल–चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया. वृद्ध ने कहा कि साई सुखी रखे. कोकिला बहन ने कहा कि महाराज सुख मेरी क़िस्मत में नहीं है और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया. महाराज ने श्री साई के व्रत के बारे में बताया. कहा कि 9 गुरुवार (फलाहार) या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साई मंदिर जाना, घर पर साई बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना. साई व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साई व्रत की किताबें 7, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट देना और इस तरह साई व्रत का फैलाव करना. साई बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे, लेकिन साई बाबा पर अटूट श्रद्धा रखनी ज़रूरी है. कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया. 9वें गुरुवार को ग़रीबों को भोजन दिया, व्रत की पुस्तकें भेंट दीं. उनके घर से झगड़े दूर हुए, घर में बहुत ही सुख–शांति हो गई, जैसे महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया हो. उनका धंधा–रोज़गार फिर से चालू हो गया. थोड़े समय में ही सुख–समृद्धि बढ़ गई. दोनों पति–पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे. एक दिन कोकिला बहन के जेठ–जेठानी सूरत से आए. बातों–बातों में उन्होंने बताया के उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं. कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साई बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साई बाबा पर विश्वास रखना ज़रूरी है. साई सबकी सहायता करते हैं. उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा. कोकिला बहन ने उन्हें वे सारी बातें बताईं जो ख़ुद उन्हें वृद्ध महाराज ने बताईं थीं. सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साई व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं. उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में दी थीं. इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी की शादी साई व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह तय हो गई. उनके पड़ोसी का गहनों का डिब्बा गुम हो गया, अब महीने के बाद वह न जाने कहां से वापस मिल गया. ऐसे कई अद्‌भुत चमत्कार हुए थे. कोकिला बहन ने जान लिया कि साई बाबा की महिमा महान है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साई बाबा की आरती

आरती उतारे हम तुम्हारी साई बाबा ।
चरणों के तेरे हम पुजारी साई बाबा
विद्या बल बुद्धि, बंधु माता-पिता हो
तन, मन, धन प्राण, तुम ही सखा हो
हे जगदाता अवतारे, साई बाबा ।
आरती उतारे हम तुम्हारी साई बाबा

ब्रह्म के सगुण अवतार तुम स्वामी
ज्ञानी दयावान प्रभु अंतरयामी
सुन लो विनती हमारी साई बाबा ।
आरती उतारे हम तुम्हारी साई बाबा

आदि हो अनंत त्रिगुणात्मक मूर्ति
सिंधु करुणा के हो उद्धारक मूर्ति
शिरडी के संत चमत्कारी साई बाबा ।
आरती उतारे हम तुम्हारी साई बाबा

भक्तों की खातिर, जनम लिए तुम
प्रेम ज्ञान सत्य स्नेह, मरम दिए तुम
दुखिया जनों के हितकारी साई बाबा ।
आरती उतारें हम तुम्हारी साई बाबा ।

श्री साईनाथ स्तवन मंजरी

मयूरेश्वर जय सर्वाधार। सर्व साक्षी हे गौरिकुमार।
अचिन्त्य सरूप हे लंबोदर। रक्षा करो मम, सिद्धेश्वर।

सकल गुणों का तू है स्वामी। गणपति तू है अंतर्यामी।
अखिल शास्त्र गाते तव महिमा। भालचंद्र मंगल गज वदना।

मां शारदे वाग विलासनी। शब्द–सृष्टि की अखिल स्वामिनी।
जगजननी तव शक्ति अपार। तुझसे अखिल जगत व्यवहार।

कवियों की तूं शक्ति प्रदात्री। सारे जग की भूषण दात्री।
तेरे चरणों के हम बंदे। नमो–नमो माता जगदंबे।

पूर्ण ब्रह्म हे संत सहारे। पंढरीनाथ रूप तुम धारे।
करुणासिंधु जय दयानिधान। पांडुरंग नरसिंह भगवान।

सारे जग का सूत्रधार तू। इस संसृति का सुराधार तू।
करते शास्त्र तुम्हारा चिंतन। तत्स्वरूप में रमते निशदिन।

जो केवल पोथी के ज्ञानी । नहीं पाते तुझको वे प्राणी।
बुद्धिहीन प्रगटाये वाणी। व्यर्थ विवाद करें अज्ञानी।

तुझको जानते सच्चे संत। पाये नहीं कोई भी अंत।
पद–पंकज में विनत प्रणाम। जयति–जयति शिरडी घनश्याम।

पंचवक्र शिवशंकर जय हो। प्रलयंकर अभ्यंकर जय हो।
जय नीलकंठ हे दिगंबर। पशुपतिनाथ के प्रणव स्वरा।

हृदय से जपता जो तव नाम। उसके होते पूर्ण सब काम।
साई नाम महा सुखदाई। महिमा व्यापक जग में छाई।

पदारविंद में करूं प्रणाम। स्तोत्र लिखूं प्रभु तेरे नाम।
आशीष वर्षा करो नाथ हे । जगतपति हे भोलेनाथ हे।

दत्तात्रेय को करूं प्रणाम। विष्णु नारायण जो सुखधाम।
तुकाराम से संतजनों को। प्रणाम शत–शत भक्तजनों को।

जयति–जयति जय–जय सांई नाथ हे। रक्षक तू ही दीनदयाल हे।
मुझको कर दो प्रभु सनाथ। शरणागत हूं तेरे द्वार हे।

तू है पूर्ण ब्रह्म भगवान। विष्णु पुरुषोत्तम तू सुखधाम।
उमापति शिव तू निष्काम। था दहन किया नाथ ने काम।

निराकार तू–तू है परमेश्वर। ज्ञान–गगन का अहो दिवाकर।
दयासिंधु तू करुणा–आकर। दलन–रोग भव–मूल सुधाकर।

निर्धन जन का चिंतामणि तू। भक्त–काज हित सुरसुरि जम तू।
भवसागर हित नौका तू है। निराश्रितों का आश्रय तू है।

जग–कारण तू आदि विधाता। विमलभाव चैतन्य प्रदाता।
दीनबंधु करुणानिधि ताता। क्रीड़ा तेरी अद्‌भुत दाता।

तू है अजन्मा जग निर्माता। तू मृत्युंजय काल–विजेता।
एक मात्र तू ज्ञेय–तत्व है। सत्य–शोध से रहे प्राप्य है।

क्रमशः

यह पुस्तक भारतीय मिथकों से भी पाठकों को परिचित कराती है. इसमें कई रोचक बातें हैं, जिनमें से एक है शाप का वर्णन.

अनंत विजय

यस ! वी हैव प्रेमचंद

बेहद ही दिलचस्प, लेकिन हैरान करने वाला वाक़िया है. एक दिन यूं ही दफ्तर से निकला तो तफ़रीह के लिए पास के ही एक मॉल में चला गया. अपनी आदत है कि जहां भी जाता हूं वहां किताबों की दुकान ढूंढकर एक बार उसके चक्कर ज़रूर लगाता हूं. नोएडा के उस शानदार मॉल में भी घूमते-घामते एक बहुत बड़ी किताबों की दुकान पर जा पहुंचा. बेहद करीने से शानदार कवर में चमचमाती अंग्रेजी की किताबें रैक पर लगी थीं. कई नई किताबें तो न्यू अराइवल के डेस्क पर खड़ी और पड़ी थीं. अलग-अलग तरह की किताबों का अलग-अलग सेक्शन बना था, जहां आप अपनी सहूलियत और पसंद के हिसाब से किताबों को चुनकर ख़रीद सकते हैं. काफ़ी देर घूमने के बाद जब मुझे कहीं हिंदी की किताबें नहीं दिखाई दीं तो मैं सेल्स काउंटर पर गया और वहां खड़े सज्जन से पूछा कि भाई साहब आपके पास हिंदी की किताबें नहीं हैं क्या. वह बेहद तत्परता से काउंटर छोड़कर मेरी मदद के लिए बाहर आ गया. मैंने उनसे कहा कि मैं काफ़ी देर से हिंदी की किताबें तलाश रहा हूं, लेकिन इन तमाम चमचमाती अंग्रेजी की किताबों के बीच हिंदी की किताबें दिख नहीं रही हैं. मेरी जिज्ञासा देखकर उसका भरोसा बढ़ा और उसने मुझे अपने पीछे आने को कहा. मैं उसके साथ अंग्रेजी फिक्शन, ऑटोबॉयोग्राफी, मैनेजमेंट आदि की किताबों को पार करते हुए एक कोने में पहुंचा. उस रैक पर लिखा था इंडियन लैंग्वेजेज. सेल्समैन ने मुझे कहा कि सर यह देखिए हिंदी की किताबें यहां लगी हैं. मेरी आंखें वहां उस रैक पर हिंदी की किताबें तलाशने लगीं. वहां जो किताबें मौजूद थीं, उनमें हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के चार खंड, अमर्त्य सेन की किताबों के अनुवाद के अलावा डायमंड पॉकेट बुक्स की कई किताबें लगी थीं. इसके अलावा शिवाजी सावंत का मृत्युंजय भी वहां रखा था. वाणी प्रकाशन की भी कुछ किताबें लगी थीं. जब मुझे मेरे मतलब की कोई भी किताब नहीं मिली तो मैंने सेल्समैन से पूछा कि क्या आपके पास प्रेमचंद की किताबें हैं? उसने तपाक से जवाब दिया-यस सर वी हैव प्रेमचंद एंड वी हैव ऑल द बुक्स रिट्न बाय प्रेमचंद. मैंने कहा कि कहां हैं मुझे तो दिख नहीं रहीं. मेरे इतना बोलते ही वह अचानक ग़ायब हो गया और चंद पलों में दस बारह किताबों का बंडलनुमा पैकेट लेकर प्रकट हुआ. पैकेट को लगभग खोलते हुए उसने कहा कि यह प्रेमचंद का सेलेक्टेड वर्क है. वह यह बताते हुए गर्व का अनुभव कर रहा था कि उसके पास हिंदी के महानतम लेखक प्रेमचंद की चुनिंदा रचनाओं का पूरा सेट मौजूद है. लेकिन मैं कहीं गहरी सोच में डूबा जा रहा था. मेरे मन में यह सोचकर निराशा का अंधकार भरता जा रहा था कि प्रेमचंद को अब भारत में, वह भी उत्तर भारत में लोग अंग्रेजी में पढ़ेंगे. अचानक मेरी तंद्रा टूटी जब उसने पूछा कि सर बिल बनवा दूं. मैंने अपने सूखते हलक़ से उससे माफ़ी मांगी और तेज़ चलता हुआ बुक कैफे से बाहर आ गया .

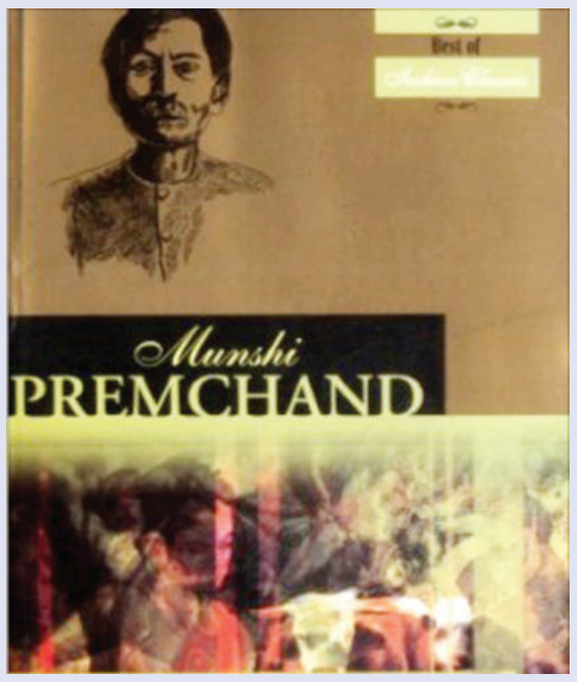

बुक कैफे से बाहर निकलकर मैं लगातार इसी सोच में डूबा रहा कि प्रेमचंद की रचनाएं हिंदी में सुलभ न होकर अंग्रेजी में बेहतर तरीक़े से क्यों सुलभ हैं. किसी भी रचनाकार की कृति अगर किसी अन्य भाषा में मौजूद हो तो बहुत अच्छी बात है. उससे उस लेखक की स्वीकार्यता और उसके पाठकों का दायरा भी बढ़ता है. लेकिन मेरी चिंता का कारण प्रेमचंद की रचनाओं का अंग्रेजी में उपलब्ध होना नहीं था. चिंता की वजह प्रेचमंद की रचनाओं का हिंदी में उपलब्ध नहीं होना था. हमें इसके कारणों में जाना होगा, तलाशना होगा उन वजहों को. मेरा मानना है कि हिंदी में प्रकाशकों को इस बात की चिंता ज़रा कम होती है कि किताबें पाठकों के लिए सुलभ करवाई जाएं. हिंदी के लगभग सभी प्रकाशक मेरे मित्र हैं और गाहे-बगाहे उनसे बातचीत होती भी रहती है. लेकिन उस बातचीत में एक-दो प्रकाशकों को छोड़कर कोई भी कभी इस बात के लिए प्रयास करता नहीं दिखता कि कैसे पाठकों तक पहुंचा जाए. मैं इस स्तंभ में कई बार इस बात को खुले तौर पर और कई बार इशारों में कह चुका हूं कि भारत में हिंदी का जो प्रकाशन उद्योग है वह सालों पुरानी लीक पर चल रहा है और प्रकाशकों के अंदर उस लीक से हटने की न तो बेचैनी है और न ही नए तौर-तरीक़ों को आज़माने और अपनाने की ललक. मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि वाणी प्रकाशन न केवल फेसबुक पर तक़रीबन पांच हज़ार की मित्र संख्या के साथ मौजूद है, बल्कि इस सोशल साइट पर उसका एक अलग से पन्ना है. लेकिन वहीं इस बात का दुख भी होता है कि वाणी की तरह अन्य प्रकाशन संस्थान इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. पहले भी कई बार कह चुका हूं कि प्रकाशन संस्थानों की अपनी ख़ुद की बेवसाइट भी नहीं है, दो-चार को छोड़कर. उससे भी मज़े की बात है कि जिन प्रकाशन संस्थानों की बेवसाइट्स हैं, वहां अगर आप ख़रीदारी करेंगे तो कम छूट मिलती है और फ्लिपकार्ट जैसी बेवसाइट्स पर पाठकों को ज़्यादा छूट और कैश ऑन डिलीवरी जैसी सुविधा भी उपलब्ध है. हमारे हिंदी के ज़्यादातर प्रकाशकों में पाठकों तक पहुंचने की जो व्यवसायिक ललक होनी चाहिए, वह नहीं है. नतीजा यह होता है कि सिर्फ़ देशभर में इधर-उधर लगने वाले पुस्तक मेलों में भागीदारी कर वे अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं. प्रकाशकों की तरफ़ से पाठकों तक पहुंचने की कोई ठोस योजना प्रकाशकों के पास नहीं है, हां कभी-कभार कुछ छिटपुट होता रहता है.

वैश्वीकरण के इस युग में अब वक़्त आ गया है कि हिंदी के प्रकाशकों को पारंपरिक कारोबारी रास्ते से हटना होगा और उस अत्याधुनिक रास्ते पर चलना होगा जिससे कि वे दूसरी भाषाओं के प्रकाशकों से कंपीट कर सकें. पाठकों तक पहुंचने के लिए सारे प्रकाशकों को मिलकर एक ऐसी योजना बनानी होगी, जिसमें सबकी बराबर की भागीदारी हो. अब वह वक़्त ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, जहां भारी भरकम सरकारी ख़रीद हो.

लेकिन वैश्वीकरण के इस युग में अब वक़्त आ गया है कि हिंदी के प्रकाशकों को पारंपरिक कारोबारी रास्ते से हटना होगा और उस अत्याधुनिक रास्ते पर चलना होगा जिससे कि वे दूसरी भाषाओं के प्रकाशकों से कंपीट कर सकें. पाठकों तक पहुंचने के लिए सारे प्रकाशकों को मिलकर एक ऐसी योजना बनानी होगी, जिसमें सबकी बराबर की भागीदारी हो. अब वह वक़्त ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, जहां भारी भरकम सरकारी ख़रीद हो. सरकारी ख़रीद में होने वाले भ्रष्टाचार के मद्देनज़र अब इस तरह की बात उठने लगी है कि थोक सरकारी ख़रीद बंद कर दी जाए. अगर थोक सरकारी ख़रीद बंद हो गई तो प्रकाशकों के पास पाठकों तक पहुंचने के प्रयास के अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं. इसलिए जब पाठक ही प्रकाशकों के आख़िरी विकल्प होते जा रहे हों तो अभी से उस विकल्प को लेकर गंभीरता से काम होना चाहिए और उन तक पहुंचने और उन्हें पुस्तकें सुलभ करने की गंभीर कोशिश होनी चाहिए. इसके लिए हमें पुस्तकों की उपलब्धता के बारे में सोचना होगा. हर उस जगह को तलाशना होगा, जहां किताबें रखी और बेची जा सकें. उन रास्तों को तलाशना होगा, जो सीधे पाठकों तक पहुंचते हों. फ्लिपकॉर्ट जैसी बेवसाइट्स के साथ कारोबारी रिश्ते प्रगाढ़ करने होंगे. उन बेवसाइट्स पर यह ज़ोर डालना होगा कि वे यह भी प्रचारित करें कि वहां हिंदी की तमाम पुस्तकें मौजूद हैं और पाठकों को एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकता है. आने वाला वक़्त पूरी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग का है और हिंदी के प्रकाशकों को इसको ही ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की रणनीति बनानी होगी. अन्यथा हमें बार-बार यह सुनना पड़ेगा कि यस सर वी हैव प्रेमचंद इन ऑवर स्टॉक.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

देवताओं की रोचक कहानियां

सर्वश्रेष्ठ पुस्तक समीक्षा

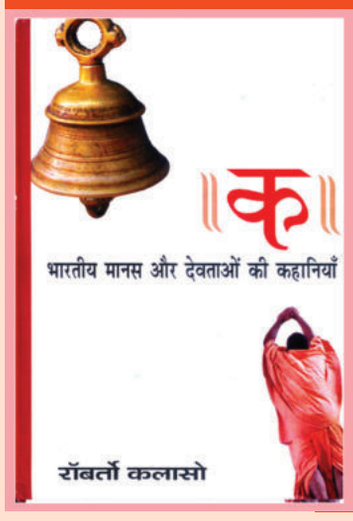

समीक्ष्य कृति-भारतीय मानस और देवताओं की कहानियां
लेखक-रॉबर्तो कलासो
प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
मूल्य-450 रुपये

इतालवी लेखक रॉबर्तो कलासो की पुस्तक भारतीय मानस और देवताओं की कहानियां अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है. इस पुस्तक में लेखक ने हिंदुओं के देवी-देवताओं की कहानियों को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है. इसमें सृष्टि के आरंभ से लेकर बुद्धकाल तक के मिथकीय प्रश्नों, किंवदंतियों, दार्शनिक खोजों का वर्णन है. यह पुस्तक भारतीय मिथकों से भी पाठकों को परिचित कराती है. इसमें कई रोचक बातें हैं, जिनमें से एक है शाप का वर्णन. लेखक का कहना है कि कथाओं को आगे बढ़ाने में किसी शाप की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती थी. शाप की भीषणता और उससे जुड़े कष्टों को सहनीय बनाने का काम करते थे प्रण और वरदान, वैसे इनकी भूमिका शाप जितनी महत्वपूर्ण नहीं होती थी. और ऐसा नहीं कि शाप केवल मनुष्यों को ही संकटों में डालते थे, देवता भी उनके प्रभाव से अछूते नहीं रह पाते थे. ये शाप देने वाले प्राय: ब्राह्मण और कभी-कभी ऋषिगण भी होते थे. हम पाते हैं कि हर शाप के साथ नियति चक्र भी घूमने लगता था. कई बार ऐसा भी होता था कि शापित व्यक्ति को शाप का पता ही नहीं चलता था और शाप अपना प्रभाव दिखाने लगता था. बेचारी शकुंतला एक शाप के कारण ही अनेक वर्षों तक अपने प्रिय के संग-साथ से वंचित रही. यद्यपि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था. इन कथाओं को सुनाने वाले व्यास में भी भयानक शाप देने की क्षमता थी. शाप किसी के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन ला देता था, उसके प्रभाव से जीवन जैसे उलट-पलट जाता था. शास्त्र-पुराण हर घटनाक्रम का वर्णन तो बहुत विस्तार से करते दिखाई देते हैं, किंतु उस घटनाक्रम के मूल में उपस्थित शाप के विषय में कुछ अधिक नहीं कहते. कभी-कभी साधारण शाप से सृष्टि क्रम में ऐसा भयानक भूचाल आ जाता था, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पाता था.

दुर्वासा में शिव का ताप था. वह शिव के अंश थे. दुर्वासा भी एक ऋषि थे, किंतु याज्ञवल्क्य या विश्वामित्र अथवा अन्य मंत्रदृष्टा ऋषियों जैसे नहीं, न ही वह व्यास की तरह कविगुण संपन्न थे. दुर्वासा का संसार तो क्रोध और रोष के आवरण के पीछे बसता था. उनका व्यक्तित्व शाप और वरदान में ही दिखाई देता था. वह किसी सामान्य बात से भी उत्तेजित-क्रोधित हो सकते थे. यह कहना या जानना लगभग असंभव था कि किस बात पर भड़क कर शाप नहीं दे डालेंगे. एक बार दुर्वासा इंद्र से मिले. उन्होंने अपनी माला इंद्र के हाथी ऐरावत को दे दी, किंतु ऐरावत ठहरा हाथी. माला उसे परेशान करने लगी. अपनी सूंड से खिसकाकर ऐरावत ने पुष्पमाला को नीचे गिरा दिया. तुरंत संसार को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली श्री समुद्र में समा गईं. इंद्र को लगा बस संकट आने ही वाला है, उनकी शक्तियां उनसे छिनने वाली हैं. उन्होंने चारों ओर देखा तो सब तरफ़ निर्जनता थी, मानो एकाएक कुछ अघट घट गया हो. ऐरावत द्वारा गिराई गई पुष्पमाला स्वर्ग से सीधी दुर्वासा पर जा गिरी. उसी माला में श्री का वास था. यह होते ही संसार की भव्यता नष्ट हो गई, हरियाली सूख गई. इस साधारण सी दिखाई देने वाली घटना के फलस्वरूप ही देवताओं को अपने अस्तिव की रक्षा के लिए सागर मंथन जैसा कठिन कार्य करने पर विवश होना पड़ा. दुर्वासा यदि कहीं दिखाई पड़ते तो इसे भयानक संकट की पूर्व सूचना माना जाता था. देवता जानते थे कि इस कृशकाय क्रोधी ब्राह्मण में पलभर में संसार का विनाश करने की क्षमता है. पौराणिक विवरण बताते हैं कि जब-जब संसार पर संकट मंडराया दुर्वासा के कारण. दुर्वासा वरदान भी देते थे. उन्होंने कुंती को भी एक वरदान दिया था. उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया था, जिसके माध्यम से वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी. इसी मंत्र की शक्ति से कुंती ने देवताओं का आह्वान किया और दिव्य संपर्क के बाद युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन कुंती की कोख में आए. कुंती ने माद्री को अश्विनी कुमारों वाला मंत्र बताया तो वह उन्हें बुलाने में सफल रही थी तथा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ. कुल मिलाकर यह पुस्तक ज्ञानवर्द्धक और उपयोगी है.

शिरीष मालवीय
feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

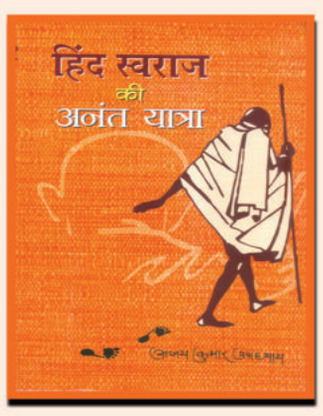

पुस्तक का नाम
हिंद स्वराज की अनंत यात्रा
लेखक
अजय कुमार उपाध्याय
प्रकाशक
प्रभात प्रकाशन
मूल्य
250 रुपये

इस पुस्तक में हिंद स्वराज के प्रकाश में महात्मा गांधी के जीवन की यात्रा का वर्णन है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

ब्राईट® की सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

21st Century A DICTIONARY OF COMMON ERRORS ₹ 99
CROSS STITCH Manual Part - 1 ₹ 60
Cross-Stitch Manual Part - II ₹ 70
21st Century DICT ENGLISH - HINDI ₹ 75
21 Century DICT. English-English-Hindi ₹ 125
वजन कम करने के सरल उपाय ₹ 50
इंगलिश सीखिए और बोलिए ₹ 199
Stop Worrying Start Living ₹ 50
Successful Techniques to Improve Your Personality ₹ 99
★ VASTU SHASTRA ₹ 70
WORD POWER ₹ 20
WORD POWER MADE EASY ₹ 80
★ Love Letters ₹ 30
Think Positive Act Positive ₹ 70
Treasury of Idiom & Phrases ₹ 75
How to be an Entrepreneur ₹ 50
Unique Letter Writing ₹ 45
Guide to Good Health ₹ 40
Handbook of Synonyms, Antonyms & Homonyms ₹ 75
Homoeopathic Remedies ₹ 40
How to Lose Weight ₹ 50
Nature Cure ₹ 35
A Modern Approach to Personality Development ₹ 45
★ Yogic Cure ₹ 40
★ Healing with Reiki ₹ 60
★ हिन्दी संस्करण भी उपलब्ध है।

FROM THE HOUSE OF : BRIGHT® Career's® BOOKS | COMPETITION REFRESHER | SCIENCE REFRESHER | G.K. GENERAL KNOWLEDGE REFRESHER

BRIGHT PUBLICATIONS®
Publishers of INDIA'S LARGEST SELLING Competition & School Books
2767, Kucha Chellan, Darya Ganj, New Delhi-110 002 (India) —— (ESTD. 1968)
Ph.: 011-64632226 & 3226, 23282226 & 3226 Fax: 011-23269227 Telefax: 64633226
E-mail: sales@brightpublications.com | Web Site: http://www.brightpublications.com

FOR VPP ORDERS, SEND ₹ 25/- AS ADVANCE & FOR FREE CATALOGUE WRITE TO US

इलाहाबाद के बाद चुनार से भी उत्पादन शुरू हो जाने से बिहार और झारखंड के उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी.

हस्तकलाओं का अस्तित्व ख़तरे में

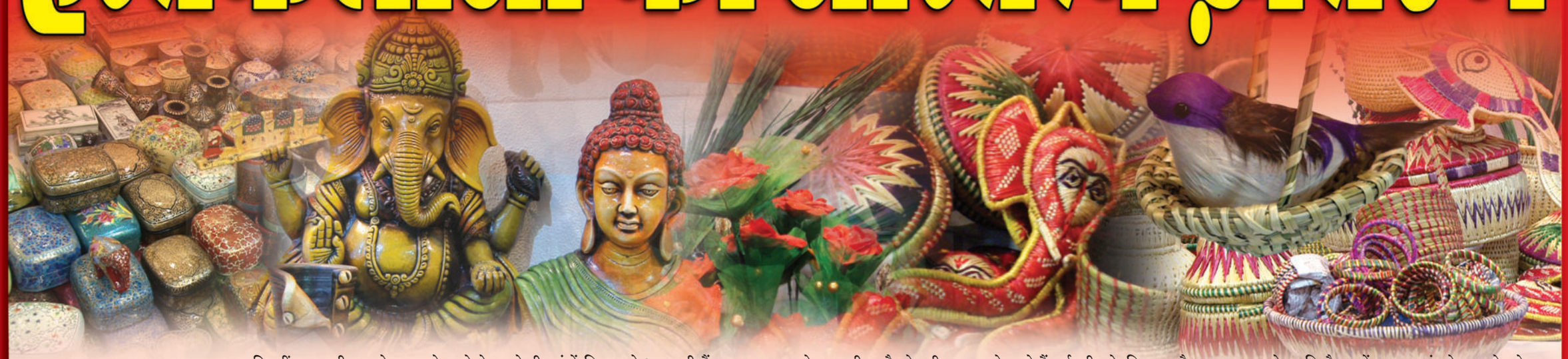

रीतिका सोनाली

इक्कीसवीं सदी के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में व्यापार लोगों को जोड़ने वाली सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से है. लेकिन आश्चर्य यह है कि व्यापार की बढ़ती समृद्धि के साथ ग़रीबी भी बढ़ी है और इससे अमीरी और ग़रीबी के बीच की खाई बड़ी हो गई है. विश्व व्यापार में वे संभावनाएं हैं, जो ग़रीबी हटाने के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेहतरीन माध्यम बन सकती हैं. लेकिन हस्तकला इस अवसर से महरूम है. समस्या यह नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वाभाविक तौर पर उनकी ज़रूरतों और हितों के विरोध में है, बल्कि समस्या यह है कि जो नियम व क़ानून इसकी अगुवाई करते हैं उसका फ़ायदा सिर्फ़ बड़ी कंपनियों को होता है. अच्छी तरह से प्रबंधित व्यापार में इतनी ताक़त होती है कि लाखों लोगों को ग़रीबी से उबारा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है.

बहुत उम्मीद से जब नाजदां ख़ातून ने गांव वालों को सिक्की कला सिखाना शुरू किया तो एक-दो दिन गांव की महिलाओं ने ख़ूब उत्साह दिखाया. दोपहर के वक़्त उनके घर का आंगन आस-पड़ोस की महिलाओं से भरा रहता था. नाजदां ख़ातून वक़्त निकाल कर उन्हें बड़ी लगन से सिक्की कला सिखातीं, जो अब गांव में केवल उनकी और उनकी बेटी के हाथों की ही शान है. लेकिन कुछ ही दिनों में नाजदां ख़ातून का आंगन धीरे-धीरे ख़ाली होने लगा, एक-एक कर महिलाओं ने आना बंद कर दिया. वे इसे सीखने में आनाकानी करने लगीं. वजह, सिक्की कला सीखने और इससे माल तैयार करने में बहुत समय लग जाता है. हालांकि यह कला गांव की मिट्टी में रची बसी है, लेकिन इसकी ख़ुशबू गुम हो गई. इसे संजोना संभव नहीं हो पाया. सिक्की कला गांव वालों के हाथों से छूटती जा रही है. यह गांववालों के जीवनयापन का ज़रिया बन पाए, ऐसा संभव नहीं हो सका. महिलाएं नाजदां ख़ातून से कहतीं कि जितने वक़्त में वे सिक्की कला सीखकर एक शो पीस या कोई भी सजावट की वस्तु तैयार कर पाएंगी उतने दिन अगर वे किसी के खेत पर मज़दूरी करेंगी तो इससे ज़्यादा पैसा आएगा और परिवार की आय में बढ़ोत्तरी होगी. उनके घर आने वाली महिलाएं भी गांव में ही सेंटर की मांग करती हैं, जिससे वे बेहतर तरीक़े से सीख पाएं और उनकी कुछ न कुछ आमदनी रोज़ हो जाए. लेकिन सरकार की तरफ़ से यहां सेंटर ले जाने की बात अभी दूर ही है. नाजदां ख़ातून ख़ुद का कच्चा माल और समय देकर भी इस कला को निपुण हाथों में सहेज नहीं पाएंगी, इस बात का उन्हें बेहद अफ़सोस है. राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में बिहार पैवेलियन में बैठी नाजदां ख़ातून टी कोस्टर बनाते हुए आते-जाते लोगों को बिहार की सिक्की कला से बड़े शौक़ से परिचित करवाती हैं. सिक्की कला के बारे में बताते हुए उनकी आंखों में गर्व झलकता है, लेकिन पूछने वाले के मुड़ते ही आंखें निराशा से भर जाती हैं. दरअसल, पूरा दिन लगाकर सिक्की कला से बनाई गई एक टी कोस्टर की क़ीमत मात्र पचास रुपये है. सिक्की कला के क्राफ्ट बनाने में नाजदां ख़ातून माहिर हैं. वह पटना के सरकारी प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षित लोगों से भी बेहतर क्राफ्ट बना सकती हैं, लेकिन वह अपनी कला से लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं. वह देवी-देवताओं की मूर्तियां छोड़कर, केवल वैसी ही चीज़ें बनाती हैं जो शहरी कामकाज या मांग में शामिल हो सकें. अब साल में दो ही प्रदर्शनी कर पाती हैं, क्योंकि साल भर में भी इतना माल तैयार नहीं हो पाता कि हर प्रदर्शनी में अपनी कला प्रदर्शित कर सकें. त्रिपुरा के बैम्बू आर्टिस्ट सुभाष का स्टॉल ट्रेड फेयर में पहली बार लगा. सुभाष उस समय काफ़ी ख़ुश हुए जब एक एक्सपोर्ट हाउस की तरफ़ से उन्हें बैम्बू के 5000 मिठाई के डिब्बे बनाने का ऑर्डर मिला. लेकिन निराशा तब हुई जब उन्हें इस बात का अहसास हुआ कि उनके पास न तो इतने कारीगर हैं और न ही इतना कच्चा माल है कि वह एक महीने में माल तैयार कर सकें. सुभाष ने चार-पांच सौ पीस देने की बात कही, पर एक्सपोर्ट हाउस की मांग के अनुसार न होने की वजह से यह ऑर्डर उनके हाथ से निकल गया. कम संसाधन और निपुण हाथों की कमी की वजह से सुभाष को ट्रेड फेयर में आने का प्रयोजन पूरा होता नहीं लगता है. उत्तर प्रदेश के खुर्जा के रईसुद्दीन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अपना पुश्तैनी काम मेटल ऑक्साइड से पेंटिग करने की विद्या की प्रदर्शनी लगाकर बैठे हैं. वह फ्लॉवर वाश, क्रॉकरी और दूसरी सजावट की वस्तुएं बनाकर और उन पर ऑक्सीडाइज्ड पेंट करते हैं. यही उनका पुश्तैनी काम है. वैसे तो यह काम 400 साल पुराना है, लेकिन धीरे-धीरे इसकी साख ख़त्म होती जा रही है. कभी इस कला का गढ़ माने जाने वाले ख़ुर्जा में अब लगभग 20 ही ऐसे कारीगर बचे हैं जो इस महीन और बेहतरीन काम को करते हैं. रईसुद्दीन के पिता, दादा, परदादा ने इस काम को बाक़ायदा ख़ुदा की इनायत समझ कर किया था, लेकिन उन्होंने बीएससी करके नौकरी नहीं मिल पाने की वजह से इस काम को अपने हाथों में लिया. हालांकि वह इस कला को प्रेम से करते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसमें रुचि दिखाएगी, यह संभव नहीं लगता है. रईसुद्दीन कहते हैं कि यह कंप्यूटर का युग है और बच्चे अपना मनपसंद करियर चुनने के लिए स्वतंत्र हैं. वैसे भी इस कला को लेकर इलाक़े में कोई जागरूकता लाने की ऐसी कोशिश नहीं की गई जिससे अगली पीढ़ी इस कला में रोज़गार की संभावनाएं तलाश कर सके. फ़िलहाल रईसुद्दीन अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में अपने पुरखों की शान इस कला की निपुणता नहीं दे पाएंगे, इसका अफ़सोस उन्हें बेहद सालता है. ट्रेड फेयर के अलग-अलग पैवेलियन में ऐसी कई कहानियां हैं, जो विकास के मुहाने पर खड़ी हैं, जिन्हें अगर हाथ बढ़ाकर थाम लिया जाए तो उन्हें जीवन मिल जाएगा, और अगर इससे मुंह फेर लिया जाए तो हस्तकलाओं को विलुप्त होने से कोई नहीं बचा पाएगा. विभिन्न राज्यों के पैवेलियन में जहां बड़ी-बड़ी कंपनियों के स्टॉल राज्यों की समृद्धि का परिचय देते हैं, वहीं कोनों में बिखरी ऐसी कहानियां कंपनियों के ज़रिये राज्य के विकास को मुंह चिढ़ाती हैं. 31वें ट्रेड फेयर की थीम इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स-द मैजिक ऑफ गिफ्टेड हैंड्स की सार्थकता कम हो जाती है, जब कला का जादू बिखेरने वाले इन कलाकारों के हालात का जायज़ा लेते हैं. विभिन्न राज्यों से आए हस्त कलाकार मन में अपनी कला को वैश्विक स्तर पर फैलाने का सपना लेकर ट्रेड फेयर में आते हैं. उनकी कला का आकर्षण व्यापारियों और दूसरे लोगों को प्रभावित भी करता है, लेकिन संसाधनों आदि में कमी की वजह से इन कलाओं का जादू बिखरने से पहले ही ख़त्म हो जाता है. 1980 से प्रगति मैदान में शुरू हुए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और भारतीय विशिष्ट कलाओं को सफल रोज़गार का ज़रिया बनाने को वैश्विक प्लेटफॉर्म देना रहा है, लेकिन व्यापार मेले के हर पैवेलियन में लगे बड़ी-बड़ी कंपनियों और इंडस्ट्रीज के स्टॉल इस उद्देश्य को विपरीत दिशा में ले जाते हैं. पूर्वी चंपारण में शीप ज्वैलरी के कारीगर मो. वसीम हैदर की स्टॉल पर आते ही फैशन डिज़ाइनर पायल जोशी की आंखें ख़ुशी से चमकने लगती हैं, क्योंकि उन्हें बेहतरीन क्वालिटी की शीप ज्वैलरी बहुत कम दामों पर उपलब्ध हो गई. नदी के किनारे मिलते शीप की ज्वैलरी का फैशन गाहे-बगाहे लौट कर आता रहता है. एक फैशन शो या डिज़ाइन में इस्तेमाल के बाद यह लेटेस्ट ज्वैलरी ट्रेंड बन जाता है. लेकिन जो डिज़ाइनर्स इनका इस्तेमाल करते हैं वे इस तरह की ज्वैलरी को बाहर से मंगवाते हैं, यानी जो चीज़ देश के गांवों में कम क़ीमत पर उपलब्ध हो सकती है, सरकारी नीतियों में कमी और अनदेखी की वजह से लुप्त हो जाती है और वही चीज़ बाहर से महंगे दामों में ख़रीदकर उनका इस्तेमाल किया जाता है. मो. वसीम हैदर बताते हैं कि पूर्वी चम्पारण में शीप ज्वैलरी की लगभग 500 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से आधी से ज़्यादा बंद हो गई हैं. कारीगरों और संसाधनों की कमी से यह कला लुप्त हो रही है. लोग अब शहर जाकर या तो नौकरी करने लगे हैं या किसी और बिजनेस से जुड़ गए हैं. हस्तकला से जुड़े कलाकारों की समस्याएं बड़ी हैं. अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदर्शनी लगाने भर से इन समस्याओं का निदान संभव नहीं है और जब तक उनकी मूल समस्याओं का निदान नहीं होगा, तब तक ये प्रदर्शनियां बाहर से आने वाले बिजनेस डेलिगेट्स और लोगों के लिए केवल देखने और सराहना करने भर का साधन बनकर रह जाएंगी. दरअसल, हस्तकला से जुड़े कारागरों को परेशान करती है, उनके क्षेत्र में स्लो मार्केट ग्रोथ, एडवर्स प्राइस ट्रेंड्स और लो वैल्यू ऐड. हस्तकला से जुड़े शिल्पकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इसलिए आते हैं, ताकि उन्हें भी इस क्षेत्र से जुड़े बड़े व्यापार-उद्योग की जानकारी मिल सके, और अपनी क्षमता अनुसार इसमें वे भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें. इसके अलावा विदेशी और शहरी मार्केट के ट्रेंड और मांग को समझ सकें. इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आने वाले दूसरे लोगों से अपनी कला को प्रोत्साहित करने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए नए आइडिया और तकनीक का सुझाव ले सकें और उन्हें इस्तेमाल कर सकें, कम समय में बेहतरीन काम हो सके. सरकार को हस्तकला से जुड़े कारीगरों की मदद के लिए क़दम उठाने चाहिए. लेकिन अफ़सोस की बात है कि ट्रेड फेयर में आने वाले नेता अपने-अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी चीज़ों की तारीफ़ करते हैं और कारीगरों की पीठ थपथपा कर वापस लौट जाते हैं. हर साल ट्रेड फेयर में लगभग यही नज़ारा देखने को मिलता है.

ritika@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2011

राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में बिहार पैवेलियन में बैठी नाजदां ख़ातून टी कोस्टर बनाते हुए आते-जाते लोगों को बिहार की सिक्की कला से बड़े शौक़ से परिचित करवाती हैं. सिक्की कला के बारे में बताते हुए उनकी आंखों में गर्व झलकता है, लेकिन पूछने वाले के मुड़ते ही आंखें निराशा से भर जाती हैं. दरअसल पूरा दिन लगाकर सिक्की कला से बनाई गई एक टी कोस्टर की क़ीमत मात्र पचास रुपये है. सिक्की कला के क्राफ्ट बनाने में नाजदां ख़ातून माहिर हैं.

नाजदां ख़ातून | सुभाष | मो. वसीम हैदर | रईसुद्दीन

चुनार प्लांट से जेपी सीमेंट चादर का उत्पादन शुरू

जेपी समूह की इकाई जेपी सीमेंट चादर के चुनार प्लांट से भी उत्पादन शुरू हो गया है. इससे बिहार और झारखंड के उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी. होटल मौर्या में कंपनी के विक्रेता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी गई.

कंपनी के उपमहाप्रबंधक संजय गुप्ता ने बताया कि वर्ष 1986 में सीमेंट चादर का उत्पादन एक मिलियन टन था जो अब 34 मिलियन टन पर पहुंच गया है. इलाहाबाद के बाद चुनार से भी उत्पादन शुरू हो जाने से बिहार और झारखंड के उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी. बिहार में कंपनी की भागीदारी 11 फ़ीसदी है जो अब बढ़कर 20 फ़ीसदी पर पहुंच जाएगी. मोहनिया और बेगूसराय में भी डीपी खोलने की योजना है.

पटना मुज़फ्फरपुर और सीवान में पहले से है. सीमेंट चादर का निर्माण आधुनिक तरीक़े से हो रहा है. इस कारण यह गुणवत्ता में अव्वल है. बिहार में क़रीब 105 अधिकृत विक्रेता और 700 फटकर विक्रेता कंपनी से जुड़े हैं. इस मौक़े पर उपक्षेत्रीय प्रबंधक अरुण मलिक ने विक्रेताओं को सम्मानित किया. वरिष्ठ महाप्रबंधक पीपी सिंह ने सीमेंट प्रभाग के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

गौतम गंभीर अपोलो ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के अभियान गिफ्ट ए लाइफ की वेबसाइट की ओपनिंग सेरोमनी मे पहुंचे थे.

बोल्ट की हैट्रिक

जमैका के उसैन बोल्ट और ऑस्ट्रेलिया की महिला विश्व चैंपियन (100 मीटर बाधा दौड़) सैली पीयर्सन को अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ (आईएएएफ) ने एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाज़ा है. बीजिंग ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ स्पर्धा के चैंपियन रहे बोल्ट को इस पुरस्कार से तीसरी बार सम्मानित किया गया है यानी यह उनकी हैट्रिक है. इससे पहले बोल्ट को वर्ष 2008 और 2009 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. 25 वर्षीय बोल्ट इस वर्ष दाएगू में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में अपने ख़िताब की रक्षा करने में कामयाब रहे थे. इसके अलावा इस चैंपियनशिप में 4 गुणा 100 मीटर रिले दौड़ स्पर्धा में बोल्ट ने जमैका की टीम को विश्व रिकॉर्ड के साथ (37.04 सेकेंड) पहला स्थान बरक़रार रखने में अहम भूमिका निभाई थी. इस वर्ष दक्षिण कोरिया के दाएगू में संपन्न हुए विश्व चैंपियनशिप में बोल्ट को फॉल्स स्टार्ट के कारण 100 मीटर दौड़ के लिए अयोग्य घोषित किया गया था. 25 वर्षीय पीयर्सन ने इस वर्ष विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ का ख़िताब पिछले 19 वर्षों में सबसे तेज़ समय (12.21 सेकेंड) के साथ अपने नाम किया था. उल्लेखनीय है कि वर्ष 1988 में शुरू किए गए इस पुरस्कार को हासिल करने वाली पीयर्सन ऑस्ट्रेलिया की पहली एथलीट हैं.

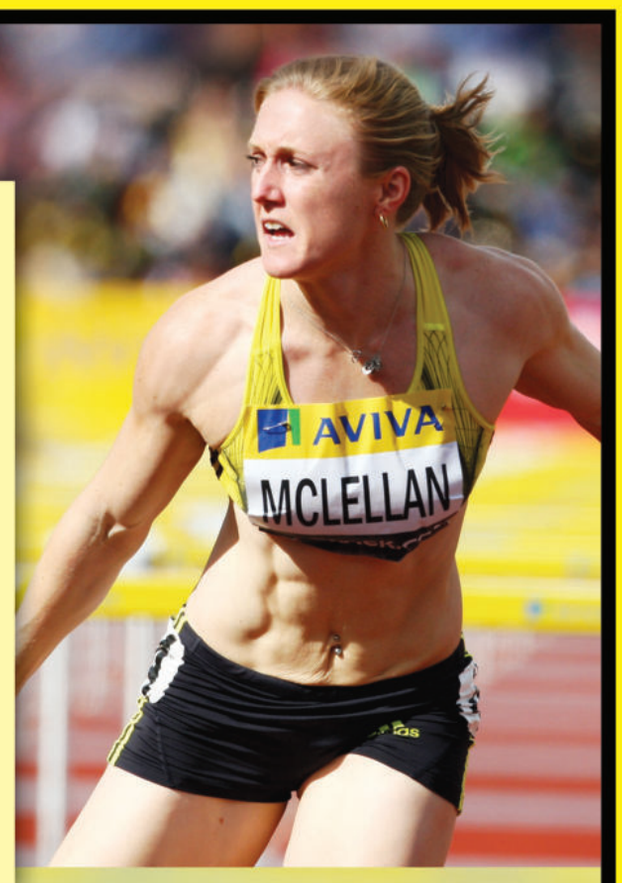

द वॉल की नई इमारत

मिस्टर भरोसेमंद यानी द वॉल राहुल द्रविड़ हाल ही में वर्ष 2011 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के इयान बेल को पीछे छोड़ दिया है. द्रविड़ के नाम पर अब इस साल दस मैचों में 952 रन हैं और वह बेल (आठ मैच में 950 रन) से आगे हो गए हैं. इस सीनियर बल्लेबाज़ को वेस्टइंडीज के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट के पहले दिन अंतिम क्षणों में काम चलाऊ स्पिनर क्रेग ब्राथवेट ने बोल्ड किया. भारतीय दीवार ने इस साल अब तक पांच शतक जड़े हैं. इनमें से दो शतक उन्होंने वेस्टइंडीज तथा तीन शतक इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लगाए हैं. उन्होंने इस साल 59.50 की औसत से रन बनाए हैं. ग़ौरतलब है कि उनके साथ ही वीवीएस लक्ष्मण ने भी शतक के साथ वेस्टइंडीज के ख़िलाफ़ 1500 रन पूरे किए. राहुल के इस रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस वॉल के सहारे अभी कई और इमारतों का खड़ा होना बाक़ी है.

गौतम का गंभीर प्रयास

गौतम गंभीर ने मैदान के बाहर भी ऐसी मिसाल पेश की, जिसे जिसने भी सुना वह गंभीर के सामने नतमस्तक हो गया. दरअसल, गौतम गंभीर ने अपने अंग दान करने की शपथ ली है. अपने इस फ़ैसले पर गंभीर ने कहा कि अगर उनकी यह छोटी सी कोशिश किसी के अंधेरे जीवन में उजाला ला सकती है तो यह उनके लिए सौभाग्य की बात होगी. गौतम गंभीर अपोलो ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के अभियान गिफ्ट ए लाइफ की वेबसाइट की ओपनिंग सेरोमनी में पहुंचे थे. गंभीर ने कहा कि वह चाहते हैं कि देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़ें, ताकि कई लोगों की ज़िंदगी को रौशन किया जा सके. उन्होंने कहा, इस बारे में लोगों में जागरूकता फ़ैलाने की ज़रूरत है. देश में लाखों लोगों को अंग प्रत्यारोपण की ज़रूरत है, लेकिन उस हिसाब से अंग उपलब्ध नहीं हैं. मैं मीडिया से भी अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में देश में जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाए. साथ ही गंभीर ने कहा कि वह अपने क्रिकेट के साथियों से भी कहेंगे कि वे इस मामले में उनका साथ दें. मानना पड़ेगा कि गंभीर बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ-साथ बेहतरीन इंसान भी हैं.

फोर्स इंडिया का दम

सहारा फोर्स इंडिया के ड्राइवर एड्रियन सुतिल ने अबु धाबी ग्रां प्री फार्मूला वन रेस में आठवां और उनके साथी पाल डि रेस्टा ने नौवां स्थान हासिल किया. यह तीसरा अवसर है जब फोर्स इंडिया के दोनों ड्राइवर शीर्ष दस में रहे. इससे उसने टीम चैंपियनशिप में छठे स्थान पर अपनी स्थिति मज़बूत कर ली. फोर्स इंडिया को आज छह अंक मिले और उसके अब 57 अंक हो गए. उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी सौबर से अब 15 अंक अधिक हैं, जबकि इस साल केवल एक रेस ही बची है. विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटेल के लिए यह रेस दुर्भाग्यपूर्ण रही. उन्हें इंजन की ख़राबी के कारण दूसरे लैप से ही बाहर होना पड़ा. यह पिछले साल कोरियाई ग्रां प्री के बाद पहला अवसर है, जबकि वेटेल को बीच में रेस छोड़नी पड़ी. मैकलारेन के ब्रिटिश ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने इसका फ़ायदा उठाकर इस सत्र की तीसरी रेस जीती. उन्होंने ग्रिड में दूसरे नंबर से शुरुआत की थी. हैमिल्टन के बाद फेरारी के फर्नांडो अलोंसो और उनके साथी जेनसन बटन रहे. वेटल के हटने से सुतिल और डि रेस्टा अपनी मूल ग्रिड पोजीशन से एक स्थान ऊपर बढ़ने में सफल रहे. सुतिल ने मर्सीडीज के माइकल शुमाकर पर काफ़ी दबाव बनाया. डि रेस्टा को भी नौवें स्थान के लिए टोरो रोसो के सेबेस्टियन बुइमी से कड़ी टक्कर मिली. बुइमी आख़िरी क्षणों में रेस से हट गए.

सोमदेव का निचला पायदान

लगता है कि टेनिस खिलाड़ी सोमदेव के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं. भारतीय टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन हाल ही में जारी एटीपी वर्ल्ड सिंगल्स टेनिस रैंकिंग में चार पायदान खिसककर 83वें स्थान पर पहुंच गए हैं. सोमदेव के एटीपी एकल रैंकिंग में 631 अंक हैं. सानिया मिर्ज़ा डब्ल्यूटीए रैंकिंग में अपने 88वें स्थान पर बरक़रार हैं. लेकिन भारतीयों की डबल्स रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है. टॉप 10 में शामिल महेश भूपति (6670 अंक) सातवें और लिएंडर पेस (4950 अंक) आठवें स्थान पर बने हुए हैं. रोहन बोपन्ना भी अपने 16वें स्थान पर क़ाबिज़ हैं. एटीपी सिंगल्स रैंकिंग में टॉप 10 में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसमें सर्बिया के नोवाक जोकोविच शीर्ष, रफ़ेल नडाल दूसरे और एंडी मरे तीसरे स्थान पर बरक़रार हैं. उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही उनकी रैंकिंग में कुछ सुधार होगा.

बदलाव का आनंद

विश्वनाथन आनंद का मानना है कि भारत में खेल के प्रति लोगों की आम धारणा में बदलाव आया है और इसका फ़ायदा उठाना होगा. इंडियन ग्रां प्री की सफलता पर ज़ोर देते हुए आनंद ने कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ समय में खेलों के प्रति भारतीयों के रवैये में बदलाव आया है. हाल में फार्मूला वन ही नहीं, बल्कि आप देख सकते हैं कि लोग धीरे-धीरे विविध खेलों को पसंद कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि शतरंज में हमें भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए. अपने विश्व ख़िताब की रक्षा के लिए अगले साल मई में मास्को के निकट स्कोलकोवो फाउंडेशन में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता इस्राइल के बोरिस गलफेंड का सामना करने वाले आनंद ने कहा कि यह मुश्किल मुक़ाबला होगा और उन्हें इस मुक़ाबले के लिए तैयार होने की ज़रूरत है. यहां एनआईआईटी विश्वविद्यालय के तीसरे वार्षिक समारोह के इतर आनंद ने कहा कि विरोधी काफ़ी कड़ा है, आपको अच्छी तैयारी करनी होगी. लेकिन आप कितनी भी तैयारी करो, बाज़ी का फ़ैसला शतरंज बोर्ड पर ही होता है. इसलिए आपको सिर्फ़ कड़ी मेहनत ही हारने से बचा सकती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

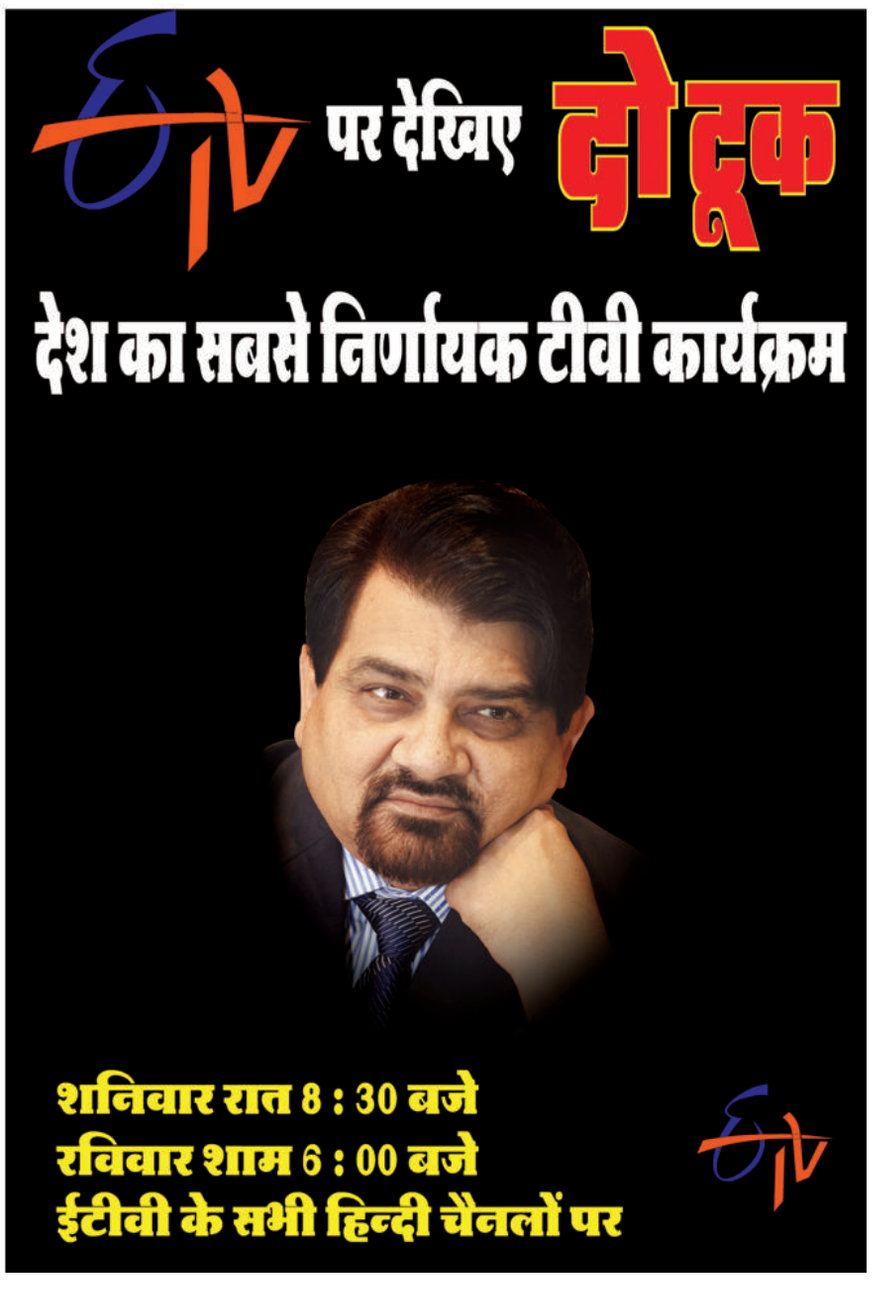

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 28 नवंबर-04 दिसंबर 2011

रोडीज और बिग बॉस के विजेता रह चुके आशुतोष कौशिक की क़रीबी दोस्त रह चुकी सोनेल आम जीवन में जैसी तेज़ तर्रार हैं वैसा ही चरित्र अभिनीत किया है उन्होंने फिल्म जीत लेंगे जहां में.

लड़की या बुलेट

बॉलीवुड की फिल्मों में पिछले कुछ समय से ट्रेंड चल गया है विदेशी फिल्म इंडस्ट्री की हिरोइंस को लेकर फिल्म बनाने का, लेकिन बॉलीवुड न केवल विदेशी हिरोइंस को प्रोमोट करता रहा है, बल्कि देश की दूसरी भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री से भी हिरोइंस को मौक़ा देता रहा है. उदाहरण के तौर पर अजय देवगन की फिल्म सिंघम की काजल अग्रवाल को देख सकते हैं. इसी तरह इस बार पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक नामी चेहरे को भी जल्द ही हिंदी फिल्म में अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाते देखेंगे. रोडीज फेम सोनेल सिंह ने यूं तो कई पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन अब वह हिंदी फिल्मों में भी काम कर रही हैं. रोडीज और बिग बॉस के विजेता रह चुके आशुतोष कौशिक की क़रीबी दोस्त रह चुकी सोनेल आम जीवन में जैसी तेज़ तर्रार हैं वैसा ही चरित्र अभिनीत किया है उन्होंने फिल्म जीत लेंगे जहां में. इस फिल्म में उनका नाम भी बुलेट है. फिल्म के निर्देशक ललित कहते हैं कि सोनेल जैसी रियल लाइफ में हैं वैसी ही फिल्म में भी उनका चरित्र है. इसीलिए उनका नाम फिल्म में बुलेट रखा गया है. अशोका मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी एक रोमांटिक फिल्म है जीत लेंगे जहां, जिसके निर्माता हैं संजू सिंह. फिल्म की पटकथा लेखन का ज़िम्मा निभाया है ख़ुद फिल्म के निर्देशक ललित एम बिष्ट ने. फिल्म में अभिनय करने वाले कलाकारों में मुख्य हैं अशोक शुक्ला, नीलाम्बरी पेरूमल, गोल्डी सुमेल, पारस सिंह मिन्हास, एना, सोनेल सिंह आदि.

घायल रिटर्न्स का निर्देशन

सनी देओल अपनी होम प्रोडक्शन विजयता फिल्म से घायल रिटर्न्स बना रहे हैं. 1990 में हिट हुई घायल का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया था. अब घायल रिटर्न्स यह हिट फिल्म घायल का ही सीक्वल है. अश्विनी चौधरी इस फिल्म का निर्देशन करने वाली थीं, तथा उन्होंने फिल्म का एक प्रोमो भी रिलीज किया था. पर अब वह यह फिल्म नहीं करेंगी. सनी देओल ने यह प्रोजेक्ट अपने दोस्त राहुल रवैल को दे दिया है. अब सनी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, यह तो ख़ुद वह ही जानते होंगे, मगर सूत्रों का कहना है कि अश्विनी अपनी कई फिल्मों को लेकर व्यस्त हैं, जिसकी वजह से वह घायल रिटर्न्स के लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं. इसलिए सनी ने यह फिल्म राहुल रवैल को सौंप दी. घायल रिटर्न्स द्वारा राहुल विजयता फिल्मस की फिल्म का निर्देशन 28 साल बाद करने वाले हैं. इससे पहले उन्होंने इस बैनर की 1983 में आई बेताब फिल्म का निर्देशन किया था. ग़ौर करने वाली बात यह है कि सनी देओल ही इस फिल्म में मुख्य किरदार में होंगे.

उभरते गायक विपिन

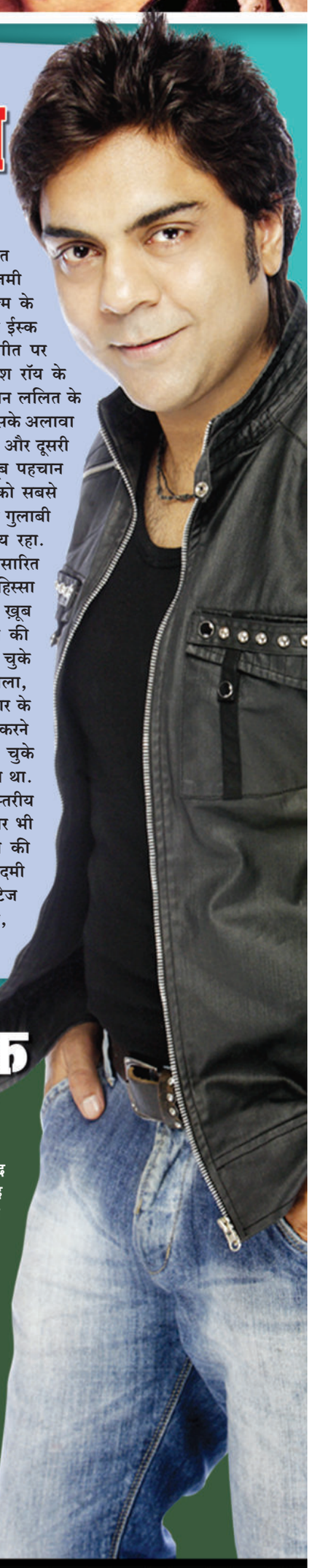

मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाये गीत गुलाबी आंखें के रीमिक्स गीत को गाकर श्रोताओं के बीच लोकप्रिय हुए गायक विपिन अनेजा ने पिछले दिनों रिलीज़ हुई निर्देशक तिग्मांशु धूलिया की हिंदी फ़िल्म साहब बीबी और गैंगस्टर में थीम सॉन्ग गाया है. यह गीत शुरू से आख़िर तक फ़िल्म की हर सिचुएशन में है. दरअसल फ़िल्म में जब लीड एक्टर जिमी शेरगिल की एंट्री होती है तब यह शुरू होता है और आख़िर तक चलता है. इस फ़िल्म के अलावा विपिन कई अन्य फिल्मों में भी गीत गा रहे हैं जैसे ईस्क, नई सुबह. फ़िल्म ईस्क में उन्होंने संगीतकार रवि पवार के संगीत निर्देशन में उत्तर प्रदेश के लोक संगीत पर आधारित गीतों को गाया है. इसके अलावा फ़िल्म नई सुबह में भी राजेश रॉय के संगीत निर्देशन में भी उन्होंने एक गीत गाया है. राजेश रॉय संगीतकार जतिन ललित के असिस्टेंट रह चुके हैं. फिल्मों में तो विपिन गीतों को गा ही रहे हैं, इसके अलावा उनके कई एलबम भी रिलीज़ हो चुके हैं, जिनमें से एक है तेरी पायल और दूसरी है सैल्यूट टू बॉलीवुड. दोनों ही एलबम में उनकी क्षमता को ख़ूब पहचान मिली. एलबम सेल्यूट टू बॉलीवुड के गीत ज़मीं गा रही है, को सबसे ज़्यादा नार्वे में डाउनलोड किया गया और इसी एलबम के गीत गुलाबी आंखें रीमिक्स गीत चैनल वी पर सबसे अधिक लोकप्रिय रहा. देश-विदेश में अनेक शो कर चुके विपिन ने कलर्स पर प्रसारित होने वाले संगीत के कार्यक्रम आइडिया रॉक्स इंडिया में हिस्सा लिया और यहां भी उनके सूफ़ी गीतों को श्रोताओं ने ख़ूब पसंद किया. कजाकिस्तान में विश्व पॉप गायिकी की प्रतियोगिता में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर चुके विपिन को न सिर्फ़ अपने देश के लिए पुरस्कार मिला, बल्कि साथ में एआर रहमान जैसे महान संगीतकार के साथ यूनिटी ऑफ़ लाइट पीस कंसर्ट में काम करने का अवसर भी मिला. अनेक जिंगल्स गा चुके विपिन का बचपन से ही संगीत की ओर रुझान था. दस वर्ष की आयु में उन्होंने दिल्ली की राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता में भाग लिया और पुरस्कार भी जीता. संगीत में ही अपने करियर को बनाने की चाहत रखने वाले विपिन ने न्यूयॉर्क स्टेट अकादमी से एमबीए में पोस्ट ग्रेजुएट किया. विपिन ने स्टेज पर तो ए आर रहमान के साथ काम किया है, लेकिन उनके संगीत निर्देशन में भी काम करने की चाहत है उनकी.

करिश्मा का करिश्मा

कुछ समय पहले तक करिश्मा ख़ुश दिखाई नहीं दे रही थीं लेकिन अब उनके चेहरे पर खिली मुस्कान साफ देखी जा सकती है. हाल ही में करिश्मा ने पति के परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाए हैं और कुछ तस्वीरें उन्होंने बहन करीना कपूर को भी भेजी हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर एक बार फिर अपनी टूटती शादी को बचाने की जुगत में जुटी हैं. उन्होंने इस बार दीपावली पति संजय कपूर और बच्चों के साथ दिल्ली में मनाई. वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आने के बाद वह पति से तलाक लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन लगता है अब उनका इरादा बदल गया है. सूत्रों ने बताया कि करिश्मा दिल्ली में पति और बच्चों के साथ क़रीब एक हफ्ते तक रहीं. उन्हें लंबे समय बाद इतना ख़ुश देखा गया. उन्होंने अपने पति और बच्चों के साथ फोटो खिंचवाकर अपनी बहन करीना को भी भेजे. करीना इन दिनों लंदन में हैं.

उल्लेखनीय है कि अभिषेक बच्चन से अलगाव के बाद करिश्मा ने संजय से 2003 में शादी की थी. संजय ने भी अभिनेत्री से शादी से कुछ दिन पहले ही अपनी पहली फैशन डिज़ाइनर पत्नी नंदिता मेहतानी से तलाक़ लिया था. 2005 में पहली बेटी के जन्म के समय से ही कहा जा रहा था कि दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ रही है. इसका कारण न्यूयॉर्क के नामी व्यवसायी की पूर्व पत्नी के साथ संजय की नज़दीकियां बताई गई थीं. पिछले साल मार्च में एक बेटा होने के बाद पति से अनबन के चलते करिश्मा ने मुंबई का रुख़ कर लिया और बच्चों के साथ बांद्रा में रहने लगीं. अब उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी दूसरी पारी शुरू कर दी है. वह निर्देशक विक्रम भट्ट की फिल्म डेंजरस इश्क से वापसी कर रही हैं. इसके अलावा वह सत्ते पे सत्ता की रीमेक में भी मुख्य भूमिका में हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म बना रहे हैं विवेक

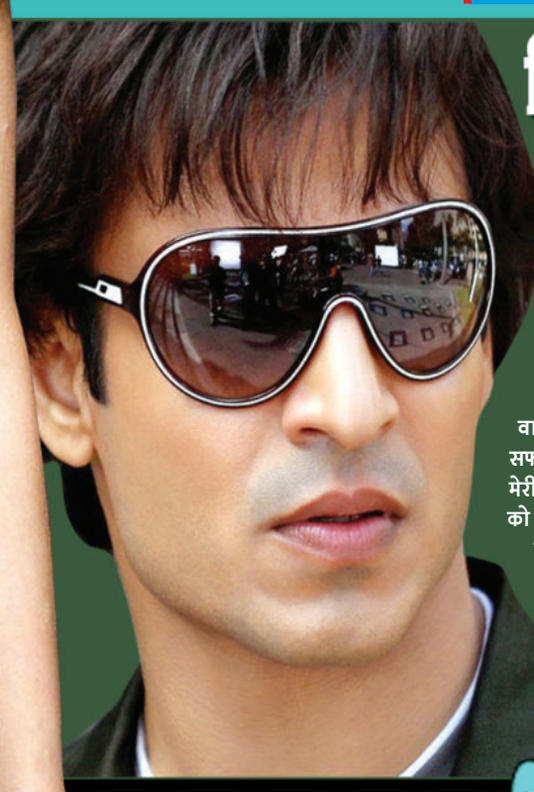

मेनस्ट्रीम सिनेमा में सफलता की ऊंचाइयों तक न पहुंच पाने वाले एक्टर्स बॉलीवुड में ही रहकर कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे वे सफलता के क़रीब पहुंच सकें. फीमेल एक्टर्स आइटम सॉन्ग, बॉडी शो या लीक से हटकर फिल्म में रोल प्ले करके ख़ुद को स्थापित करना चाहती हैं तो मेल एक्टर्स भी अलग तरह के रोल अदा करके ख़ुद को इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच प्रूव करने की कोशिश करते हैं. सफलता के क़रीब पहुंचने की कोशिश करने वाले अभिनेता विवेक ओबरॉय ने भी ख़ुद को रीइस्टैबलिश करने के लिए कुछ हटकर करने की कोशिश की है. दरअसल वह एक ख़ास तरह की फिल्म निर्माण की तैयारी में हैं. विवेक ओबरॉय का कहना है कि वह वास्तविक भारत को दिखाने के लिए सिनेमा बना रहे हैं. उन्होंने कहा, मैं अपनी सफलता का इस्तेमाल उन चीज़ों में कर रहा हूं, जो बॉलीवुड नहीं करता है. उन्होंने कहा, मेरी फिल्म की कहानी वैसी नहीं है, जैसी कि लोग अब तक देखते आए हैं. यह चीज़ों को अलग नज़रिये से देखने से जुड़ा हुआ है न कि धन कमाने से. बतौर निर्माता वॉच इंडियन सर्कस विवेक की पहली फिल्म है. फिल्म को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने फिल्म का प्रीमियर एक फिल्म समारोह में ही शेड्यूल कर दिया. इस समारोह के मुख्य पुरस्कार न्यू करेंट्स की दौड़ में शामिल हैं. विवेक की इस फिल्म का निर्देशन मंगेश हादावले ने किया है और इसमें ग़रीबी में जीवन गुज़ार रहे एक दंपत्ति की कहानी है. इस दंपत्ति का सपना है, अपने बच्चों के साथ सर्कस देखना. विवेक ने कहा, मेरा मानना है कि यह फिल्म भारत की आत्मा का प्रतीक है.

फिल्म प्रीव्यू

डर्टी पिक्चर्स

बालाजी मोशन पिक्चर्स और एएलटी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी फिल्म डर्टी पिक्चर्स दक्षिण की सुपर स्टार विजयालक्ष्मी उर्फ़ सिल्क स्मिता की कहानी है. फिल्म की निर्माता हैं एकता कपूर और शोभा कपूर. फिल्म के निर्देशक हैं मिलन लुथारिया और संगीत दिया है विशाल-शेखर ने. मुख्य कलाकार के तौर पर फिल्म में नज़र आएंगे विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी और तुषार कपूर. सुपर स्टार विजयालक्ष्मी उर्फ़ सिल्क स्मिता ने एक मेकअप गर्ल की हैसियत से फिल्मी दुनिया में क़दम रखा था, लेकिन जल्दी ही वह बी-ग्रेड फिल्मों की टॉप हीरोइन बन गईं. पोस्टर पर सिल्क स्मिता का नाम देखकर लोग टिकट ख़रीद लेते थे. उत्तेजक आइटम नंबर और बोल्ड दृश्यों की वजह से उन्हें सॉफ्ट पोर्न एक्ट्रेस भी कहा जाने लगा. अचानक मिली सफलता को सिल्क ठीक से संभाल नहीं पाईं. आर्थिक संकट और प्यार में मिले धोखे के बाद वह शराब में डूब गईं. रहस्यमयी परिस्थितियों में मात्र 36 वर्ष की उम्र में वह अपने चेन्नई स्थित अपार्टमेंट में मृत पाई गईं. सिल्क की इसी कहानी से प्रेरित होकर द डर्टी पिक्चर बनाई गई है. सिल्क के शुरुआती संघर्ष से लेकर तो 80 के दशक का वह दौर दिखाया गया है जब बॉक्स ऑफिस पर सिल्क के नाम का डंका बजता था. सिल्क के जीवन के उतार-चढ़ाव और शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी को कलरफुल और मनोरंजक तरीक़े से दिखाया गया है. निर्देशक मिलन लुथारिया ने जहां एक ओर कच्चे धागे (1999), दीवार (2004), टैक्सी नं. 9211 (2006) और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई (2010) जैसी फिल्में बनाई हैं तो दूसरी ओर चोरी-चोरी (2003) और हैट्रिक (2007) जैसी कमज़ोर फिल्में भी उनके खाते में हैं. मिलन एक अच्छे निर्देशक हैं, इसके बावजूद उनका नाम बॉलीवुड के टॉप निर्देशकों में नहीं लिया जाता है. उनकी पिछली फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई. 1970 और 80 के दशक को उन्होंने उम्दा तरीक़े से स्क्रीन पर पेश किया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 28 नवंबर-04 दिसंबर 2011

www.chauthiduniya.com

लवासा को मंज़ूरी

जनता के साथ धोखा

राजेश नामदेव

महाराष्ट्र सरकार पुणे ज़िले के मुलशी तहसील में विवादित निर्माणाधीन लवासा लेक सिटी को लेकर भ्रम की स्थिति में नज़र आ रही है. उसकी स्थिति उस सांप की तरह नज़र आ रही है, जो छछूंदर को न तो निग़ल पा रहा है और न ही उगल पा रहा है. सरकार का पर्यावरण मंत्रालय कुछ और कहता है और मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं. लवासा को लेकर सरकार दो हिस्सों में बंटी दिखाई देती है. आधा मंत्रिमंडल जहां लवासा के ख़िलाफ़ है, वहीं आधा उसके पक्ष में. जो लवासा के पक्ष में है, वह सरकार पर ज़बरदस्त दबाव बनाए हुए है. वह हर हालत में लवासा में व्याप्त अनियमितताओं को नज़रअंदाज़ कर सरकार से क्लीन चिट देने को कह रहा है, जबकि मामला मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है. इन स्थितियों में कभी सरकार लवासा कार्पोरेशन के संचालकों व अधिकारियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराती है तो कभी उसके पहले चरण को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति दिए जाने की वकालत करती है. सरकार की इस दुविधा का कारण क्या है? हालांकि, एक बात कॉमन है कि राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के दो बड़े घटक दलों में लवासा को लेकर बेचैनी साफ देखी जा रही है. इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए मुंबई से दिल्ली तक हलचल है.

लवासा को लेकर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी खेल चल रहा है. राज्य सरकार की दुविधा इस बात पर नज़र आती है कि बीते 2 नवंबर, 2011 को राज्य के पर्यावरण मंत्री संजय देवतले का बयान आता है कि एक-दो दिन में लवासा कार्पोरेशन द्वारा की गई गड़बड़ियों के ख़िलाफ़ पुणे की अदालत के समक्ष क़ानूनी कार्रवाई करने की सरकार की तैयारी है. विगत 4 नवंबर को लवासा कार्पोरेशन के 9 संचालकों के साथ ही 15 लोगों के ख़िलाफ़ पुणे के मुख्य न्यायाधीश एन.टी. घाडगे के समक्ष फ़ौजदारी मामला पेश किया जाता है. इसी दिन दिल्ली में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एक टी.वी. चैनल पर साक्षात्कार देते हुए लवासा के पहले चरण को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन से पर्यावरणीय मंज़ूरी देने का अनुरोध करने की बात कहते हैं. उसके पांचवें दिन पता चलता है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लवासा के पहले चरण के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान कर दी है. ध्यान देने वाली बात यह है कि लवासा द्वारा नियम-क़ायदों का उल्लंघन करने संबंधी मामला मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष चल रहा है. न्यायालय के आदेश पर लवासा कार्पोरेशन के 15 अधिकारियों के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मामला दर्ज किया गया है. इसके बावजूद राज्य व केंद्र सरकार द्वारा लवासा को निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति देना आश्चर्य से कम नहीं है. पता नहीं एक साल में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के बदलते ही पर्यावरण मंत्रालय के रुख में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया, जबकि लवासा कार्पोरेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण क़ानून 1986 का उल्लंघन करने पर रोक उसी ने लगाया था, लेकिन जयराम रमेश के जाते और जयंती नटराजन के पर्यावरण मंत्री बनते ही लवासा कार्पोरेशन ने ऐसा क्या कार्य किया कि उसके सारे पाप धुल गए और कुछ दिखावटी शर्तों के साथ उसको मंज़ूरी दी गई.

यह जगज़ाहिर है कि लवासा लेक सिटी मराठा क्षत्रप राकांपा सुप्रीमो व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की ड्रीम सिटी है. इसे साकार करने का कारभार भी शरद पवार ने अपने मित्र अजीत गुलाबचंद को सौंपा है, जो लवासा कार्पोरेशन के अध्यक्ष हैं. वर्ष 2010 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने पर्यावरण संरक्षण क़ानून का उल्लंघन होने पर लवासा लेक सिटी के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया था तभी से शरद पवार व उनके मित्र अजीत गुलाबचंद की बेचैनी बढ़ गई थी. शरद पवार ने तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के प्रति नाराज़गी जाहिर की थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से शिकायत भी की थी. उसके बाद लवासा प्रकरण न्यायालय में चला गया. न्यायालय के कड़े रुख के कारण महाराष्ट्र सरकार ने जिस लवासा लेक सिटी के निर्माण को मंज़ूरी दी थी, उसी के ख़िलाफ़ उसे मामला दर्ज करना पड़ा. इससे लवासा कार्पोरेशन की परेशानी और बढ़ गई. अब सवाल उठता है कि सरकार जिस लवासा कार्पोरेशन को लवासा लेक सिटी निर्माण में नियम-क़ायदों का उल्लंघन करने का दोषी मानती है, उसे निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति प्रदान करने की वकालत करने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय क्यों गए? यह सरकार का कैसा विरोधाभास है. लवासा कार्पोरेशन के जिन अधिकारियों के ख़िलाफ़ पर्यावरण संरक्षण क़ानून की धारा 15 और 16 का उल्लंघन करने पर मामला पुणे की अदालत में पेश किया गया उनमें लवासा कार्पोरेशन के अध्यक्ष अजीत गुलाबचंद, संचालक अनिरूद्ध देशपांडे, अनुराधा जितेंद्र देसाई, गौतम थापर, योजना संयोजक अंबुजा जैन, मुख्य संयोजक एस.पी. पेंढारकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. नारायण, ज्ञानदेव घोरपड़े, विट्ठल मनियार व अन्य अधिकारी शामिल हैं. इसके बावजूद मुख्यमंत्री का लवासा का पक्ष लेना अपनी ही सरकार का विरोध करना नहीं तो और क्या कहा जाएगा? मुख्यमंत्री चव्हाण विकास कार्यों संबंधी फाइल इस लिए रोके रखते हैं कि उनके दामन में भ्रष्टाचार का दाग़ न लगे, जबकि लवासा लेक सिटी निर्माण में प्रारंभ से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं. उसके बाद भी वे उसकी वकालत करने पर्यावरण मंत्रालय पहुंच गए.

अब सवाल उठता है कि सरकार जिस लवासा कार्पोरेशन को लवासा लेक सिटी निर्माण में नियम-क़ायदों का उल्लंघन करने का दोषी मानती है, उसे निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति प्रदान करने की वकालत करने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय क्यों गए?

हक़ीक़त यह है कि लवासा, तपासा (उसके निर्माण कार्यों की जांच) और टप्पासा (पहले चरण के निर्माण कार्य को पर्यावरणीय मंज़ूरी दिया जाना) की स्मार्ट राजनीति का खेल लवासा लेक सिटी को लेकर खेला जा रहा है. शरद पवार की स्मार्ट राजनीति के आगे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बौने साबित हुए हैं. पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि के बाद तृणमूल कांग्रेस द्वारा सरकार को धमकाने और 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में डीएमके की नाराज़गी से संकट में घिरी केंद्र सरकार से अपनी

(शेष पृष्ठ 18 पर)

लवासा पर अन्ना हज़ारे का ख़त

वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हज़ारे का प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लवासा लेक सिटी के मुद्दे पर लिखा गया वह पत्र जिसके कारण अंतत 26 नवंबर, 2010 को पर्यावरण मंत्रालय ने लवासा शहर में निर्माण पर रोक लगा दी थी. इस पत्र से लवासा के निर्माण कार्य में किस तरह संवैधानिक व्यवस्था को धता बताया गया है, यह स्पष्ट हो जाता है.

माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी
प्रधानमंत्री , भारत सरकार
साउथ ब्लॉक , रायसीना रोड
नई दिल्ली-110001
माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी

विषय- एक कंपनी लवासा कार्पोरेशन लिमिटेड महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में मुलशी और वेल्हे तालुका टाउनशिप प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है.

मुझे आपको यह बताते हुए अफ़सोस हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत वारसगांव डैम की 25000 एकड़ ज़मीन को महाराष्ट्र के भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट नौकरशाहों की मदद से इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया. इस इलाक़े में घने जंगल, नदियां और ग्रीन हिल हैं. इसका प्रयोग ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से किया गया. इस प्रोजेक्ट में सरकारी मशीनरी का प्रयोग ग़लत तरीके से किया गया. इस प्रोजेक्ट ने मोस वेली में 20 पूरी तरह बसे हुए गांवों को प्रभावित किया और हज़ारों लोगों को इसकी वजह से विस्थापित होना पड़ा है. आदिवासी, किसान, ग़रीब लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. इनमें से जिस किसी ने विरोध किया उसे कंपनी द्वारा धमकाया गया. दुर्भाग्य से महाराष्ट्र सरकार से ये उम्मीद की गई थी कि ये कमज़ोर वर्गों के हित में काम करेंगे, लेकिन यह प्राइवेट कंपनी के दास निकले.

यह काफ़ी दुख की बात है कि महाराष्ट्र का नेतृत्व अपने ग़रीब लोगों के संवैधानिक हितों की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं था. इसके बजाय वह प्राइवेट कंपनी के सभी तरह के लुभावने ऑफरों को स्वीकार करने में लगा था.

महाराष्ट्र सरकार ने किया नियमों और संविधान का उल्लंघन

वर्ष 1996 में महाराष्ट्र सरकार ने एक नई पर्यटन नीति की घोषणा की. वर्ष 2001 में जब कांग्रेस-राकांपा सत्ता में वापस आई, तब लवासा कार्पोरेशन लिमिटेड को हिल स्टेशन को कंपनी के मुख्य प्रपोजल के तौर पर विकसित करने की आज्ञा दी गई.

तब इसे लेक सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था. यहां पर ये बता देना आवश्यक होगा कि इसके लिए कोई टेंडर भारत सरकार द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया. किसी भी

(शेष पृष्ठ 18 पर)

लवासा पर लगने वाले आरोप

लवासा लेक सिटी परियोजना मुंबई से 190 किलोमीटर और पुणे से 65 किलोमीटर दूर करीब 25,000 एकड़ में फैली है. इसके निर्माण कार्य के शुरूआत से ही पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने व अन्य आरोप लगते रहे हैं.

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक कंपनी ने पुणे की मुलशी और वेले तहसीलों में हिल स्टेशन स्थापित करने के लिए वर्ष 2002 में राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया था.
- अनापत्ति प्रमाणपत्र को वर्ष 2004 में पर्यावरण मंज़ूरी में बदला गया और परियोजना को 2,000 एकड़ तक सीमित किया गया.
- मंत्रालय ने कहा है कि परियोजना में मंज़ूर की गई ऊंचाई से कहीं अधिक ऊंचाई पर निर्माण किया गया है.
- 10 जून को तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने महाराष्ट्र सरकार को कहा था कि लवासा कार्पोरेशन के ख़िलाफ़ ज़रूरी कदम उठाए जाएं, क्योंकि बिना हरी पट्टी छोड़े निर्माण कार्य चल रहा था. इस सिलसिले में पर्यावरण मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार को ख़त लिखा था, जिसमें कहा गया था कि बिना पर्यावरण मंत्रालय की मंज़ूरी के 681 हेक्टेयर में निर्माण कार्य जोरों से शुरू है.

केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय का राज्यमंत्री पद उनके पास था. पिछले कुछ वर्षों में जब भी राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की बात हुई, तब जिन चार-पांच नेताओं के नाम सामने आते थे, उनमें पृथ्वीराज चव्हाण का नाम ज़रूर शामिल होता था.

गन्ना उत्पादकों को न्याय मिला, लेकिन विदर्भ के कपास-धान उत्पादकों को न्याय मिलना अभी बाक़ी है, लेकिन राजू शेट्टी जैसा कोई नेता विदर्भ में नज़र नहीं आता है.

महाराष्ट्र हलचल

मन्ने की क़ीमत बढ़ाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अनशनरत सांसद राजू शेट्टी ने मांग पूरी होने पर बालक के हाथों जूस पीकर अनशन ख़त्म किया.

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण नागपुर प्रीमियर लीग फुटबॉल स्पर्धा के अवसर पर पुरुष सत्र के लिए लोकमत मीडिया के चेयरमैन सांसद विजय दर्डा को शुभकामनाएं देते हुए.

स्थानीय निकाय चुनाव

राकांपा और कांग्रेस में हलचल तेज़

युधिष्ठिर जोशी

महाराष्ट्र की 192 नगरपालिकाओं और 4 नगरपंचायतों के चुनाव दिसंबर माह में होंगे. इसे विधानसभा चुनाव के ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है. कांग्रेस के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व को नवंबर माह में एक वर्ष पूरा हो गया है. हालांकि राज्य की कमान संभालने के लिए एक वर्ष काफ़ी कम कालावधि होती है, लेकिन फिर भी चावल का एक दाना ही पूरे पके हुए चावल की कहानी बयां कर देता है. इस स्थिति का यदि विश्लेषण किया जाए, तो पृथ्वीराज चव्हाण का यह एक वर्ष निराशाजनक ही रहा है. वे उच्च शिक्षित हैं. केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय का राज्यमंत्री पद उनके पास था. पिछले कुछ वर्षों में जब भी राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की बात हुई, तब जिन चार-पांच नेताओं के नाम सामने आते थे, उनमें पृथ्वीराज चव्हाण का नाम ज़रूर शामिल होता था. उनकी मां प्रेमलाबाई कई वर्षों तक राज्य कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थीं. पिता केंद्र में राज्यमंत्री रहे. उनका कृषि, सिंचाई, मूलभूत सुविधाएं आदि विषयों में काफी गहरा अध्ययन था. पृथ्वीराज चव्हाण की शिक्षा विदेश में हुई. ऐसे में उन्हें विज्ञान और तकनीक की अच्छी जानकारी है. इतना उच्च शिक्षित मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को पहली बार मिलने के कारण कांग्रेस पार्टी के युवा वर्ग में शुरुआत में काफ़ी उत्साह था,लेकिन पिछले छह महीने से कांग्रेस पार्टी में निराशा बढ़ने लगी है. इसे स्वयं कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी स्वीकार करते हैं. मैंने क़रीब तीन महीने पूर्व इसी स्तंभ में कहा था कि मुख्यमंत्री ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन यह स्थिति 15 दिन भी नहीं टिक पाई. पृथ्वीराज चव्हाण ने मुख्यमंत्री पद स्वयं स्वीकार किया या फिर कांग्रेस हाईकमान ने राज्य में कोई और पर्याय नहीं देख, उन्हें ज़बरदस्ती यह ज़िम्मेदारी सौंपी. यह दुविधाजनक स्थिति फ़िलहाल कांग्रेस में दिख रही है. किसी भी विवाद, घोटाले में उनका नाम न फंसे, इसके लिए हमेशा पृथ्वीराज चव्हाण प्रयास करते हुए नज़र आते हैं. स्वच्छ प्रतिमा बनाए रखने की कोशिश में हालत यह है कि वे कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं. करता हूं, देखता हूं, अध्ययन करना होगा, सूचना मंगवानी होगी जैसे आश्वासन देकर वह केवल समय निकालने का प्रयास करने में लगे रहते हैं. इससे न सिर्फ़ अधिकारी व कांग्रेस और राकांपा के अन्य मंत्री, बल्कि जनता भी काफ़ी त्रस्त हो गई है. किसी भी मामले में या समस्या पर निर्णय नहीं लेना और विविध मंत्रालयों की फाइलों को अनिर्णित रखने से मंत्रालय के अधिकारी काफ़ी परेशान हो गए हैं.

पिछले एक वर्ष में कोई भी साहसिक निर्णय मुख्यमंत्री ने नहीं लिया है. पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में फार्मूला वन कार रेस हुई. इस रेस के लिए जिस तरह सेलिब्रिटी का जमावड़ा उत्तर प्रदेश में लगा, उससे सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश की ओर लग गई थी. इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में इतने अधिक पर्यटक आए कि इससे राज्य को करोड़ों रुपये के राजस्व का लाभ हुआ. हालांकि यदि देखा जाए, तो यह कार रेस महाराष्ट्र में होनी थी. इसके लिए कार रेस के आयोजकों ने राज्य [illegible]

[illegible] उत्तर प्रदेश में हुई. नया और युवा चेहरा के रूप में पृथ्वीराज चव्हाण की प्रतिष्ठा होने के बावजूद राज्य के कांग्रेसी नेता उनसे ख़ासे नाराज़ है. अब तो ख़बर है कि कांग्रेस हाईकमान भी उनकी कार्यप्रणाली से बेहद नाराज़ है. उधर, पृथ्वीराज चव्हाण के स्वभाव के एकदम उलट उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का स्वभाव और कार्यशैली है. उन्हें भी उपमुख्यमंत्री बने एक वर्ष पूरा हो गया है. शरद पवार के सानिध्य में अजीत पवार ने राजनीति की बारीकियां सीखीं हैं. कई वर्षों तक अलग-अलग विभागों का मंत्री पद संभालने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की ज़िम्मेदारी दी गई या कहें कि उन्होंने ख़ुद ही ले ली है. शरद पवार राज्य की राजनीति में पिछले कई वर्षों से ध्यान नहीं दे रहे हैं. ऐसे में उनके उत्तराधिकारी के रूप में अजीत पवार की ओर देखा जाता है. शरद पवार राज्य की हर नब्ज़ जानते हैं. उन्हें राज्य की समस्याओं की गहराई तक जानकारी है. उनकी प्रशासकीय कार्यकुशलता के कारण राज्य की कार्यप्रणाली पर उनकी छाप अलग ही दिखाई देती है. चाचा से (शरद पवार) ख़ुद को एक क़दम आगे दिखाने की जल्दी अजीत पवार में दिखाई दे रहा है. उप मुख्यमंत्री पद के बाद जल्द ही अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद के सपने आने लगे. युवा, आगे वाले को तुरंत जवाब देकर चुप करने में माहिर और निर्णय लेने में जरा भी देर नहीं करने की प्रतिमा के कारण राष्ट्रवादी का युवा वर्ग अजीत पवार की ओर आकर्षित हो रहा है. ऐसे में राष्ट्रवादी के पुराने और [illegible]

feedback@chauthiduniya.com

जनता के साथ धोखा

पृष्ठ 1 का शेष

मांग मनवाने का इससे अच्छा अवसर शरद पवार को मिलने वाला नहीं था. पिछले पखवाड़े राकांपा सुप्रीमो शरद पवार अपने सहयोगियों के साथ दस जनपथ में कांग्रेस सुप्रीमो के दरबार में जाकर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की कार्यशैली की शिकायत की थी. साथ ही सोनिया गांधी से लवासा लेक सिटी प्रोजेक्ट का मुद्दा भी रखा था. उसके बाद पेट्रोल की क़ीमतों में वृद्धि होते ही तृणमूल कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापसी की धमकी दे दी. राकांपा के कुछ नेताओं ने भी मूल्य वृद्धि पर अपनी नाराज़गी जाहिर की, लेकिन दूसरे दिन ही शरद पवार ने पेट्रोल के दामों में हुई वृद्धि को जायज ठहराया. हालांकि, इसके एवज में लवासा के पहले चरण को पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति दिए जाने का दिल्ली में सौदा हो चुका था. मुख्यमंत्री को मुंबई से दिल्ली उसी दिन बुलाया गया जिस दिन पुणे की अदालत में पर्यावरण संरक्षण क़ानून का उल्लंघन किए जाने का प्रकरण दाखिल किया गया. शाम को मुख्यमंत्री चव्हाण के कड़े तेवर ढीले पड़ गए. अचानक लवासा प्रकरण में पर्यावरण मंत्रालय के दृष्टिकोण में भी बदलाव आ गया. लवासा के पहले चरण को पूरा करने की मंजूरी मिल गई, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या सरकार के इस कदम से न्यायालय की अवमानना नहीं हुई है? भले ही केंद्र व राज्य सरकार ने राजनीतिक मजबूरी के चलते लवासा के पहले चरण को मंजूरी दिला कर अपना गठबंधन धर्म निभा दिया हो, लेकिन एक बात साफ हो गई कि वह राजनीतिक दबाव में नियम-क़ायदों को धता बताने वालों का भी साथ दे सकती है. वजह यह है कि लवासा एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके समर्थन की उसे सख्त जरूरत है. प्रधानमंत्री को आम आदमी के सपनों की बजाय अपने सहयोगी नेताओं, उद्योगपतियों, अफसरशाहों के सपनों की अधिक चिंता है. इसलिए जहां आम आदमी शासन-प्रशासन की ज्यादतियों से बेजार हो रहा है, वहीं नेता अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

लवासा पर अन्ना हज़ारे का ख़त

पृष्ठ 1 का शेष

कंपनी को मौक़ा नहीं दिया गया. सासंद सुप्रिया सुले (जो कि केंद्रीय कषि मंत्री शरद पवार की बेटी है) और सदानंद सुले (शरद पवार के दामाद है) के संयुक्त रूप से इस कंपनी में 21.97 प्रतिशत इक्विटी शेयर थे. ऐसे मे कृषि मंत्री शरद पवार इस प्रोजेक्ट में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे. भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अतिरिक्त जल्दबाजी में इजाज़त दी. इसके लिए ज़मीन के सारे नियमों का उल्लंघन किया गया. लोकल लोग, लंबे समय से इस क्षेत्र में रह रहे थे. उन्हें इस क्षेत्र से ताक़त और पैसे का प्रयोग कर बाहर फिंकवा दिया गया. कृषि भूमि जो कि उनकी जीविका का एकमात्र साधन थी, को लवासा ने छीन लिया. क़ानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आदिवासी ज़मीन को ग़ैर आदिवासी ज़मीन में बदला जाए. आदिवासियों की ज़मीन को ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से हड़प लिया गया. दुर्भाग्य की बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनके इस काम में हरसंभव सहायता की. इसने आदिवासियों ओर किसानों को बुरी स्थिति में पहुंचा दिया. उदाहरण के तौर पर पुणे के कलेक्टर ने भारत सरकार के रिवेन्यू डिपॉर्टमेंट को पत्र लिखकर कहा कि इस ज़मीन की ग्रांट लवासा को दे दिया जाए, अन्यथा इसका वितरण कर दिया जाए. यह वितरण लैंड सीलिंग एक्ट 1961 के तहत था.

अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि सीलिंग ज़मीन को लवासा को देने से 1.64 करोड़ रुपये सरकार के खाते में आएंगे और अगर ये ज़मीन ग़रीबों को दी जाती है तो उसे 1.02 लाख रुपये एकत्र होंगे. यहां पर इस बात का ध्यान दिला देना ज़रूरी होगा कि सीलिंग एक्ट के तहत ज़मीन भूमिहीन लोगों को दी जाती है न कि प्राइवेट फ़ायदा कमाने वाली कंपनी को. यह इस बात का उदाहरण है कि महाराष्ट्र सरकार के अफ़सर फ़ायदा कमाने वाले व्यवसायी हैं. मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि राज्य लोगों के भले के लिए काम कर रहा है? या एक प्राइवेट कंपनी है जो कि फ़ायदा और नुक़सान की चिंता करने वाली है. महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (भारत सरकार के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की सब्सिडी) ने ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से 141.5 हेक्टेयर ज़मीन की लीज कम दर पर ले ली. साथ ही पानी के अंदर की ज़मीन को एक उद्देश्य के लिए बेचा गया जो कि लवासा और भारत सरकार को ज्ञात था. इस कंपनी को 3.03 टीएमसी पानी स्थापित करने का अधिकार था जो कि पूरे पुणे शहर के लिए तीन माह तक पानी की सप्लाई कर सकता था. इस पानी के अतिरिक्त लवासा ने अप्रत्यक्ष रूप से बांध की क्षमता को भी कम कर दिया. इससे पुणे शहर की पानी की सप्लाई को ख़तरा हो गया. सबसे दुखद बात ये है कि रिवेन्यू मंत्री नारायण राणे का ये बयान कि लवासा की सभी अनियमितताओं को नियमित किया जाना चाहिए. यह वाकई में शर्म की बात है कि एक कैबिनेट मंत्री इस तरह की अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करें. यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और असवैधानिक है. कोई भी क़ानून मंत्री को इस तरह के अधिकार प्रदान नही करता.

राणे में इस बात का साहस नहीं है कि वह ये बताएं कि किस तरह की अनियमितताओं को पहचाना गया. राणे के पास इस बात का जवाब नहीं था कि जांच को कांफीडेंशियल क्यों रखा जाए? यह बिल्कुल शराबी व्यक्ति की तरह था जिसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वह क्या बयान दे रहा है. राणे ने खराब वक्तव्य दिया जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम और वैल्यू को धक्का पहुंचा रहा था. वह लोकतांत्रिक वैल्यू, आम आदमी के संवैधानिक अधिकार, स्थाई विकास और प्राकृतिक स्त्रोतों का संरक्षण जैसे मुद्दों को समझने में सक्षम नहीं थे. ऐसे में उन्होंने बिना सोचे- विचारे इस तरह का वक्तव्य दिया. अगर नारायण राणे सतत विकास चाहते हैं, तो उनको सलाह देनी चाहिए कि वह अपने गृह राज्य के गांव जैसे कि हिवरे बाज़ार और रालेगणसिद्धी घूमे जहां पूरा विकास शांति के साथ हो रहा है और उसमें समाज के अंतिम तबके का ख्याल रखा जा रहा है. वापस लवासा पर लौटते हैं. भारत सरकार ने लवासा को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी स्टेटस इश्यू किया था. यह महाराष्ट्र के रीजनल और टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत किया गया था. इसकी वजह से लवासा को लोकल सरकार ने इनटाइटलमेंट दे दिया और ये अपने बिल्डिंग प्लान को खुद बनाने क लिए सक्षम हो गई. आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने स्पेशल पावर किसी प्राइवेट कंपनी को दिए हैं. यह बेहद गंभीर मामला है जो कि संविधान की बुनियाद को चुनौती देते हैं. ऐसी सुविधाओं का ग़लत फ़ायदा उठाया गया. कोई भी ग़लत व्यक्ति किसी विशेष टेरीटरी का प्रयोग ख़तरनाक कामों जैसे कि आतंकवाद, नारकोटिक ड्रग प्रोडक्शन आदि के लिए कर सकता है. ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में अपनी सारी बुद्धि खो दी है. ऐसे में आपको गंभीर तरीक़े से हस्तक्षेप की आवश्यकता है और ऐसे में आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय राष्ट्रपति सरकार को जल्द से जल्द बर्ख़ास्त करें. सरकार भारत के संविधान से खिलवाड़ कर रही है और ऐसे में उसे बर्ख़ास्त किया जाना चाहिए.

भारत सरकार ने लवासा को अतिरिक्त फ़ायदे दिए

महोदय, मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि केंद्र सकरार ने भी लवासा को फ़ायदा पहुंचाने और उसका बचाव करने का काम किया, जबकि इससे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही थी. मैं इसे पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इसे 1994 के ईआईए नोटिफिकेशन के तहत कोई वैध क्लीयरेंस नहीं मिली थी और न ही ईआईए नोटिफिकेशन 2006 की कैटेगरी आठ के अंतर्गत क्लीयरेंस मिली थी. प्रोजेक्ट के कई हिस्सों का एलीवेशन हज़ार मीटर से अधिक था. ऐसे में इसे 1994 के ईआईए नोटिफिकेशन के तहत केंद्र सरकार से पर्यावरण क्लीयरेंस चाहिए थी. हालांकि प्रोजेक्ट से जुड़े लोग राज्य सरकार से क्लीयरेंस चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं था. दूसरी बात कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 4 जुलाई 2005 को एक पत्र के द्वारा सूचित किया था कि लवासा प्रोजेक्ट को किसी भी तरह की निर्माण की गतिविधि की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, जब तक कि इसे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन केटेगरी से इंवायरनमेंटल क्लीयरेंस न मिल जाएं.

हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया. वहीं पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भी इस पर किसी तरीके की कार्यवाही नहीं की. मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि माननीय मंत्री ने कोई कार्यवाही नहीं की जबकि इकोलॉजी का भयंकर तरीके से दोहन किया गया और इसका नुकसान हुआ. आश्चर्य की बात ये है कि जयराम रमेश ने इस मसले पर चुप्पी साधे रखी, जबकि वह नवी मुंबई एयरपोर्ट में पर्यावरण के बचाव के लिए बेहतर तरीके से काम कर रहे थे. इस संबंध में सभी तथ्य कार्यकर्ताओं के संज्ञान में लाए गए. प्रमुख बात ये है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप करने के लिए पूरी तरह सक्षम है. हालांकि मंत्रालय इस मसले पर पूरी तरह मौन रहा. लवासा के मसले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए. इसमें कई तरह के घोटालों की बात सामने आई, कई नियमों का उल्लंघन किया, जिसकी नियमित तरीके से जांच करने की आवश्यकता है. यही नहीं इसमें ईमानदारी और गंभीरता दिखाने की जरूरत है. ऐसे में मेरा आपसे अनुरोध है कि इसकी जांच करवाई जाए.

यह देश 26 जनवरी, 1950 से गणतंत्र है. संविधान ने आम आदमी को सभी संवैधानिक अधिकार दिए हैं. देश के सभी स्त्रोतों का संबंध आम आदमी से है. ये मंत्रियों की प्राइवेट संपत्ति नहीं है. दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि राणे जैसे मंत्री ये नहीं समझते और वह लवासा को किसी भी क़ीमत पर फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं. इसमें आपके गंभीर हस्तक्षेप की आवश्यकता है. मैं सोनिया और राहुल गांधी से इस मामले को देखने को कहूंगा और आदिवासी और पिछड़े हुए लोगों को न्याय दिलाने की मांग करूंगा. मैं देश के राष्ट्रपिता द्वारा दिखाए गए पथ पर चलने के लिए कटिबद्ध हूं. मैं इस बात को लेकर काफी निराश हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है. ऐसे में मैंने 5 नवंबर, 2010 से अपना विरोध करने का निश्चय किया है. अगर 11 नवंबर तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, तो मैं अपना पद्म विभूषण लौटा दूंगा जो कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा मुझे दिया गया था.

मैं 1 दिसंबर से महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के अलंदी में भूख हड़ताल शुरू कर दूंगा. ऐसे में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें. उचित कार्यवाही करें और लोकल आदिवासियों, ग़रीब किसानों को न्याय दिलाएं.

धन्यवाद
आपका के बी उर्फ अन्ना हज़ारे

ये क्या हो रहा है...

कब जागेंगे विदर्भ के नेता?

स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता ने सांसद राजू शेट्टी ने कमाल कर दिया. गन्ना उत्पादकों के लिए संघर्ष वहां से शुरू किया जहां कोई बारामती के महाराजा व राकांपा सुप्रीमो के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था. वह भी शक्कर लॉबी के विरुद्ध तो कोई वहां सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन इस बार सांसद राजू शेट्टी ने बारामती में आंदोलन का बिगुल फूंक कर शरद पवार के शक्कर साम्राज्य की चूलें हिला दीं. उन्होंने अनशन किया तो सारे राज्य के गन्ना उत्पादक उनके साथ खड़े नज़र आए. सरकार झुकी, शक्कर लॉबी को संरक्षण देने वाले झुके और शक्कर कारख़ाना संचालक भी बातचीत करने के लिए सामने आए. गन्ना उत्पादकों को न्याय मिला, लेकिन विदर्भ के कपास-धान उत्पादकों को न्याय मिलना अभी बाक़ी है, लेकिन राजू शेट्टी जैसा कोई नेता विदर्भ में नज़र नहीं आता है. बारामती वासिययों के अनुसार 45 साल बाद इतना व्यापक आंदोलन शरद पवार के गढ़ में देखने को मिला, लेकिन विदर्भ में सत्तापक्ष का हो या विपक्षी दल का कोई नेता ऐसा नहीं है जो राजू शेट्टी जैसा कमाल कर सके. क्या हमारे विदर्भ के जन प्रतिनिधि या नेता राजू शेट्टी के आंदोलन से कोई सीख या सबक़ लेंगे? विदर्भ के कपास व धान उत्पादक किसान भी ऐसा कोई विश्वसनीय नेतृत्व के सामने आने की बाट जोह रहा है, जो उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष छेड़े, लेकिन विदर्भ के नेताओं को सत्ता की चाशनी अधिक प्रिय लगती है. हालत यह है कि यहां के जितने भी विधायक-सांसद व अन्य नेता हैं, उन सबने सत्ता का उपभोग इतना किया है और कर रहे हैं कि उनमें कपास व धान उत्पादकों के हक़ के लिए राजू शेट्टी जैसा आंदोलन खड़ा करने का साहस नहीं है. इसकी वजह यह है कि विदर्भ के सत्तारूढ़ दल के नेता पहले दारू ठेके का लाइसेंस मांगते थे, अब वे स्कूल-कॉलेज का लाइसेंस लेकर अपना धंधा शुरू कर रखा है. जिसके कारण उनके स्वार्थ अलग हैं. वे अपने स्वार्थपूर्ति के लिए जनहित को किनारे रख देते हैं. इसी के चलते तो विदर्भ के भूमिपुत्र बदहाल हैं. आत्महत्या करने को मज़बूर हैं. उनके नाम पर करोड़ों का पैकेज घोषित तो किया जाता है पर वह किसानों तक नहीं पहुंचता हैं. आखिर विदर्भ के नेता नितिन गडकरी, बनवारीलाल पुरोहित, सांसद विलास मुत्तेमार, दत्ता मेघे, विजय दर्डा, प्रफुल्ल पटेल, मुकुल वासनिक, हंसराज अहिर, विधायक नितिन राऊत, देवेंन्द्र फडणवीस, अनिल देशमुख, संजय देवतले, सुधीर मुनगंटीवार, सुरेश देशमुख, डॉ. अनिल बोंडे, डॉ. राजेंद्र शिंगणे, सुखचैन संचेती, डॉ. हिरानी, नाना पटले सहित अन्य नेता बतायें कि उनके रहते आखिर हो क्या रहा है? क्यों भूमिपुत्रों को उनकी उपज का न्यायोचित दाम नहीं मिल रहा है? क्यों विदर्भ के किसान सतत आत्महत्या करने को मज़बूर हैं? राजू शेट्टी ने अब कपास, सोयाबीन, धान उत्पादकों के लिए संघर्ष करने की घोषणा बारामती जीतने के बाद की है, लेकिन विदर्भ का एक भी नेता पद व सत्तासुख का मोह छोड़कर क्यों नहीं भूमिपुत्रों के लिए संघर्ष करने को सड़कों पर उतरते हैं. विडंबना यह है कि यहां के नेता मात्र भाषणों में सरकार को चेतावनी देकर, ज्ञापन सौंपकर, कभी-कभार झुटपुट धरना-प्रदर्शन कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं. इसलिए सत्ता में बैठे लोग विदर्भ के नेताओं के बयानों को न ज्यादा तवज्जो देते हैं और न यहां के बदहाल किसानों की चिंता करते हैं. विदर्भ हर क्षेत्र में पिछड़ रहा तो उसे पिछड़ने देते हैं. यदि विदर्भ के जनप्रतिनिधि ज़रा भी संवेदनशील हैं तो उनको बारामती में हुए आंदोलन से सबक़ लेना चाहिए. राजू शेट्टी ने राह दिखा दी है. उस राह का अनुसरण करना बाक़ी है. क्या विदर्भ के नेताओं व जन प्रतिनिधियों में इतना साहस है वे सत्तासुख और पद का मोह छोड़कर, अपने स्वार्थ को भूलकर यहां के भूमिपुत्रों को न्याय दिलाने के लिए न केवल आंदोलन छेड़ें, बल्कि उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करें?

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

आर्णी में शिवाजी चौक पर अनशन करते किसान दादाराव केंचे व नृतक आशीष के परिजन.

पंढरपुर में घोड़ों के बाज़ार में घोड़े की ख़ूबियों को दर्शाता उसका मालिक और घोड़े के करतब का आनंद उठाते लोग.

व्यापार मेले में महाराष्ट्र की कलाकृतियों की धूम

राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे 31वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में महाराष्ट्र पवेलियन में में आदिवासी इलाक़ों से लाए गए पेड़ की जड़ों और तने को ख़ूबसूरत कलाकृतियों को मेले में आए दर्शकों ने ख़ूब सराहा. लकड़ी की सुंदर कलाकृतियों को देख विश्वास नहीं होता की इन्हें पेड़ की जड़ों और तने से बनाया गया है. जड़ों को कहीं आदमी की शक्ल तो कहीं जानवर की शक्ल दिया गया.

आदिवासी इलाक़ों में रहने वाले कारीगर जंगलों में जाकर पुराने या सूखे पेड़ों की जड़ों और किसी ख़ास आकृति केतने की तलाश करते है. जब उनमें कुछ ख़ास दिखता है तब उसे ये घर लाकर नक्काशी व पच्चीकारी विधि से सुंदर आकृतियों में ढाल देते है. फिर उसे अलग-अलग रंग दिया जाता है. यहां लकड़ी का सुपाड़ी बॉक्स भी ख़ास तरह का है. लकड़ी केबड़े हिस्से को काट छांट कर बनाया गया कछुए की शक्ल का बॉक्स काफी ख़ूबसूरत दिखता है. महाराष्ट्र पवेलियन में मौजूद जादुई लैंप को भी दर्शकों ने ख़ूब पसंद किया. चीनी मिट्टी का बना सेंट पॉट भी बेहतरीन अंदाज़ में बनाया गया है. इस पॉट केनिचले हिस्से में मोमबत्ती जला दीजिए और ऊपरी हिस्से में थोड़ा पानी डालकर सेंट की दो बूंदे डाल दीजिए. मोमबत्ती से पॉट के ऊपरी हिस्से में रखा पानी उबलेगा और सेंट की ख़ुशबू पूरे कमरे में बिखरती रहेगी. इसी मोमबत्ती पॉट की तरह पूरे ट्रेड फेयर में महाराष्ट्र की कलाकृतियां भी जलवाफ़रोश रही.

रीतिका सोनाली
ritika@chauthiduniya.com

लोणारा गांव के लोगों की यह लड़ाई शुरू हुई 31 दिसंबर 2004 से, जब वन विभाग के क़रीब 7-8 कर्मचारी ट्रक लेकर महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले की भिवापुर तहसील के लोणारा गांव के पास स्थित जंगल में पहुंचे.

ग्रामीणों की अनूठी पहल

सैकड़ों लोग बचा रहे करोड़ों की वनसंपदा

नागपुर ज़िले की भिवापुर तहसील का लोणारा गांव, जहां ग्रामीणों द्वारा हमारा गांव, हमारा राज आंदोलन चलाया जा रहा है.

लोणारा गांव स्थित ज़िला परिषद का प्राथमिक स्कूल.

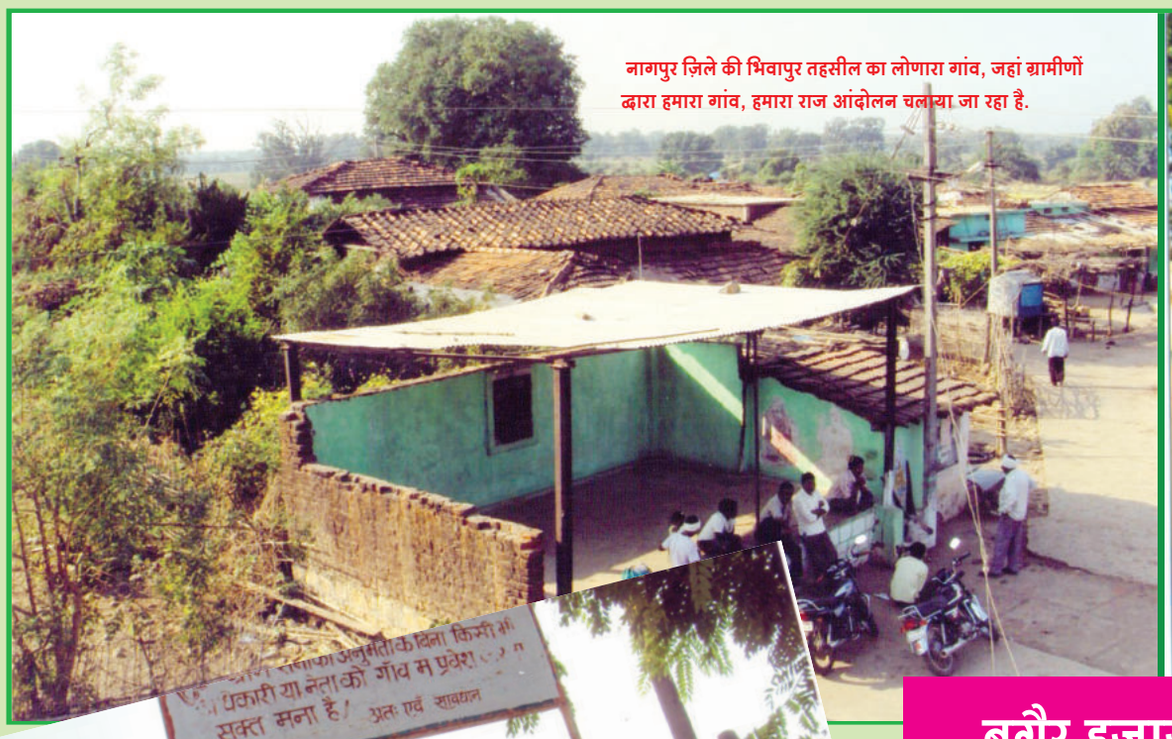

लोणारा गांव में ग्रामीणों की ओर से गांव में लगाया गया तख्ता, जिसमें ग्रामसभा की मंज़ूरी के बग़ैर किसी भी अधिकारी या नेता को गांव में नहीं आने की हिदायत दी गई है.

वषसवस

मयूर रंगारी

आज जब राज्य व देश में बेतहाशा जंगल की कटाई की जा रही है. वन संपदा की तस्करी कर करोड़ों कमाया जा रहा है. पर्यावरण को नुक़सान पहुंचाया जा रहा है. ऐसे में नागपुर ज़िले के लोणारा ग्रामवासियों का अपने आसपास के जंगल के प्रति लगाव देखते ही बनता है. वे जंगलों से न केवल प्यार करते हैं, बल्कि उसके संरक्षण के प्रति भी पूरी तरह सतर्क हैं. तभी तो वे कहते हैं–आम्ही आमच्या जंगलाला तोडू देणार नाही. (हम हमारे जंगल को तोड़ने नहीं देंगे) प्रशासन ने जबरदस्ती केली तर? (प्रशासन ने यदि जबरदस्ती की तो?) 150–200 पुलिस वाल्यांना येऊ द्या. गावातल्या आम्ही चारच बुड्ग्या बाया त्यांचावर पुरुन जाऊ. (आने दो 150–200 पुलिसवालों को. गांव की हम चार बुज़ुर्ग महिलाएं ही उन पर भारी पड़ेंगी.) अपने जीवन के लगभग 70 वर्ष पार चुकी सावित्राबाई ढोणे का जंगल के प्रति लगाव देखते ही बनता है. जंगल बचाने का मुद्दा मानों उनकी बुढी हड्डियों में फिर से जान भर देने का काम करता है. वे ही नहीं, बल्कि लगभग 500 जनसंख्या और क़रीब 80 घरों की बस्ती वाले लोणारा गांव की हर महिला और पुरुष अपने जंगल के प्रति भावुक है. गांववाले साफ़ कहते हैं कि जंगल उनकी संपत्ति है. उसका संरक्षण करने की ज़िम्मेदारी उनकी है. वे किसी भी अधिकारी या पुलिस को इसे हाथ नहीं लगाने देंगे.

लोणारा गांव के लोगों की यह लड़ाई शुरू हुई 31 दिसंबर 2004 से, जब वन विभाग के क़रीब 7–8 कर्मचारी ट्रक लेकर महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले की भिवापुर तहसील के लोणारा गांव के पास स्थित जंगल में पहुंचे. बिना किसी को जानकारी दिए उन्होंने सागौन पेड़ की कटाई शुरू कर दी. इसकी भनक लगते ही, गीताचार्य तुकाराम दादा के नेतृत्व में लोणारा गांव के लोग वहां पहुंचे. बिना जानकारी दिए पेड़ों को काटने से गुस्साए ग्रामीणों ने कटाई रोक दी और वन विभाग के कर्मचारियों को बंधक बना लिया. उन्हें गांव की स्कूल में रात भर रखा गया. इसकी जानकारी मिलने के बाद 1 जनवरी 2005 को पुलिस निरीक्षक अपने साथियों के साथ लोणारा गांव पहुंचे. गांववालों ने पुलिस निरीक्षक को पंचायत राज एक्ट का हवाला दिया. इस क़ानून के अनुसार गांव से लगे मालगुजारी जंगल पर ग्राम पंचायत का अधिकार होता है. बिना ग्राम पंचायत की इजाज़त के इसकी कटाई नहीं की जा सकती है. इसी के तहत लोणारा गांव के लोगों ने गांव से सटकर 540 हेक्टेयर की वनसंपदा पर अपना अधिकार बताया. उन्होंने कहा कि यदि जंगल से कोई ग्रामीण सूखी लकड़ी भी तोड़ता है, तो वन विभाग उस पर जुर्माना ठोंकता है. यह वन उनकी मालकी का है. इसलिए उन्होंने वन कर्मचारियों को पकड़कर ट्रक पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना दिए बग़ैर वे ट्रक को यहां से ले जाने नहीं देंगे. बताया जाता है कि वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा 120–130 घनमीटर लकड़ी तोड़ी गई थी, जिसका बाज़ार मूल्य 25 लाख रुपये से भी अधिक है.

12 ग्रामीणों को गिरफ़्तार किया

पुलिस निरीक्षक से चर्चा के बाद ग्रामीणों ने वन कर्मचारियों को छोड़ तो दिया, लेकिन जुर्माना दिए बिना ट्रक को छोड़ने से मना कर दिया. 6 जनवरी 2005 को वन अधिकारी अनिल मोहोड़ आए. उन्होंने कहा कि वे जुर्माना नहीं भर सकते. ग्रामीणों को वन विभाग का ट्रक छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी बात मानने से भी इंकार कर दिया. 8 जनवरी को परिसर के बेसुर क्षेत्र में यात्रा होने से गांव के अधिकतर लोग वहां गए थे. इसका लाभ उठाकर क़रीब 400 पुलिस कर्मचारियों, जिनमें 100 बंदूकधारी, 8 पुलिस निरीक्षक, 2 पुलिस उप विभागीय अधिकारियों का समावेश था. उन्होंने गांव को घेर लिया. वे गांव के क़रीब 12 लोगों को गिरफ़्तार कर ले गए. इनमें देवमन धारणे, जामाजी धारणे, गणपत धारणे, वामन धारणे, तुकाराम ढोणे, श्यामू गजभे, राजू गजभे, प्रवीण डडमल आदि का समावेश था. बाद में उन्हें जमानत लेने के लिए कहा गया, लेकिन ज़मानत लेने से ग्रामीणों ने साफ इंकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें 9 जनवरी को नागपुर के जेल में रवाना कर दिया गया. इस मामले में 16 जनवरी को हुई पहली सुनवाई में पूरा गांव मौजूद था. ग्रामीणों ने साफ़ तौर पर कहा कि पहले उन्हें बताया जाए कि उन्हें किस आरोप के तहत गिरफ़्तार किया गया है? तभी वे ज़मानत लेंगे. 27 जनवरी को पुनः सुनवाई हुई. बाद में उन्हें 28 जनवरी को व्यक्तिगत बांड पर ज़मानत दी गई. ग्रामीणों ने कहा कि वे सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन पुलिस फिर 40 ग्रामीणों को अपने साथ ले गई, लेकिन इस घटना का इतना विरोध हुआ कि वरिष्ठ अधिकारियों को ग्रामीणों को तुरंत छोड़ने का आदेश देना पड़ा. तत्कालीन एसपी भूषण कुमार उपाध्याय ने ग्रामीणों को लोणारा गांव छोड़ने के आदेश दिए.

जब ग्रामवासियों से इस घटना के संबंध में बातचीत की गई तो क़रीब 21 दिन तक पुलिस हिरासत में रहे देवमन धारणे कई मुद्दों पर अपना रुख़ स्पष्ट किया. उनका साफ तौर पर कहना है कि जब मालगुज़ारी के तहत 540 हेक्टेयर जंगल पर गांव वालों का अधिकार है, तो वन विभाग यहां के पेड़ कैसे तोड़ सकता है. गांव वाले मर जाएंगे, लेकिन करोड़ों की वन संपदा को बर्बाद नहीं होने देंगे. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका भी दाख़िल की है. एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है. प्रशासन के व्यवहार से दुखी धारणे ने कहा कि अधिकारियों ने कई बार गांव वालों को अंधेरे में रखकर काम किया. उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में प्रशासन ने तोड़ी हुई सागौन लकड़ी की नीलामी का विज्ञापन अख़बारों में दिया. गांव वालों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई. विज्ञापन पढ़ने के बाद कुछ ठेकेदार गांव में आए और लकड़ी ले जाने के संबंध में गांव वालों से चर्चा की. ग्रामीणों ने साफ़ तौर पर ठेकेदारों से कहा कि यदि उनके पास ज्यादा पैसे हैं, तो वे प्रशासन की इस नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वे किसी भी क़ीमत पर लकड़ी ले जाने नहीं देंगे. ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन को यह नीलामी रद्द करनी पड़ी. देवमन धारणे ने बताया कि वर्ष 1985 में गांव से कुछ दूर धामण गांव में स्थित बड़ा तालाब फूट गया था. गांव वालों ने वन विभाग से कहा कि उस तालाब की मरम्मत के लिए वे वहां के पेड़ तोड़ सकते हैं, लेकिन वन विभाग इसे नहीं माना. वह सागौन के ही पेड़ों को तोड़ना चाहता है. ग्रामीणों का कहना है कि पुलिसवालों ने कई बार उन्हें धमकियां दी हैं. गांव को नक्सली घोषित करने का झूठा प्रचार भी किया गया. गयाबाई ढोणे, सुंदरबाई बावणे, मीरा ढोणे, रूपाली बावणे, संगीता सेरकी आदि महिलाओं का कहना है कि उन्हें जो अधिकार क़ानून ने दिया है, उसे वे नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने कहा कि पहले सरकार उनके गांव का विकास करे, फिर लकड़ी ले जाने पर चर्चा की जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

बगैर इजाज़त गांव में प्रवेश निषेध

प्रशासन की ओर से हो रही मनमानी को रोकने के लिए ग्रामीणों ने एक प्रस्ताव पारित किया है. इसके तहत किसी भी अधिकारी या नेता को गांव में प्रवेश करने के पूर्व ग्रामसभा की मंज़ूरी लेना आवश्यक होगा. इस प्रस्ताव का बाक़ायदा एक बोर्ड गांव की सीमा की शुरुआत में ही लगाया गया है. प्राथमिक स्कूल के कंपाउंड से सटकर लगाए गए इस बोर्ड में ग्रामसभा की मंज़ूरी नहीं लेने वाले अधिकारियों और नेताओं को गांव में प्रवेश करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

अन्ना हज़ारे ने किया दौरा

गांव के विनायक ढोणे और प्रकाश सावसाकले ने बताया कि गांव में 23 मार्च 2005 को गांव में संग्राम आंदोलन किया गया था. इस दौरान ग्रामीणों ने किसी भी हालत में तोड़ा हुआ सागौन नहीं ले जाने देने और जंगल में एक भी पेड़ को तोड़ने नहीं देने का संकल्प लिया. उन्होंने बताया कि तत्कालीन ज़िलाधिकारी ने गांववालों से कहा था कि वे एक दिन में लकड़ी लेकर जाएंगे. कुछ लोग लकड़ी लेने आए भी, लेकिन गांव वालों ने उन्हें लौटा दिया. उन्होंने बताया कि गांव वालों के संघर्ष की जानकारी मिलने पर 2 बार अन्ना हज़ारे और सत्यपाल महाराज ने गांव का दौरा किया था. अन्ना हज़ारे ने गांव वालों से कहा कि वे ग्रामीणों के हर संघर्ष में उनके साथ हैं. आज लोणारा गांव के लोगों की इस हिम्मत की सभी लोग सराहना करते हैं. आसपास के गांव वालों की मानें, तो ये उनके लिए उदाहरण है कि अपने अधिकारों को किस तरह पाया जाता है. लोणारा गांव आज देश के बाक़ी गांव वालों के लिए एक उदाहरण बन गया है.

लोणारा गांव की महिलाएं.

लोणारा गांव वासियों द्वारा वनविभाग के कर्मचारियों से जब्त किया गया लाखों रुपये का सागौन.

Postal Regn. No.RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 28 नवंबर-04 दिसंबर 2011

रोडीज और बिग बॉस के विजेता रह चुके आशुतोष कौशिक की क़रीबी दोस्त रह चुकी सोनेल आम जीवन में जैसी तेज़ तर्रार हैं वैसा ही चरित्र अभिनीत किया है उन्होंने फिल्म जीत लेंगे जहां में.

लड़की या बुलेट

बॉलीवुड की फिल्मों में पिछले कुछ समय से ट्रेंड चल गया है विदेशी फिल्म इंडस्ट्री की हिरोइंस को लेकर फिल्म बनाने का, लेकिन बॉलीवुड न केवल विदेशी हिरोइंस को प्रोमोट करता रहा है, बल्कि देश की दूसरी भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री से भी हिरोइंस को मौक़ा देता रहा है. उदाहरण के तौर पर अजय देवगन की फिल्म सिंघम की काजल अग्रवाल को देख सकते हैं. इसी तरह इस बार पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक नामी चेहरे को भी जल्द ही हिंदी फिल्म में अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाते देखेंगे. रोडीज फेम सोनेल सिंह ने यूं तो कई पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन अब वह हिंदी फिल्मों में भी काम कर रही हैं. रोडीज और बिग बॉस के विजेता रह चुके आशुतोष कौशिक की क़रीबी दोस्त रह चुकी सोनेल आम जीवन में जैसी तेज़ तर्रार हैं वैसा ही चरित्र अभिनीत किया है उन्होंने फिल्म जीत लेंगे जहां में. इस फिल्म में उनका नाम भी बुलेट है. फिल्म के निर्देशक ललित कहते हैं कि सोनेल जैसी रियल लाइफ में हैं वैसी ही फिल्म में भी उनका चरित्र है. इसीलिए उनका नाम फिल्म में बुलेट रखा गया है. अशोका मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी एक रोमांटिक फिल्म है जीत लेंगे जहां, जिसके निर्माता हैं संजू सिंह. फिल्म की पटकथा लेखन का ज़िम्मा निभाया है ख़ुद फिल्म के निर्देशक ललित एम बिष्ट ने. फिल्म में अभिनय करने वाले कलाकारों में मुख्य हैं अशोक शुक्ला, नीलाम्बरी पेरूमल, गोल्डी सुमेल, पारस सिंह मिन्हास, एना, सोनेल सिंह आदि.

घायल रिटर्न्स का निर्देशन

सनी देओल अपनी होम प्रोडक्शन विजयता फिल्म से घायल रिटर्न्स बना रहे हैं. 1990 में हिट हुई घायल का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया था. अब घायल रिटर्न्स यह हिट फिल्म घायल का ही सीक्वल है. अश्विनी चौधरी इस फिल्म का निर्देशन करने वाली थीं, तथा उन्होंने फिल्म का एक प्रोमो भी रिलीज किया था. पर अब वह यह फिल्म नहीं करेंगी. सनी देओल ने यह प्रोजेक्ट अपने दोस्त राहुल रवैल को दे दिया है. अब सनी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, यह तो ख़ुद वह ही जानते होंगे, मगर सूत्रों का कहना है कि अश्विनी अपनी कई फिल्मों को लेकर व्यस्त हैं, जिसकी वजह से वह घायल रिटर्न्स के लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं. इसलिए सनी ने यह फिल्म राहुल रवैल को सौंप दी. घायल रिटर्न्स द्वारा राहुल विजयता फिल्मस की फिल्म का निर्देशन 28 साल बाद करने वाले हैं. इससे पहले उन्होंने इस बैनर की 1983 में आई बेताब फिल्म का निर्देशन किया था. ग़ौर करने वाली बात यह है कि सनी देओल ही इस फिल्म में मुख्य किरदार में होंगे.

करिश्मा का करिश्मा

कुछ समय पहले तक करिश्मा ख़ुश दिखाई नहीं दे रही थीं लेकिन अब उनके चेहरे पर खिली मुस्कान साफ देखी जा सकती है. हाल ही में करिश्मा ने पति के परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाए हैं और कुछ तस्वीरें उन्होंने बहन करीना कपूर को भी भेजी हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर एक बार फिर अपनी टूटती शादी को बचाने की जुगत में जुटी हैं. उन्होंने इस बार दीपावली पति संजय कपूर और बच्चों के साथ दिल्ली में मनाई. वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आने के बाद वह पति से तलाक़ लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन लगता है अब उनका इरादा बदल गया है. सूत्रों ने बताया कि करिश्मा दिल्ली में पति और बच्चों के साथ क़रीब एक हफ्ते तक रहीं. उन्हें लंबे समय बाद इतना ख़ुश देखा गया. उन्होंने अपने पति और बच्चों के साथ फोटो खिंचवाकर अपनी बहन करीना को भी भेजे. करीना इन दिनों लंदन में हैं.

उल्लेखनीय है कि अभिषेक बच्चन से अलगाव के बाद करिश्मा ने संजय से 2003 में शादी की थी. संजय ने भी अभिनेत्री से शादी से कुछ दिन पहले ही अपनी पहली फैशन डिज़ाइनर पत्नी नंदिता मेहतानी से तलाक़ लिया था. 2005 में पहली बेटी के जन्म के समय से ही कहा जा रहा था कि दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ रही है. इसका कारण न्यूयॉर्क के नामी व्यवसायी की पूर्व पत्नी के साथ संजय की नज़दीकियां बताई गई थीं. पिछले साल मार्च में एक बेटा होने के बाद पति से अनबन के चलते करिश्मा ने मुंबई का रुख़ कर लिया और बच्चों के साथ बांद्रा में रहने लगीं. अब उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी दूसरी पारी शुरू कर दी है. वह निर्देशक विक्रम भट्ट की फिल्म डेंजरस इश्क से वापसी कर रही हैं. इसके अलावा वह सत्ते पे सत्ता की रीमेक में भी मुख्य भूमिका में हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

उभरते गायक विपिन

मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाये गीत गुलाबी आंखें के रीमिक्स गीत को गाकर श्रोताओं के बीच लोकप्रिय हुए गायक विपिन अनेजा ने पिछले दिनों रिलीज़ हुई निर्देशक तिग्मांशु धूलिया की हिंदी फ़िल्म साहब बीबी और गैंगस्टर में थीम सॉन्ग गाया है. यह गीत शुरू से आख़िर तक फ़िल्म की हर सिचुएशन में है. दरअसल फ़िल्म में जब लीड एक्टर जिमी शेरगिल की एंट्री होती है तब यह शुरू होता है और आख़िर तक चलता है. इस फ़िल्म के अलावा विपिन कई अन्य फिल्मों में भी गीत गा रहे हैं जैसे ईस्क, नई सुबह. फ़िल्म ईस्क में उन्होंने संगीतकार रवि पवार के संगीत निर्देशन में उत्तर प्रदेश के लोक संगीत पर आधारित गीतों को गाया है. इसके अलावा फ़िल्म नई सुबह में भी राजेश रॉय के संगीत निर्देशन में भी उन्होंने एक गीत गाया है. राजेश रॉय संगीतकार जतिन ललित के असिस्टेंट रह चुके हैं. फिल्मों में तो विपिन गीतों को गा ही रहे हैं, इसके अलावा उनके कई एलबम भी रिलीज़ हो चुके हैं, जिनमें से एक है तेरी पायल और दूसरी है सैल्यूट टू बॉलीवुड. दोनों ही एलबम में उनकी क्षमता को ख़ूब पहचान मिली. एलबम सेल्यूट टू बॉलीवुड के गीत ज़मीं गा रही है, को सबसे ज़्यादा नार्वे में डाउनलोड किया गया और इसी एलबम के गीत गुलाबी आंखें रीमिक्स गीत चैनल वी पर सबसे अधिक लोकप्रिय रहा. देश-विदेश में अनेक शो कर चुके विपिन ने कलर्स पर प्रसारित होने वाले संगीत के कार्यक्रम आइडिया रॉक्स इंडिया में हिस्सा लिया और यहां भी उनके सूफ़ी गीतों को श्रोताओं ने ख़ूब पसंद किया. कजाकिस्तान में विश्व पॉप गायिकी की प्रतियोगिता में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर चुके विपिन को न सिर्फ़ अपने देश के लिए पुरस्कार मिला, बल्कि साथ में एआर रहमान जैसे महान संगीतकार के साथ यूनिटी ऑफ़ लाइट पीस कंसर्ट में काम करने का अवसर भी मिला. अनेक जिंगल्स गा चुके विपिन का बचपन से ही संगीत की ओर रुझान था. दस वर्ष की आयु में उन्होंने दिल्ली की राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता में भाग लिया और पुरस्कार भी जीता. संगीत में ही अपने करियर को बनाने की चाहत रखने वाले विपिन ने न्यूयॉर्क स्टेट अकादमी से एमबीए में पोस्ट ग्रेजुएट किया. विपिन ने स्टेज पर तो ए आर रहमान के साथ काम किया है, लेकिन उनके संगीत निर्देशन में भी काम करने की चाहत है उनकी.

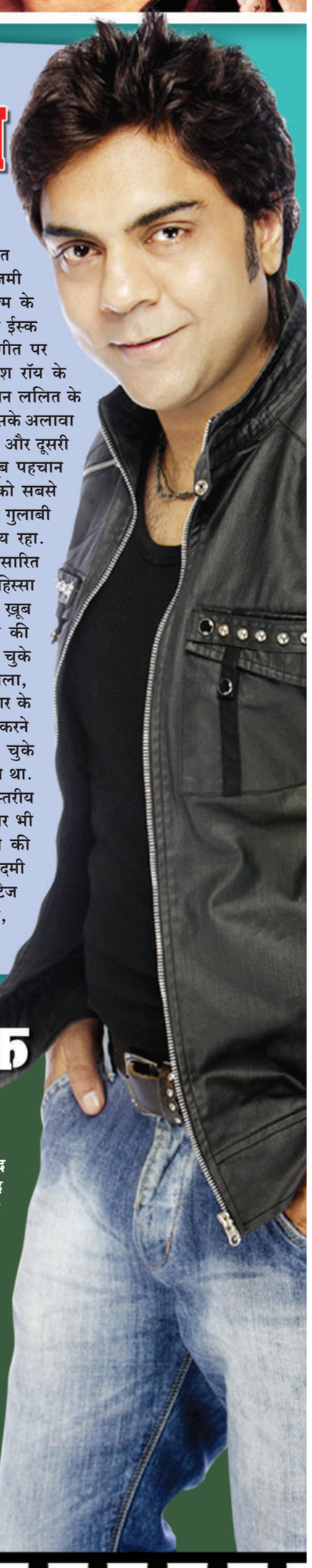

फिल्म बना रहे हैं विवेक

मेनस्ट्रीम सिनेमा में सफलता की ऊंचाइयों तक न पहुंच पाने वाले एक्टर्स बॉलीवुड में ही रहकर कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे वे सफलता के क़रीब पहुंच सकें. फीमेल एक्टर्स आइटम सॉन्ग, बॉडी शो या लीक से हटकर फिल्म में रोल प्ले करके ख़ुद को स्थापित करना चाहती हैं तो मेल एक्टर्स भी अलग तरह के रोल अदा करके ख़ुद को इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच प्रूव करने की कोशिश करते हैं. सफलता के क़रीब पहुंचने की कोशिश करने वाले अभिनेता विवेक ओबरॉय ने भी ख़ुद को रीइस्टैबलिश करने के लिए कुछ हटकर करने की कोशिश की है. दरअसल वह एक ख़ास तरह की फिल्म निर्माण की तैयारी में हैं. विवेक ओबरॉय का कहना है कि वह वास्तविक भारत को दिखाने के लिए सिनेमा बना रहे हैं. उन्होंने कहा, मैं अपनी सफलता का इस्तेमाल उन चीज़ों में कर रहा हूं, जो बॉलीवुड नहीं करता है. उन्होंने कहा, मेरी फिल्म की कहानी वैसी नहीं है, जैसी कि लोग अब तक देखते आए हैं. यह चीज़ों को अलग नज़रिये से देखने से जुड़ा हुआ है न कि धन कमाने से. बतौर निर्माता वॉच इंडियन सर्कस विवेक की पहली फिल्म है. फिल्म को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने फिल्म का प्रीमियर एक फिल्म समारोह में ही शेड्यूल कर दिया. इस समारोह के मुख्य पुरस्कार न्यू करेंट्स की दौड़ में शामिल हैं. विवेक की इस फिल्म का निर्देशन मंगेश हादावले ने किया है और इसमें ग़रीबी में जीवन गुज़ार रहे एक दंपत्ति की कहानी है. इस दंपत्ति का सपना है, अपने बच्चों के साथ सर्कस देखना. विवेक ने कहा, मेरा मानना है कि यह फिल्म भारत की आत्मा का प्रतीक है.

फिल्म प्रीव्यू

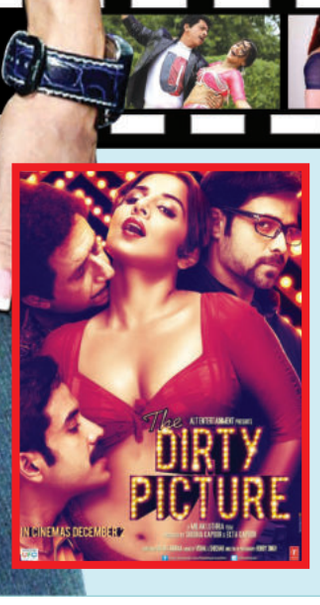

डर्टी पिक्चर्स

बालाजी मोशन पिक्चर्स और एएलटी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी फिल्म डर्टी पिक्चर्स दक्षिण की सुपर स्टार विजयालक्ष्मी उर्फ़ सिल्क स्मिता की कहानी है. फिल्म की निर्माता हैं एकता कपूर और शोभा कपूर. फिल्म के निर्देशक हैं मिलन लुथारिया और संगीत दिया है विशाल-शेखर ने. मुख्य कलाकार के तौर पर फिल्म में नज़र आएंगे विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी और तुषार कपूर. सुपर स्टार विजयालक्ष्मी उर्फ़ सिल्क स्मिता ने एक मेकअप गर्ल की हैसियत से फिल्मी दुनिया में क़दम रखा था, लेकिन जल्दी ही वह बी-ग्रेड फिल्मों की टॉप हीरोइन बन गईं. पोस्टर पर सिल्क स्मिता का नाम देखकर लोग टिकट ख़रीद लेते थे. उत्तेजक आइटम नंबर और बोल्ड दृश्यों की वजह से उन्हें सॉफ्ट पोर्न एक्ट्रेस भी कहा जाने लगा. अचानक मिली सफलता को सिल्क ठीक से संभाल नहीं पाईं. आर्थिक संकट और प्यार में मिले धोखे के बाद वह शराब में डूब गईं. रहस्यमयी परिस्थितियों में मात्र 36 वर्ष की उम्र में वह अपने चेन्नई स्थित अपार्टमेंट में मृत पाई गईं. सिल्क की इसी कहानी से प्रेरित होकर द डर्टी पिक्चर बनाई गई है. सिल्क के शुरुआती संघर्ष से लेकर तो 80 के दशक का वह दौर दिखाया गया है जब बॉक्स ऑफिस पर सिल्क के नाम का डंका बजता था. सिल्क के जीवन के उतार-चढ़ाव और शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी को कलरफुल और मनोरंजक तरीक़े से दिखाया गया है. निर्देशक मिलन लुथारिया ने जहां एक ओर कच्चे धागे (1999), दीवार (2004), टैक्सी नं. 9211 (2006) और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई (2010) जैसी फिल्में बनाई हैं तो दूसरी ओर चोरी-चोरी (2003) और हैट्रिक (2007) जैसी कमज़ोर फिल्में भी उनके खाते में हैं. मिलन एक अच्छे निर्देशक हैं, इसके बावजूद उनका नाम बॉलीवुड केटॉप निर्देशकों में नहीं लिया जाता है. उनकी पिछली फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई. 1970 और 80 के दशक को उन्होंने उम्दा तरीक़े से स्क्रीन पर पेश किया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 28 नवंबर-04 दिसंबर 2011

www.chauthiduniya.com

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI STATION
BIT Pithoria, Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

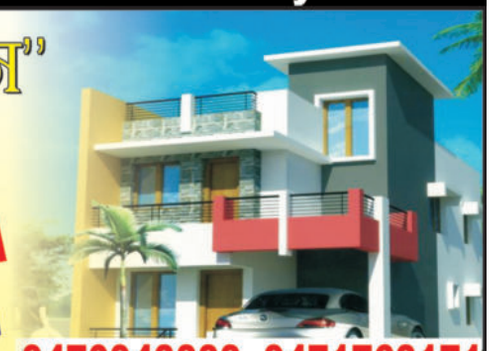

9386045623/9470981772

9470943888, 9471763171

सुशासन भी अनुपम को बचा नहीं सका

वह जगह, जहां शव को जलाया गया.

अनुपम की चूड़ियां और साड़ी दिखाते हुए मुकेश के माता-पिता.

मुकेश कुमार

वीरेंद्र कुमार (अनुपम के पिता)

हत्यारों की नज़र में उसका प्यार गुनाह और वो ख़ुद गुनहगार थी. अनुपम का प्यार और प्रेम विवाह इनके अहम और झूठी शान के लिए चुनौती था. सो अपनी झूठी शान को बचाने के नाम पर इन लोगों ने अनुपम की जान ले ली. और सुशासन के प्रहरी मूकदर्शक बने रहे.

सरोज सिंह

अनुपम ने मुकेश से प्यार की जिद नहीं छोड़ी और पंचायत ने फ़ैसला कर अनुपम को टुकड़े-टुकड़े कर मार डाला. अनुपम की हत्या एक ऐसी कहानी है, जिसने बिहार के सामाजिक तानेबाने में औरतों की हैसियत को उजागर कर दिया. पटना की चमक दमक से दूर मुरलीगंज की अनुपम का कसूर बस इतना ही था कि उसने अपने दिल की बात सुनी और मुकेश से प्यार कर बैठी. इसका अंजाम यह हुआ कि मधेपुरा ज़िला के मुरलीगंज थानान्तर्गत सिंगीऔन गांव में मरघट की वीरानगी छाई हुई है. ऑनर किलिंग का दाग इस गांव पर चस्पा हो चुका है. कोई भी ग्रामीण वहां हुए ऑनर किलिंग के संबंध में मुंह खोलने को तैयार नहीं है. दोनों पक्ष के लोग अपने घरों से सुरक्षा की ख़ातिर भागे हुए हैं. घटना के कई दिनों बाद भी गांव ने खामोशी ओढ़ रखी है. गांव के लोग किसी अजनबी को महज कौतूहल वश देख लेते हैं. लेकिन घटना के संबंध में बेजुवान बने हुए हैं.

दरअसल, भतीजे से प्रेम विवाह करना अनुपम को काफी महंगा पड़ा. इसी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई. गांव के लोगों ने अपनी संस्कृति बचाने के लिए कलेजे पर पत्थर रख कर कड़ा निर्णय लिया और रात में अंधकार के साए में ग्रामीण हमलावर हो उठे. पड़ोस में स्थित अनुपम के ससुराल में जाकर उत्पात मचाया. अनुपम को मारते पीटते हुए बगल में भूमि यादव के बगीचे पर ले गये और अपने पति को छोड़ कर भतीजे से शादी रचाने के लिए बतौर सजा उसके अंगों को काट डाला गया. अनुपम तड़पती रही और चीखती रही. लेकिन किसी को तरस नहीं आया. इसके बाद उसके छटपटाते जिस्म पर किरोसिन तेल डाल कर उसे जला दिया गया. 8 और 9 नवम्बर की रात में हुई इस घटना का एक मात्र चश्मदीद गवाह मृतका अनुपम का कथित पति मुकेश कुमार ही है. उसने मुरलीगंज थाने में अनुपम के पिता वीरेंद्र प्रसाद यादव, दादा बालेश्वर प्रसाद यादव, चाचा गजेंद्र प्रसाद यादव, सुजेंद्र प्रसाद यादव तथा गांव के मुखिया अशोक कुमार यादव सहित 15 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है. कहते हैं कि इस घटना से पहले लोगों ने पंचायत लगाकर सजा तय की, फिर घटना को अंजाम दिया. मुकेश रिश्ते के सवाल पर चुप हो जाता है, लेकिन रोते हुए कहता है कि तीन वर्ष से अनुपम के लिए उसका प्रेम परवान चढ़ा और अनुपम उसके साथ भाग कर शादी करना चाहती थी. लेकिन उसकी मनाही पर बात टल गयी. मुकेश कहता है दोनों के प्रेम से तंग आकर अनुपम के घर वालों ने उसकी शादी रमनी गांव के पन्ना यादव से कर दी. लेकिन शादी के समय ही अनुपम ने अपना विरोध जता दिया और अपने पति से झगड़ा कर ससुराल से घर चली आई. फिर उसने जान दे देने की बात कहते हुए मुकेश के साथ घर बसाने की इच्छा जताई थी. फिर मुकेश ने भाग कर पहले सिंहेश्वर मंदिर में अनुपम से शादी की और दोनों हरियाणा के गुड़गांव चले गए. वहां से अपने गांव लौटते ही अनुपम की हत्या कर दी गयी. मुकेश का कहना है कि अनुपम के रिश्तेदार उसकी भी हत्या करना चाहते थे. लेकिन मौके पर छिप जाने से वह बच गया. अनुपम के पिता बीरेंद्र यादव मुकेश की बातों को तवज्जो देने के बजाए कहते हैं कि उसकी बेटी की हत्या मुकेश और उसके परिवार वालों ने की है और स्वयं बचने के लिए पुलिस को मेल में लेकर उन लोगों को फंसाया गया है. इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है अन्यथा उसकी बेटी के अपहरण की जानकारी दिए जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की. हत्या की सूचना थाने में दिए जाने के बाद भी पुलिस खामोश रही और उल्टे उन लोगों को ही फंसा दिया गया है. लेकिन 9 नबम्बर को मधेपुरा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मुकेश सहित पांच लोगों के ख़िलाफ़ अनुपम की हत्या का मामला दर्ज करा दिया गया है. जिसे प्राथमिकी के लिए मुरलीगंज थाना भेजा गया है.

पुलिस अधीक्षक गोपाल प्रसाद इस हत्या को ऑनर किलिंग के करीब देख रहे हैं. लेकिन अनुपम के पिता के आवेदन को देखने के बाद ही निर्णय लेने की बात कहते हैं. स्थानीय पुलिस अपनी वर्दी पर धब्बा लगने नहीं देना चाहती है. थानाध्यक्ष रंजीत वत्स कहते हैं कि इस मामले को वह गंभीरता से देख रहे हैं, ताकि किसी को कोई शिकायत नहीं हो. इस बीच राज्य महिला आयोग की टीम मंजू कुमारी उर्फ गुड्डी देवी के नेतृत्व में गांव आकर लौट गयी है. आयोग ने इस कांड को गंभीरता से लिया है. लेकिन इस मौत ने समाज पर कई सवाल छोड़ दिए हैं. जिसे सभ्य समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हैं. फ़िलहाल, गांव की खामोशी अनुपम की मौत की पूरी सच्चाई खुद ब खुद बयां कर रही है.

साथ में देवाशीष बोस

feedback@chauthiduniya.com

सभ्य समाज के चेहरे पर कालिख

अनुपम की चिता की राख भले ही ठंडी हो गई हो लेकिन इस दागदार घटना से मधेपुरा के मुंह पर कालिख पुत गई है. अलबत्ता मधेपुरा की महिलाएं बिफर रहीं हैं और पुलिस की दबिश को नाकाफी मान रहीं है. भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर डॉ. प्रज्ञा प्रसाद का कहना है कि मानव जाति में महिला बन कर पैदा लेना आज भी अभिशाप है. यह घटना पुरुष समाज की कायरता को दर्शाती है. पिता और पति के रहते अनुपम को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह स्त्री थी. अनुपम को मारने वाले हैवान हैं तथा धरती पर हैवानों का रहना अनुचित है. पार्वती विज्ञान महाविद्यालय, मधेपुरा में संगीत की ब्याख्याता रीता कुमारी गुस्से में कहती है कि प्रेम विवाह रचाना कोई गुनाह नहीं है. लेकिन किसी अबला स्त्री को जला देना बर्बर और कायरता है. सरकार के नारी सशक्तिकरण को प्रशासन ठेंगा दिखा रहा है. समाज को आत्म आलोचना करना होगा. अन्यथा इससे भी घिनौना तस्वीर देखनी पड़ेगी. टीपी कॉलेज, मधेपुरा में हिन्दी विभाग की प्रोफेसर डॉ. वीणा कुमारी ने इस घटना की निन्दा की और कहा कि प्रेम विवाह ग़लत नहीं हैं, लेकिन विकृतियों को कदापि पसन्द नहीं किया जा सकता है. समाज और अभिभावकों को अपनी नज़रिया बदलना होगा और प्रशासन को अधिक मुश्तैद होना होगा. अन्यथा आत्म निर्णय का परिणाम घातक होगा. जिसका ख़ामियाजा हम सबको भोगना पड़ेगा. भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में गृह विज्ञान की विभागाध्यक्ष डा. सैयदा रानी बताती हैं कि लोमहर्षक इस घटना के पीछे उन्मादी सोच, अशिक्षा तथा कुरीतियां मुख्य कारण हैं. समाज में बेहतर संदेश के लिए प्रशासन को कारगर कदम उठाने चाहिए तथा दोषी लोगों को सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए. पीएस कॉलेज में मनोविज्ञान की प्रोफेसर डॉ. मीना कुमारी कहती हैं कि युग युगान्तर से स्त्री के प्रति समाज की जो सोच बनी हुई है. यह बर्बर घटना इसी का आईना है. शिक्षा और संस्कार की कमी इस तरह की घटनाओं का मुख्य कारण है. दोषियों को मौत की सजा समाज के लिए नसीहत होगी. जिला अधिवक्ता संघ के प्रधान सचिव जवाहर झा इस घटना को सामाजिक विकृति मानते हैं. उनका कहना है कि सदियों से पुरुष आकांक्षा के तले दबी औरतों की अस्मिता का यही हश्र है. लेकिन अब स्त्री चाहरदीवारी के अन्दर सिसकने के बजाय चीत्कार रही है. जबकि बिरोध के स्वर दूर तक गूंजने चाहिए अन्यथा ये घटनाएं हमेशा दोहराई जाती रहेंगी. जिला लोक अभियोजक मृत्युंजय प्रसाद सिंह कहते हैं कि स्त्री की हत्या करना समाज के साथ अपराध है. जबकि अपराधियों के लिए कानून के हाथ लम्बे हैं. इसमें कोई दोषी नहीं छूटेगा और कोई निर्दोष नहीं फंसेगा. पुलिस की कार्रवाई जारी है. अपराधी अपराध को अंजाम देकर भूमिगत हो गए हैं. लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ़ लेगी. प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. दिलीप कुमार सिंह इस घटना को बर्बर समाज का डरावना चेहरा बताते हुए कहते हैं कि दोषियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सख्त होनी चाहिए. ताकि समाज में एक बेहतर संदेश जाए. और ऐसी घटना फिर बिहार और समाज के चेहरे पर कालिख न पोत सके. राजद के ज्योति मंडल तो इस घटना के लिए सीधे प्रशासन को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं. इनका कहना है कि अक्सर प्रेम विवाह रचाने वाले प्रेमी युगल को पुलिस अपहरण के मामला में फंसा कर परेशान करती है. ऐसी स्थिति में इन्हें कानून का सहारा चाहिए. पुलिस अपने आसूचना के द्वारा अगर पहले ही सजग रहती तो यह घटना घटित नहीं होती. लेकिन दोषियों को फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए.

देवाशीष बोस

feedback@chauthiduniya.com